खण्ड–489, अंक–6
शुक्रवार, 05 आषाढ़, शक संवत् 1936
(26 जून, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-37
चीनी मिल एसोसियेशन द्वारा मुख्य मंत्री व मुख्य सचिव को दिये पत्र में जबरदस्ती किसानों के गन्ने का भुगतान कराने पर अगले सत्र में पेराई नहीं होने देने के सम्बन्ध में दी गई धमकी पर व्यवस्था का प्रश्न	38-39
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	39-40
जनपद शाहजहांपुर में सीवर लाइन तथा एस0टी0पी0 सहित सीवर लाइन का प्रथम चरण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40-41
मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम पावर ऑफ अर्टानी के माध्यम से कब्जा धारकों को सीधे रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41
कानपुर महानगर स्थित छावनी क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण महामारी फैलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41-42
विधान सभा क्षेत्र नूरपुर जनपद बिजनौर की ग्राम सभा किवाड़ की चीलों की मंडेया से कांठ मार्ग पर रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली में बल्दीराय ब्लाक को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	42-43
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज की नदियों में पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
जनपद चन्दौली में नरवन क्षेत्र के नरायनपुर पम्प कैनाल को चक्का बांध लिफ्ट जमनियां से सिंचाई हेतु पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद की नदियों के किनारों पर ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	44
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	44-45

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा के सरकारी चकरोड व तालाब पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के कैमुआ नाले का चौड़ीकरण एवं नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	45
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में व्याप्त विद्युत संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 के अन्तर्गत निर्माण इकाई के उप परियोजना प्रबन्धक के द्वारा किये गये गम्भीर घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद उन्नाव के कतिपय ब्लाकों में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	46-47
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड माण्डा अन्तर्गत ग्राम सभा मझिगवां का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	47
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 131वां (एक सौ इकत्तीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	48
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	48
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	48
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	48
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	48
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	49
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	49

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत पुरदिल नगर मुख्य सड़क से ग्राम शंकरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बृज बिहारी कौशिक आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	49
जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत जरेरा चौराहे से ग्राम नगला वीर सहाय तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नवीन पाराशर आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	49
जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम पिछोती से ग्राम धुबई होते हुए सिकन्दराराऊ-हसायन मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री आरिफ अली बेग आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	50
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर राजमार्ग पर निगोही के पास कैमुआ नाले पर पुराना जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पुल का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री जितेन्द्र गुप्ता आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ..	50
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम जहांनपुर से ग्राम नेकापुर तक की क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सड़क का जनहित में निर्माण एवं डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री उमेश यादव आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	50
जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा विद्यापुर-बखरवा में मोदीनगर विद्यापुर मार्ग पर स्थित गन्दे नाले के टूटे हुये पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगपाल आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	50
जनपद गाजियाबाद में विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा त्योड़ी-13 विस्वा में इदरीश के मकान से ग्राम तलहटा तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शहजादा प्रधान आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	51
जनपद मथुरा के राया बाईपास का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निर्माण कराये जाने विषयक श्री मानसिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	51
जनपद मथुरा के महुअन टोल टैक्स पर स्थानीय निवासियों का आवागमन निःशुल्क कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	51

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत ग्राम कुड़ी से सेहुडा होते हुये नकहा जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मधुसूदन यादव आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	51
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के विकास-खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पिरैला नरहरिया में सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मधुसूदन यादव आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	51
जनपद मोदीनगर में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के मजदूरों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में संसदीय समिति का गठन	52
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	52
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	53-54
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	54-120
अनुदानवार बजट साहित्य के उपलब्ध न होने पर व्यवस्था का प्रश्न... ...	120-122
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	122-125
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर की उपेक्षा एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	125
जनपद बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारियों द्वारा आदेश के बावजूद श्री रामप्रसाद त्यागी का भुगतान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री गयाचरण दिनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	126
जनपद बुलन्दशहर के ग्राम दौलतपुर कला में अवैध दुकानें बनाकर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)...	126
जनपद सहारनपुर के ग्राम शुक्रताल में सड़क के किनारे नाली व सड़क के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	126-127
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यूनिट मानचित्रों की स्वीकृति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	127-128
जनपद बिजनौर के नहटौर और हल्दौर के सरकारी अस्पताल में पर्याप्त डाक्टर, दवा तथा पैथालोजी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में श्री ओम कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	128

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर के ग्राम सलेमपुर से ग्राम पीकी तक राजवाहे की पटरी पर सड़क व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	128-129
जनपद चित्रकूट के ग्राम बरेठी में एक भी ट्यूबवेल न होने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	129-130
जनपद शामली में गिरते जल स्तर एवं नदियों के प्रदूषित पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	130

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 26 जून, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-346

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
20. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
23. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
24. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
28. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
30. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
32. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
33. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
34. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
35. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
36. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
44. इकबाल, श्री — बिजनौर
45. इकबाल महमूद, श्री — संभल
46. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
47. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
48. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
49. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
50. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती

51. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
52. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
55. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
56. उमाशंकर, श्री बलिया
57. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
58. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
59. ओम कुमार, श्री बिजनौर
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
62. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
63. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
64. काली चरन सुमन, श्री आगरा
65. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
66. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
67. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. कैलाश, श्री गाजीपुर
70. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
71. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
72. गजराज सिंह, श्री हापुड़
73. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
74. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
75. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
76. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
77. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
78. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
79. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
82. गोमती यादव, श्री लखनऊ
83. गोरख पासवान, श्री बलिया
84. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
85. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
86. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
87. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
89. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
90. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
91. जगपाल, श्री सहारनपुर
92. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
93. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
94. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
95. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
96. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
99. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
102. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
103. तसलीम, श्री बिजनौर
104. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
105. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
106. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
107. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
108. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
109. दलजीत सिंह, श्री बांदा
110. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
111. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
112. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
113. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़

115. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
116. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
118. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
119. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
120. धर्मराज, श्री बाराबंकी
121. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
122. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
123. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
124. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
125. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
126. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
127. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
128. नारद राय, श्री बलिया
129. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
130. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
131. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
132. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
133. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
134. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
135. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
136. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
137. पीतमराम, श्री पीलीभीत
138. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
139. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
140. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
141. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
142. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
143. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
144. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
145. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
146. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
147. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
148. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
149. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
150. फेरन लाल, श्री ललितपुर
151. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
152. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
153. बदलू खां, श्री उन्नाव
154. बाबू खां, श्री हरदोई
155. बाबूलाल, श्री गोण्डा
156. बावन सिंह, श्री गोण्डा
157. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
158. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
159. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
160. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
161. बैजनाथ, श्री मऊ
162. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
163. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
164. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
165. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
166. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
167. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
168. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
169. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
170. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
171. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
172. मनबोध, श्री देवरिया
173. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
174. मनीष रावत, श्री सीतापुर
175. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
176. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
177. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज

178. महबूब अली, श्री अमरोहा
179. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
180. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
181. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
182. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
183. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
184. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
185. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
186. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
187. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
188. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
189. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
190. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
191. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
192. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
193. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
194. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
195. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
196. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
197. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
198. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
199. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
200. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
201. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
202. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
203. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
204. यासर शाह, श्री बहराइच
205. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
206. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
207. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
208. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
209. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
210. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
211. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
212. रणजीत सुमन, श्री एटा
213. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
214. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
215. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
216. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
217. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
218. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
219. रवि शर्मा, श्री झांसी
220. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
221. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
222. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
223. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
224. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
225. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
226. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
227. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
228. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
229. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
230. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
231. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
232. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
233. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
234. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
235. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
236. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
237. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
238. राधे श्याम, श्री अमेठी
239. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
240. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर

241. राम करन आर्य, श्री बस्ती
242. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
243. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
244. राम गोविन्द, श्री बलिया
245. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
246. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
247. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
248. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
249. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
250. राम मगन, श्री बाराबंकी
251. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
252. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
253. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
254. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
255. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
256. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
257. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
258. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
259. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
260. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
261. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
262. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
263. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
264. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
265. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
266. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
267. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
268. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
269. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
270. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
271. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
272. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
273. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
274. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
275. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
276. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
277. विजय सिंह, श्री रामपुर
278. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
279. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
280. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
281. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
282. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
283. वीरपाल राठी, श्री बागपत
284. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
285. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
286. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
287. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
288. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
289. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
290. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
291. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
292. शाकिर अली, श्री देवरिया
293. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
294. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
295. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
296. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
297. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
298. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
299. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
300. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
301. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
302. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी

303. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
304. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
305. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
306. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
307. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
308. संजय कपूर, श्री रामपुर
309. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
310. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
311. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
312. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
313. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
314. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
315. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
316. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
317. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
318. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
319. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
320. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
321. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
322. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
323. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
324. सियाराम सागर, डा0 बरेली
325. सीमा, श्रीमती जौनपुर
326. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
327. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
328. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
329. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
330. सुधाकर, श्री मऊ
331. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
332. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
333. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
334. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
335. सुरेश राणा, श्री शामली
336. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
337. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
338. सुल्तान बेग, श्री बरेली
339. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
340. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
341. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
342. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
343. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
344. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
345. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
346. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :- मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण व विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नत्थी (क)

प्रदेश में यमुना नदी के किनारे अवस्थित बड़े शहरों के गन्दे पानी में गिरने से रोकने तथा प्रदूषण मुक्त करने सम्बन्धी कार्य योजना की जानकारी

**01-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यमुना नदी के किनारे अवस्थित बड़े शहरों की गंदी नालियों, सीवरों का पानी तथा औद्योगिक क्षेत्रों से उत्सर्जित कचरेयुक्त गन्दे पानी को यमुना नदी में गिरने से रोकने तथा उसे पर्यावरण के अनुकूल प्रदूषण से मुक्त किये जाने की सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

प्रदेश में यमुना नदी के किनारे अवस्थित बड़े शहरों की गंदी नालियों, सीवरों का पानी तथा औद्योगक क्षेत्रों से उत्सर्जित कचरेयुक्त गंदे पानी को यमुना नदी में गिरने से रोकने तथा उसे पर्यावरण के अनुकूल प्रदूषण से मुक्त किये जाने हेतु सरकार द्वारा यमुना नदी में घरेलू सीवेज से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु उ0प्र0 जल निगम एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से योजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं एवं वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योगों को अपने प्रदूषित जल को शुद्धिकृत करने के लिए औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करना होता हैं एवं उद्योगों से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह को निर्धारित मानक तक शुद्धिकृत करना होता है। उक्त का पालन न करने पर उनके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1

(प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

वह उपस्थित नहीं हैं।

श्री अखिलेश सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी सदन चला नहीं है व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया। प्रश्न प्रहर में व्यवस्था नहीं उठायी जाती जब प्रश्न प्रहर खत्म हो जाये तब उठाइयेगा।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के महानगरों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय

*01-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-13 व 2013-14 में प्रदेश के महानगरों में ध्वनि प्रदूषण का ग्राफ अत्यधिक तेजी से बढ़ने के कारण लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 प्रख्यापित किये गये हैं जो दिनांक 14-02-2000 से प्रवृत्त किये गये हैं एवं 2010 में संशोधित किये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीक्षक एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपर्युक्त नियमों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी की परिभाषा में आते हैं।

उक्त ध्वनि प्रदूषण नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिये ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय तथा शान्त क्षेत्रों/परिक्षेत्रों में प्रत्येक नगर को वर्गीकृत कराया गया है। सभी अस्पतालों शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों एवं न्यायालयों के आस-पास कम से कम 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र को शान्त क्षेत्र घोषित किया गया है तथा वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपदों में उड़नदस्तों का गठन किया गया है। जिसके नामित सदस्य जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी सम्बन्धित थाने का थानाध्यक्ष, अथवा उसका प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी हैं।

लाउडस्पीकरों से जनित ध्वनि प्रदूषण की रोक थाम हेतु प्रदेश में ध्वनि नियम 2000 में विनिर्धारित स्थलों पर रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य लाउडस्पीकर न बजाये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्म पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो वायुमंडल में कई तरह के प्रदूषण हैं चाहे जल प्रदूषण हो, चाहें ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो तीनों की प्रदूषण गम्भीर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ध्वनि प्रदूषण आज के आधुनिक युग की सबसे गम्भीर समस्या बन रही है। मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या महानगरों में ध्वनि प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है सरकार ने खुद माना कि ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और उसके प्रभाव में कई गम्भीर बीमारियों के शिकार प्रदेशवासियों को

होना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम चाहें आगरा की बात करें या लखनऊ की बात करें तो जो सरकार ने 4 वर्गों में बांटा है शहर को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और शांत क्षेत्र, अगर हम केवल लखनऊ की बात करें तो 2013 में जो मानक हैं आवासीय क्षेत्र के वह 55 डिसमिल होना चाहिये वह लखनऊ में 76.7 है आवासीय क्षेत्र में और जो वाणिज्य क्षेत्र में 65 होना चाहिए लखनऊ शहर में वह 78.8 हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र में 75 होना चाहिए वह 80.5 हैं और जो सबसे गम्भीर बात है जो सरकार ने शांत क्षेत्र घोषित किये हैं अगर वहां भी हम लखनऊ की बात करें तो जो प्रदूषण का मानक 50 है वह लखनऊ में 75.5 है यानि डेढ़ गुना अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी चाहे लखनऊ हो चाहे प्रदेश के महानगर हों या और भी शहर हो सभी शहरों में आवासीय और शांत क्षेत्र में जो ध्वनि प्रदूषण है वह मानकों से अधिक है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शहरों में महानगरों के साथ प्रदेश के और शहरों में आवासीय और शान्त क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण मानक से अधिक है। इसे कम करने के लिये जो आपने विवरण दिया है कि आपने उड़न दस्ते बनाये हैं। इन उड़न दस्तों ने अभी तक पिछले दिनों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है, यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कि सरकार पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये क्या पर्यावरण नीति बनाने पर विचार कर रही है और वह नीति कब तक बन जायेगी ?

जन्तु उद्यान (राज्य मंत्री) (डा0 शिव प्रताप यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक लखनऊ का सवाल है, यहां पर आटोमेटिक मानीटरिंग स्टेशन 5 जगहों पर बनाये गये हैं, पी0जी0आई0, लोहिया अस्पताल, इन्दिरा नगर, तालकटोरा इण्डस्ट्रियल एरिया और डी0आर0एम0 आफिस। इसके अलावा और भी स्थानों पर न्वायज मीटर के द्वारा चेंकिग होती रहती है, उड़न दस्ते चेंकिग करते हैं और जहां पर ध्वनि प्रदूषण की मात्रा ज्यादा पायी जाती है वहां पर नोटिस दी जाती है और कई चरणों में कार्यवाही की जाती है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मैंने कार्यवाही के बारे में पूछा था, माननीय मंत्री जी ने वह नहीं बताया। माननीय मंत्री जी ने जिन स्थानों का नाम लिया है, वह शान्त क्षेत्र में आते हैं। और वहां मानक से ज्यादा प्रदूषण है। आप जरा यह भी बता दें कि वहां मानक से ज्यादा कितना प्रदूषण पाया गया। मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि जहां मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण हैं वहां सरकार ने क्या कार्यवाही की, आपने कमेटी बना दी, आपने दस्ते बना दिये लेकिन उन दस्तों ने क्या किया। दूसरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा सवाल था कि क्या पर्यावरण नीति बनायेंगे उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नियम की बात है अधिनियम 1986, जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया, उसको वर्ष 2010 में यह संशोधित किया गया तो प्रावधान आलरेडी है, इसके लिये नये बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे यह सवाल तो महानगरों के सम्बन्ध में पूछा गया, अगर आप अनुमति दें तो एक सवाल पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

शाहजहांपुर का है इसमें कि नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो लोग हाउस में ध्वनि प्रदूषण करते हैं, उसके लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं है, उसमे आपका भी नाम आ सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक न तो सत्ता पक्ष की ओर से और न पीठ की ओर से मुझे इस बात के लिये कभी इंगित किया गया कि मैंने कभी इस हाउस में ध्वनि प्रदूषण किया हो। इसलिये विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहते हुये आपसे अनुरोध करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है, वही आप बता दें, सुझाव दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सुझाव तो यह है मान्यवर, कि जो लोग हाउस में ध्वनि प्रदूषण करते हैं, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की योजना बनाई है। हम तो केवल यह जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं है।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

यह नेता विपक्ष पर इनडाइरेक्ट हमला बोल रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार अगर कोई कार्यवाही करना चाहती है तो दो चीज हैं। एक तो सरकार पूरे प्रदेश का कोई सर्वे करायें और देखे कि विभिन्न महानगरों में वास्तव में ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है। सर्वे कराने के लिए हर महाजनपद में ध्वनि मापक यन्त्र होने चाहिए। अब ये जो उड़नदस्ते सरकार ने बना दिये क्या सरकार यह बतायेगी कि उन उड़नदस्तों को अलग-अलग महानगरों मे ध्वनि मापक यन्त्र दिये गये हैं जिससे कि वह माप सके कि यह 70 डेसिबल से अधिक हैं या नहीं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग इसको लेते हल्के से हैं अधिक शोर हो तो ब्लड प्रेशर होगा, अधिक शोर होगा तो कान के पर्दे फटेंगे, रात में नींद नहीं आयेगी, व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जायेगा। इतनी गम्भीर बीमारियां जिस चीज से पैदा होती हैं, तो मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे हम लोगों ने हल्के से लिया है। उड़नदस्ते क्या करेंगे अगर ध्वनि मापक यन्त्र नहीं है तो यह तो कहने की बात है कि हमने उड़नदस्तों को कह

दिया लेकिन उड़नदस्ते कैसे नापेंगे कि कितना शोर हो रहा है। तो सरकार पहले तो यह बताये कि विभिन्न जनपदों में विभिन्न महानगरों में नापने के लिए ध्वनिमापक यन्त्र दिया गया है या नहीं दूसरा प्रश्न यह कि सरकार ने कहा कि हम कार्यवाही करेंगे, 2002 के अधिनियम की बात की। मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि जो लोग ध्वनि प्रदूषण करते हैं भारत सरकार ने उनके लिए 5 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है, यह ऐक्ट में प्रावधान है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का ऐक्ट है उसमें ध्वनि प्रदूषण करने वालों के लिए सजा का क्या प्रावधान हैं। इन्हीं दो सवालों के जवाब दे दें तो सरकार की मंशा साफ हो जायेगी।

डा0 शिव प्रताप यादव-

जहां तक ध्वनि मापक यन्त्र का सवाल है तो मान्यवर, 18 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक मेन कार्यालय है। उत्तर प्रदेश नियन्त्रण बोर्ड का और वहां पर क्षेत्रीय कार्यालयों से महीने में एक बार सभी महानगरों में चेकिंग की व्यवस्था होती है और इसके अलावा अगर कहीं शिकायत मिलती है तो वहां पर भी क्षेत्रीय कार्यालय के लोग जाते हैं और जो परसेंटेज ऑफ ध्वनि है उसको ध्वनि प्रदूषण यन्त्र द्वारा नापते हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

जो ऐक्ट में सजा है उसको तो बात दीजिए।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, जो सजा की बात है जो ऐक्ट है उसमें व्यवस्था है उसे हम बता देंगे क्योंकि यह प्रश्न सजा के बारे में तो है नहीं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यह प्रश्न लाने का मेरा उद्देश्य यही था, हमारे पास सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, बहुत हल्के आर्थिक दण्ड देकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों को हम छोड़ देते हैं। भारत सरकार ने पांच साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था की है क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो भारत सरकार ने ऐक्ट बनाया है और जिस सजा का प्रावधान किया है हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने ऐक्ट में उचित परिवर्तन करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी-

मान्यवर, पहले से बता दें कि ध्वनि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं पहले इसकी व्याख्या कर दें, यही आप बता दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं जवाब दे दूंगा। सरकार स्वीकार कर लें कि वह जवाब देने में सक्षम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य का कहना यह है कि आपका जो विधान है उसमें सजा कम है क्या भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जिसमे सजा का प्रावधान ज्यादा है, इस प्रकार का क्या कोई प्रावधान बनाने पर आप विचार करेंगे।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, कई चरणों में होता है पहले नोटिस दिया जाता है उसके बाद क्लोजर के लिए लिखा जाता है तो अभी तक तो भारत सरकार द्वारा जो आप बता रहे हैं संज्ञान में लाये हैं उस पर विचार कर लिया जायेगा।

प्रदेश में उद्योगों द्वारा नदियों मे डाले जा रहे विषैले रसायनिक पदार्थों को प्रदूषण मुक्त बनाने सम्बन्धी जानकारी

*02-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बह रही नदियां, जो फैक्ट्रियों तथा अन्य उद्योगों द्वारा डाले जा रहे विषैले रसायनिक पदार्थों के कारण प्रदूषित हो गयी है, को प्रदूषण मुक्त करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश में बह रही नदियां, जो फैक्ट्रियों तथा अन्य उद्योगों द्वारा डाले जा रहे विषैले रासायनिक पदोर्थों के कारण प्रदूषित होती हैं, उनके जल की गुणता का अध्ययन राष्ट्रीय जल गुणता अनुश्रवण प्रोग्राम के अंतर्गत गंगा, वरुणा, काली, रामगंगा, सई, हिण्डल, गोमती, सरयू, यमुना, घाघरा, राप्ती, वेतवा, रिहंद जलाशय, रामगढ़ लेक, गोविन्द सागर, समरपुर झील, माहिल एवं लक्ष्मी तालाब को सम्मिलित करते हुए 53 स्थलों पर प्रतिमाह किया जाता है।

उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योगों को अपने प्रदूषित जल को शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करना होता है एवं उद्योग शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करना होता है एवं उद्योग से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह को निर्धारित मानक तक शुद्धिकृत करना होता है। उक्त का पालन न करने पर उनके विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज देश भर में नदियों को साफ करने के लिए एक चर्चा हो रही है क्योंकि नदियां इस देश की लाइफ-लाइन हैं। कभी-कभी हम इस बात को कहते हैं कि हम फलानी नदी को बचाने का प्रयास करेंगे। इस पर कई तरह के आन्दोलन चलते हैं, सेव गंगा के ऊपर सेमिनार होते हैं। मान्यवर, गंगा नदी आदि काल से है और आदिकाल तक रहेगी। आज मनुष्य को बचाने के लिए नदियों का संरक्षण करना आवश्यक है उसको सही तरीके से साफ करना आवश्यक है। विशेष रूप से गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान विगत कई वर्षों से चल रहा है, यमुना एक्शन प्लान भी चल रहा है और विभिन्न नदियों को भी साफ करने के लिए समय-समय पर कार्यवाही होती है। मगर इतने वर्षों के बाद भी इस बात को नहीं कहा जा सकता कि गंगा नदी का जल विशेष रूप से कानपुर महानगर में आचमन तो दूर स्नान करने लायक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, गंगा के साथ हम धार्मिक आधार पर जुड़े हुए हैं, सामाजिक आधार पर भी जुड़े हुए हैं और जीवन की लइफ-लाइन के

कारण जीने के लिए भी जुड़े हुए हैं, इसकी अगर व्याख्या की जाए तो अपने आप में बहुत विस्तृत हो जायेगा। उसका उत्तर इतने हल्के से मिलेगा मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप मेरा प्रश्न और उत्तर देख लें। मैंने पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बह रही नदियां, जो फैक्ट्रियों तथा अन्य उद्योगों द्वारा डाले जा रहे विषैले रसायनिक पदार्थों के कारण प्रदूषित हो गयी है, को प्रदूषण मुक्त करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछ लीजिए, यह तो इसमें है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपका ध्यान जायेगा तो मुझे संरक्षण मिलेगा, मुझे आसानी होगी और जब आपका संरक्षण मिलता है तो बहुत कुछ हो जाता है। उसका उत्तर दिया कि जी हां। जो विस्तृत विवरण बताया है उसमें फैक्ट्रियों तथा अन्य उद्योगों द्वारा डाले जा रहे विषैले रसायनिक पदार्थों के कारण प्रदूषित होती है, उनके जल की गुणता का अध्ययन राष्ट्रीय जल गुणता अनुश्रवण प्रोग्राम के अन्तर्गत 53 स्थलों पर प्रतिमाह किया जाता है। आगे इन्होंने दिया है कि जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 के अनुसार फैक्ट्री वालों को उसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाना चाहिए। मान्यवर, जब सारी की सारी मॉनीटरिंग हो रही है तो क्या यह सरकार इस बात को कहने के लिए तैयार है कि सारी फैक्ट्रियों के अन्दर यह प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगे हुए हैं और क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने के बाद हम इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि गंगा में शुद्ध जल जा रहा है और अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने के बाद अगर ट्रीटमेंट प्लाण्ट की आवश्यकता नहीं है तो फिर सरकार ने वह ट्रीटमेंट प्लाण्ट क्यों लगाये ? मैं आपके माध्यम से केवल इतनी जानकारी करना चाहता हूं कि ऐसे कितने स्थानों के ऊपर ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लाण्ट फैक्ट्रियों में लगने चाहिए थे और कितने स्थानों पर लगे हैं और कितने स्थानों पर नहीं लगे हैं और जहां पर नहीं लगे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? दूसरी बात जो फाइनल ट्रीटमेंट प्लाण्ट है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट है और दूसरे ट्रीटमेंट प्लाण्ट हैं जो फैक्ट्रियों के प्रदूषित जल का शोधन करते हैं वह कितने स्थानों के ऊपर लगने चाहिए थे और कितने स्थानों पर लगे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आपने बड़ा विस्तृत प्रश्न पूछ लिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने विस्तृत प्रश्न पूछ लिया है इन्होंने बताया है कि उद्योगों को अपने प्रदूषित जल को शुद्धीकृत करने के लिए औद्योगिक उत्प्रवाह, शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करना होता है। एवं उद्योग से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह को निर्धारित मानक तक शुद्धिकृत करना होता है। उक्त का पालन न करने पर उनके विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। आप पूछ रहे हैं कि कितने जगह लगा है तो यह बड़ा लम्बा प्रश्न होगा। दण्ड वाला पूछ लेते।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

डा0 शिवप्रताप यादव-

अध्यक्ष जी यह जो कार्यवाही की गयी है 43 फैक्ट्रियों को क्लोजर का आर्डर कर दिया गया है जिन्होंने ई0टी0पी0 नहीं लगाए थे। इसके अलावा नोटिस आफ डायरेक्शन दिया गया है ऐसे 25 फैक्ट्रियों को सुधरने का मौका दिया गया है। 8 को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि क्यों न उद्योग बन्द कर दिया जाय।

श्री सतीश महाना-

मेरा दूसरा प्रश्न जो था उसके बारे में इन्होंने बताया कि 43 के खिलाफ कार्यवाही की गयी तो कितनी फैक्ट्री लगी है गंगा और इन सारी नदियों के किनारे यह जानकारी होनी चाहिए जब जानकारी नहीं है तो आप कार्यवाही कैसे करेंगे। 500 से ज्यादा फैक्ट्री तो कानपुर और उन्नाव में लगी हैं। इनमें से 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों ने ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं लगाए हैं। मैं एक ही जिले की बात कर रहा हूं और यह पूरे प्रदेश का जवाब दे रहे हैं कि 43 के खिलाफ कार्यवाही की गयी मेरा दूसरा प्रश्न था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद किसी प्रकार के शोधन की आवश्यकता होती है। यदि होती है तो कितनी जगह आपने प्लाण्ट लगाया है।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, टोटल उद्योग 1,868 हैं। इनमें यह कार्यवाही की गई जो हमने बताया जो नदियां हैं उनके जल के लिए जो निर्धारित मानक हैं ई0टी0पी0 के बाद जो निर्धारित मानक हैं उसके अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे श्रेणी ए में लिया जाता है जिसमें डिजाल्व आक्सीजन की मि0ग्राम प्रति ली0 की मात्रा है वह 6 न्यूनतम होनी चाहिए। और बी0श्रेणी में 5 होनी चाहिए। यह घुलित आक्सीजन की मात्रा है अगर 4 मि0ग्रा0 प्रति लीटर डी0ओ0 की मात्रा है तो सी श्रेणी हुआ इसी प्रकार डी0 में भी 4 है और ई में इससे भी कम मात्रा होती है। ए श्रेणी में बिना पारम्परिक उपचार के लिए जीवाणु नाशक के पश्चात् पानी उपयोगी हो जाता है और यह पानी पीने योग्य हो जाता है। बी0 श्रेणी को हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं केवल स्नान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सी श्रेणी का पानी कीटाणुनाशक एवं पारम्परिक उपचार के बाद पीने योग्य होता है। डी श्रेणी मत्स्य पालन के लिए है। ई श्रेणी का पानी सिंचाई एवं इण्डस्ट्रियल कूलिंग के लिए उपयोगी है। यह मानक है।

श्री सतीश महाना-

मैंने पूछा था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी उसका उत्तर नहीं आया। मान्यवर, एक छात्र था उसने क्रिकेट पर एस्से याद किया लेकिन हवाई जहाज पर एस्से आ गया तो उसने लिखा कि हवाई जहाज पर बैठा लेकिन जहाज खराब हो गया जिससे वह उतरा और उसने फिर क्रिकेट खेला और क्रिकेट पर याद किए हुए एस्से को लिख दिया। मान्यवर, जब तक क्रिकेट का एस्से खत्म हुआ तो हवाई जहाज पर लिख दिया। तो मान्यवर, यह जो याद करके आये हैं बिना मतलब वह बोले चले जा रहे हैं। मैंने प्रश्न किया था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लाण्ट के बाद भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है ? अगर होती है तो कितनी जगह ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाया गया है ? मान्यवर, इसका उत्तर नहीं आया तो मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो सबका आ रहा है।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न पूरे प्रदेश के लिये बड़ा गम्भीर विषय है और कई बार कई नियमों में मैंने इसे उठाया है और आपका उस पश्चिम क्षेत्र में काफी प्रवास हुआ है, आपको जानकारी भी है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सहारनपुर से लेकर पश्चिम में दो नदियां कृष्णा और हिन्डन निकलती हैं। हिन्डन की चर्चा जवाब में भी आई है, कई बार मैंने पूछा भी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सरकार के संज्ञान में भी होगा अभी सहारनपुर में 15 दिन तक अनशन चला और मैं पूरी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। शुगर फैक्ट्री नरोता, गतता फैक्ट्री नरोता, बजाज हिन्दुस्तान थाना बोवन, श्यामली की अनेकों फैक्ट्रियां, मुजफ्फरनगर का पूरा उद्योग इनका सारा का सारा जो पानी है, यह हिन्डन और कृष्णा में जाता है और महत्वपूर्ण इसलिये भी है मान्यवर, कि लाखों लोग बीमारी की चपेट में हैं। कैंसर, पीलिया तमाम प्रकार की बीमारियां गांव में फैल गयी हैं। पहले से ही गांव में आर्थिक संकट है। एक-एक गांव में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह लोग कैंसर की चपेट में हैं।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछिये।

श्री सुरेश राणा-

मेरा यह निवेदन है और सवाल भी है कि क्या जिन फैक्ट्रियों का मैंने नाम बताया है पूरी जानकारी के आधार पर बताया है, न उनमें कोई ट्रीटमेंट प्लाण्ट है, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी, यह मेरा ऑथेन्टिक सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो नाम बताये हैं, उसके बारे में बतायेंगे।

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय सदस्य सूची दे देंगे हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

जल की गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिये अध्यक्ष जो राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोग्राम के तहत इनका नदियों का जो जल प्रदूषित होता हे, उसकी जांच होती है। मान्यवर, हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी निकल रही है और शारदा नदी का नाम इन नदियों में शामिल नहीं है जबकि पलिया से लगाकर खपलिया, खम्भार खेड़ा, गुनरिया और कम से कम 7-8 चीनी मिलों का दूषित पानी शारदा नदी में जाकर उसमें मिलकर उसको प्रदूषित कर रहा है। हमारे यहां वैसे भी पानी की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। पीने का पानी पीने लायक नहीं है। सबसे ज्यादा घेंघा, थॉयराइड, कैंसर दुनिया भर की बीमारी पेयजल न होने की वजह से होती है।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे जनपद लखीमपुर की चीनी मिलों का, जिनमें ने ए0टी0पी0 है ना उनके यहां उसको शोधन करने का कोई इंतजाम है तो यह अपना सारा पानी निकालकर शारदा नदी में डालते हैं तो पहला तो हम यह कहना चाहते हैं कि इसको जो जल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोग्राम है उसमें शारदा नदी को सम्मिलित किया जाय दूसरा जो शारदा नदी में दूषित प्रदूषित पानी डाला जाता है, इसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न है कि शारदा नदी इसमें नहीं है, इसको भी दिखवा लीजिये।

डा0 शिव प्रताप यादव-

यह जो प्राधिकरण है इसमें इसको प्रथम चरण द्वितीय चरण में नहीं लिया जाता है लेकिन जो यह माननीय सदस्य ने फैक्ट्रियों का नाम लिया है कि वहां ए0टी0पी0 नहीं लगा है, तो इसको दिखवा लेंगे, नहीं लगा है लगवा दिया जायेगा।

डा0 मो0 अयूब-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देता हूं आपने हमें प्रश्न पूछने का अवसर दिया। सरकार के संज्ञान में है कि भू-गर्भ जनित बीमारियां इन्सेफलाइटिस, बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल में है और वहां का भू-गर्भ जल प्रदूषित है इसके लिये मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अरे सवाल करिये ना। नदियों की बात हो रही है।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। क्योंकि हमारे जनपद में भू-गर्भ जल कैमिकल से प्रदूषित हो रहा है इसीलिये मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो फैक्ट्रियां इन्डस्ट्रियल एरिया में हैं उन पर तो कुछ प्रतिबन्ध है, मगर जो फैक्ट्रियां इन्डस्ट्रियल एरिया में न हो करके गांव में लगी हुई है, बड़ी इन्डस्ट्रियां, उनमें कोई चेक नहीं है और वह सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रही है और गांव और जनता उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में धौरहरा गांव में एक रैना पेपर मिल लगी हुई है, उसे रैना पेपर मिल से धौरहरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र जल प्रदूषण के साथ-साथ, वायु प्रदूषण से संक्रमित है और शिकार है। अगर आप एक घण्टा धौरहरा गांव में बैठ जाये तो पूरा कपड़ा राख के उत्सर्जन से काला हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न तो नदियों के बारे में है, आप राख के उत्सर्जन की बात कह रहे हैं।

डा0 मो0 अयूब-

अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां स्क्रैबर न लगने की वजह से पूरा वायु मण्डल प्रदूषित है। इससे पीने का शुद्ध पानी बाहर अगर कोई रखता भी है, वह भी काला हो जाता है, खाना

पर पड़ जाता है, उसमें इतना राख निकलता है, इसके लिये स्क्रैबर लगाना हर इन्डस्ट्री के लिये जरूरी होता है जो धान से ब्वायलर चलाते हैं, मगर स्क्रैबर की व्यवस्था न होने से पूरा वायु प्रदूषित है और जो फैक्ट्री से केमिकल निकलता है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल तो पूछिये, क्या चाहते हैं ?

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, इसके लिये मैंने स्वयं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर पत्र दिया था। मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे जिलाधिकारी महोदय के साथ-साथ यहां के प्रदूषक नियंत्रक को इन्फार्मेशन देने के बाद भी इस पर कार्यवाही नहीं हुई और आज तक उस रैना पेपर मिल से जो उत्सर्जन निकल रहा है, जिससे वायु प्रदूषित हो रही है और जिससे जल प्रदूषित हो रहा है, क्या सरकार उसकी जांच करा करके उस पर प्रतिबन्ध लगायेगी या समुचित व्यवस्था करेगी ताकि वहां जल और वायु प्रदूषण न हो ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि खलीलाबाद में घौरहरा गांव में एक रैना पेपर मिल लगी हुई है, वहां एक नदी भी है, ये उस नदी का नाम नहीं ले रहे हैं। यह कह रहे हैं उसमें स्क्रैबर नहीं लगाया गया है तो क्या इसको दिखवा लेंगे, यहीं इनका प्रश्न है।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नदियों से जुड़ा हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी माननीय विधायक जी ने भी उठाया, शामली में मुजफ्फरनगर में हिंडन नदी और कृष्णा नदी पूरी तरह से प्रभावित है और आस-पास के गांवों में बीमारी फैली है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सरकार गंभीरता दिखाते हुये, जिनका जिक्र किया गया है, कृष्णा नदी के लिये क्या कोई जांच समिति बना करके जांच कराने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

भड़ाना जी पूछिये।

श्री पंकज कुमार मलिक-

अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिये।

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरठ की काली नदी बहुत प्रदूषित हो रही है, अध्यक्ष जी, यह काली नदी, मेरठ में बह रहे गन्दे पानी और कारखानों की वजह से प्रदूषित हो रही है। मैं पूर्व में भी इस सदन को अवगत करा चुका हूं, क्या सरकार उसकी सफाई के लिये कोई समुचित व्यवस्था करायेगी ?

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरशराबा उत्पन्न हो गया, शोर शराबे के मध्य।)

श्री रविन्द्र भड़ाना-

नम्बर दो, क्या सरकार मेरठ में जो अवैध कमेले चल रहे हैं उनका गंदा पानी काली नदी में छोड़ा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कमेला कहां से आ गया। हो गया, आपका वह सवाल नहीं बनता। चलिये बैठिये।

(इस बीच विपक्ष के कई सदस्य लगातार बोलते रहे, शोरशराबा जारी रहा।)

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, जनपद हरदोई में मेरे विकास खण्ड भरभनी में बह रहे नाले में बदायूं जनपद से अत्यन्त प्रदूषित केमिकल युक्त काला बदबूदार पानी छोड़ा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा करिये, कि आप इसको मंत्री जी को लिखकर दे दीजिये। वह उसकी जांच करा लेंगे। अब हम आगे बढ़ते है।

(राष्ट्रीय लोक दल एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में व्यवधान हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सरकार के पास किसी भी प्रकार की योजना प्रदूषण को रोकने की नहीं है। मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है।

(शोर शराबे के कारण भाषण सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सीटों पर जायें। अब चलिये, चलिये। कांग्रेस के मा0 सदस्यगण आप अपनी सीटों पर जाये। चलिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में उद्यमियों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरा पैसा खाता है। एस0टी0पी0 चलते नहीं है।

(शोर शराबे के कारण भाषण सुना नहीं जा सका।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप सीटों पर चलें। अपने स्थानों पर जायें। सवाल महाना जी का है और यह लोग यहां खड़ें हैं। जाइये अपने स्थान पर जाइये।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, यह नदियों का प्रदूषण दूर नहीं करना चाहते है यह राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गंगा का प्रदूषण दूर करेंगे तो वहां जाकर पूछिये न।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग चलिये। अब आप चलो न, अपनी सीटों पर जाये। आप सभी से निवेदन है कि अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

(सदन के वेल में उपस्थिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्यगण अपनी-अपनी बात कहते रहे, जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न रही।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जायें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आपने मौका दिया, हमने अनुपूरक प्रश्न पूछा, लेकिन मा0 मंत्री जी ने अनुपूरक का उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपकी इच्छा नहीं है कि यह सदन चले तो बता दें, रोज-रोज प्रश्न प्रहर को बाधित करने का यह तरीका ठीक नहीं है और हमको मजबूर न करिये कि हम और अधिकारों का प्रयोग करें, इसलिये आप लोग चलकर अपनी सीटों पर बैठें।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, दिल्ली में यमुना नदी से पानी निकाल लिया जाता है, यमुना नदी दिल्ली से आगे चलकर जब चम्बल में मिलती है तो यमुना में पानी आता है, मैं इनसे बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को एक वृहद कार्य योजना बनानी चाहिये, यमुना नदी का पानी दिल्ली में ही निकाल लिया जाता है और जब आगरा और मथुरा में नदी आती है तो पानी ही नहीं रहता है, यह तो कहिये ड्रेन का पानी, सीवरेज का पानी उसमें जाता है तो ज्यों-ज्यों यमुना आगे आती है, तो आगे यमुना में बेतवा वगैरह जो नदियां हैं वह उसमें मिलती है तब जाकर यमुना में पानी आता है। इसलिये मैं इनसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को नदियों के बारे में व्यापक कार्य योजना बनाई जानी चाहिये। यहां एक प्लान्ट का मामला नहीं है, यह पूरे हिन्दुस्तान का मामला है। अब दिल्ली से यमुना आती है, अगर इटावा में चम्बल नहीं न मिले यमुना नदी में तो आगे पानी ही नहीं रहेगा, तो इसके लिये व्यापक कार्य-योजना बनाने की जरूरत है। इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, अगर यमुना नदी दिल्ली में प्रदूषित है, दिल्ली में ही उसका पानी निकाल लिया जाता है, तो कहां से आगरा, मथुरा में पानी आयेगा, यू0पी0 में पानी कहां से आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर चलें, यह छपेगा नहीं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, हमको छपवाना नहीं है, हम तो सिर्फ इतना उत्तर चाहते हैं कि इसके लिये जांच समिति बनेगी कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर चलिये, माथुर साहब इन लोगों को बुलाइये।

(तत्पश्चात् सदन के वेल में उपस्थिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, यह फैक्ट्रियों के नाम दे दें, उसको हम दिखवा लेंगे, परीक्षण करा लेंगे कि ई0टी0पी0 लगा है या नहीं लगा है, लिस्ट दे दें।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, सवाल का जवाब नहीं आया और मा0 मंत्री जी का एक भी जवाब संतोषजनक नहीं था, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो सबसे भ्रष्ट विभाग है पर्यावरण विभाग का, जिसके सारी यूनिटों से बंधे हुये पैसे आते हैं, उनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं चलते, नगर महापालिका नहीं चलाती, क्योंकि उनके पैसे बंधे हुये आते हैं, पूरे प्रदेश की नदियों का हाल इसीलिये खराब है, नदियों में सारा गन्दा पानी जाता है, यमुना प्रदूषित हो रही है, गंगा प्रदूषित हो रही है, गोमती प्रदूषित हो रही है, देश की सारी नदियां प्रदूषित हो रही है और मा0 मंत्री जी का एक भी जवाब सही नहीं है।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, इस समस्या की जड़ में जायं, यमुना नदी का पानी पहले ही दिल्ली में सब निकाल लिया जाता है, आगरा और मथुरा तक पानी नहीं पहुंच पाता है, तो पहले इसके लिये वृहद कार्य योजना बनाई जानी चाहिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, नदियों का जल प्रदूषित होने से लोगों में त्वचा सम्बन्धी रोग हो रहे हैं, हेपेटाइटिस-सी जैसे रोग हो रहे हैं, लेकिन सरकार इसके प्रति गम्भीर नहीं है, मा0 मंत्री जी ने कोई भी जवाब संतोषजनक ढंग से नहीं दिया, इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(तत्पश्चात् श्री प्रदीप माथुर के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्यगण सदन का बर्हिगमन कर गये।)

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता कांग्रेस की पीड़ा यह नहीं थी कि यमुना नदी पर क्या बात करें, उनकी पीड़ा यह थी कि उन्हीं के सदस्य उन्हीं के खिलाफ बहिष्कार कर गये, तो उनके पास कुछ बचा नहीं था। मान्यवर अगर वह इतने ही पीड़ित थे तो विषय के ऊपर बात-चीत करते। उनके एक मा0 सदस्य गये, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे तो वह नाराज होकर चल दिये, इसके कारण उन्होंने सदन का बर्हिगमन किया है, इसलिये मान्यवर आप परेशान न हों। दूसरी बात मान्यवर, यहां पर मैंने

पूछा था कि सरकार इसके प्रति क्या कर रही है, मान्यवर, सरकार के आदरणीय मंत्री जी को यह पता ही नहीं है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लान्ट के बाद भी पानी का शोधन होना चाहिये, चाहे इन्फ्लूएन्स ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के द्वारा चाहे सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के द्वारा। मान्यवर, जब उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है। मान्यवर, मैंने जिस समय प्रश्न पूछा तो आपने नहीं बताया। मान्यवर, आपके कहने के बाद भी इन्होंने नहीं बताया।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, इतने सीनियर मेम्बर हो करके आप इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। ई0टी0पी0 लगता है फैक्ट्रीज में और एस0टी0पी0 लगता है सीवर प्लान्ट में। हमारे पास पूरा डाटा है।

श्री अध्यक्ष-

वह जानते हैं, सब बताये हैं आपको। मा0 मंत्री जी ने सब उत्तर दिया है, आप समझ नहीं पाये महाना जी, उन्होंने सब उत्तर दिया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सरकार के पास जानकारी नहीं है। सरकार इस पर कुछ करना नहीं चाहती है इसलिये मान्यवर, मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते है।

(तत्पश्चात् श्री सतीश महाना भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मो0 आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी प्रदूषण को लेकर कांग्रेस के मा0 सदस्यों ने और बाद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बहिष्कार किया। आप भी जवाब सुन रहे थे और संतुष्ट थे। हर प्रश्न का जवाब आ रहा था लेकिन इन दोनों राजनैतिक दलों के लिये बड़ी परेशानी का सवाल यह है कि एक ने सत्ता खोई है और एक ने सत्ता पाई है। जिन्होंने ने सत्ता खोई है उन्हें खोने का डर है और जिन्होंने सत्ता पाई है उन्हें भी जल्द खोने का डर है। महंगाई कम हो इसके लिये राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया है, केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नदियों का पानी साफ हो इस पर केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकारें ही करें जबकि इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया और सरकार बनी तो वे महंगाई कम करेंगे। बजाय महंगाई कम करने के महंगाई कहां है आपको भी मालूम है तो क्योंकि यह प्रश्न बहुत पहले का लगा हुआ है और उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी। वह प्रश्न और आज के हालात में बहुत फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सदन में इस बात के लिये जवाबदेह होना पड़ेगा कि जिन मुद्दों पर चाहे का बनारस हो, चाहे दिल्ली से गुजरने वाली नदियां हो। केन्द्र सरकार ने क्या शुरूआत की है। जब तक केन्द्र सरकार कोई शुरूआत नहीं करती तो जो गन्दगी लेकर राज्यों में नदियां आती है, उनकी सफाई का क्या तरीका होगा। यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिये। मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि इस तरह का माहौल जैसा आपने देखा और आपने बार-बार यह कहा, इंगित भी किया कि प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है और वेल में कांग्रेस पार्टी के सदस्य आ रहे हैं। अगर इस परिपाटी को आप रोक सकें तो बहुत अच्छा होगा अन्यथा ये प्रश्नों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। रोज यह देखा जा रहा है कि ज्यादा वक्त हंगामे की नज्र किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अखबार की और टेलीविजन की खबरें बनायी जा सकें तो जिन लोगों ने अखबार और टेलीविजन के जरिये

सत्ता हासिल की है। जिन्होंने पूरे देश में भ्रम पैदा करके और अपनी दौलत की ताकत का बेपनाह इस्तेमाल करके, मीडिया पर कब्जा करके, मीडिया का नाजायज इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की है क्योंकि आज के दिन उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है लेकिन हमारा और आपका यह दायित्व बनता है कि हमारा संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से और आपका मा0 अध्यक्ष की हैसियत से कि इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिये और प्रश्नकाल शांतिपूर्वक होना चाहिये।

प्रदेश में वेबसाइटों की सुरक्षा पुख्ता करने सम्बन्धी जानकारी

*03–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी विभागों के वेबसाइटों को हैक करके संवेदनशील जानकारियां अपराधियों तक पहुंचने के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा पुख्ता करने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

एन0आई0सी0 से प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक रखने का आपने अवसर दिया। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था लेकिन इसको हल्के में लिया गया। मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा था कि क्या सरकारी विभागों के वेबसाइटों को हैक करने की जानकारी सरकार के पास है। इस पर जवाब आया है कि एन0आई00सी0 से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जबकि सत्यता है इसे गूगल पर भी देखा जा सकता है। 29 मई, 2014 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में भी छपा कि हिन्दुस्तान के भारत और पाकिस्तान के दोनों प्रधानमंत्रियों के मुलाकात के तीसरे दिन ही उत्तर प्रदेश गर्वमेंट की तीन वेबसाइटें हैक कर ली गयीं पाकिस्तानी हाईकर्स के द्वारा डब्ल्यू0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 डॉट-ताजमहल, डब्ल्यू0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 डाट आगराफोर्ट, डब्ल्यू0डब्ल्यू0डब्ल्यू0, डॉट-फतेहपुर सिकरी ऐसी उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग की तीन वेबसाइटें हैक की गयी, तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई जांच करवायी जायेगी या इसके लिये कोई ठोस रणनीति या प्राविधान किया जायेगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

डा0 शिव प्रताप यादव-

जैसाकि मैंने बताया कि एन0आई0सी0 से जो प्राप्त सूचना है, उसके अनुसार कोई सरकारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी वेबसाइट हैक नहीं हुई है। जहां तक सवाल है एन0आई0सी0 डाटा सेन्टर से वेबसाइट जो होस्ट की जाती है, भारत की सरटेन द्वारा निर्धारित इंटरनेट सुरक्षा नीति के अन्तर्गत निर्धारित है और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा सिक्योरिटी के लिये आडिट होता इनपैनाल्ड एजेन्सीज हैं, उसमें एक भारत सरकार की एजेन्सी है एस0टी0क्यू0सी0 और दो प्राइवेट कम्पनी है, साइबर क्यू0 और इ0 सेन्ट्रिक, तो इनसे पूरा आच्छादित है, तो इसमें पूरी व्यवस्था की गयी

है कि हैक न किया जाये और जहां तक हमको जानकारी है हमारी किसी भी सरकारी वेबसाइट को हैक नहीं किया गया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है और सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। डब्ल्यू0डब्ल्यू0 ताजमहल भारत का सबसे अच्छा वेबसाइट माना गया था, सर्टिफिकेट मिली थी। मा0 सदस्य ने सिर्फ तीन की बात की अभी परसों तीन नौजवानों ने समाचार पत्र में इंटरव्यू देकर कहा, छपा है इंटरव्यू कि हमने यू0पी0टी0यू0 की वेबसाइट सात महीने तक हैक की। हमने महामाया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट 2010 से हैक की। ग्रामीण बैक बलिया की वेबसाइट हैक हुई। ये जो एक स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी है उसमें एक दुखःद प्रकरण हुआ था, कुछ क्रिकेट के मैच को लेकर कुछ विद्यार्थियों को दण्ड दिया गया था। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई और सवाल यह है कि सरकार यह कह रही है कि इसको किसी भी हैकिंग की जानकारी नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर सरकार को जानकारी नही है, पूरे प्रदेश को जानकारी है, हम लोगों को, जानकारी है, तो सरकार कहीं तो यह बतायेंगी कि प्रदेश की सुरक्षा के प्रति, और तो और अध्यक्ष जी जिस एन0आई0सी0 की यह चर्चा कर रहे हैं, उस एन0आई0सी0 की वेबसाइट यू0पी0 गवर्मेंट एन0आई0सी0 डॉट इन यह भी हैक हो चुकी है। और इसी के हवाले यह कह रहे है कि किसी की सूचना नहीं है, जिसके हवाले से कह रहे हैं उसकी कि वेबसाइट हैक हो चुकी है। सवाल है कि सरकार तो किसी हैकिंग को स्वीकार नहीं कर रही, या तो जान नहीं रही अधिकारियों ने बताया नहीं या जानती है जानबूझकर छिपा रही है। सरकार को अपनी मंशा जाहिर करनी चाहिये। आज के युग में आक्रमण सीमाओं से नहीं होता। सीमाओं से आक्रमण तो न जाने कब होगा, अब ये आक्रमण की नई विधाये हैं और हम इनको गैर जिम्मेदारी के साथ नहीं ले सकते। एक-एक लागिंग और एक-एक पासवर्ड की हैकिंग की गई है और अगर इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर यू0पी0टी0यू0 में तो अध्यक्ष जी, 800 कालेज की साइट हैक कर ली गयी। सारे स्टूडेन्ट का बायोडाटा चुरा लिया गया। जब खुले आम बोला जा रहा है तो क्या सरकार कहीं इसको संज्ञान में लेगी। तो क्या सरकार यह बतायेंगे कि जो प्रकरण मैंने सदन में दिये इनको तो अपने-आप संज्ञान में होना चाहिये लेकिन नहीं है चलिये हम इनकी मदद करते हैं जो प्रकरण हम लोगों ने दिये उस प्रकरण की ये जांच करायेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी वह दुबारा हैकिंग न हो इसके लिये कदम उठाने पड़ेंगे।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों की वेबसाइट हैकिंग होने के बारे में कहा गया है। मैंने स्पष्ट कहा है कि हैकिंग नहीं होती है। माननीय सदस्य ने सुभारती और इंजीनियरिंग कालेज की बात कहीं है। वह स्वायतशासी बाडी है और उनके बारे में प्रश्न नहीं किया गया है, हम दिखवा लेंगे यदि आप लिखकर के दे देंगे।

प्रदेश में पी0आर0डी0 जवानों के दैनिक पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी का विचाराधीन प्रकरण

*04-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0आर0डी0 जवानों का दैनिक पारिश्रमिक 160-रु0 प्रतिदिन दिया जाता है ? क्या यह सही है कि उक्त पारिश्रमिक सरकार के द्वारा

घोषित अकुशल श्रमिक की प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी दर से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की गणना करने का आधार पी0आर0डी0 जवानों के दैनिक पारिश्रमिक से भिन्न है तथा इस आधार पर पी0आर0डी0 जवानों के दैनिक पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं किया जाता है।

पी0आर0डी0 जवानों के दैनिक पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी का प्रकरण विचाराधीन है।

श्री मनीष असीजा-

श्रीमन्, पी0आर0डी0 नौजवानों का दल है। देश की आजादी के बाद 1948 में इसका गठन हुआ था। मान्यवर, इस दल में उस समय नौजवानों की भर्ती हुयी थी क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में पुलिस फोर्स बहुत कम था और यह लोग पुलिस बल के कामों में मदद कर रहे थे। उस समय तमाम ऐसे काम थे जो पुलिस बल में कमी के कारण वह कर रहे थे। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था है, लेकिन 1962 से इसका क्षरण होना प्रारम्भ हुआ है। मान्यवर, जब से यह होमगार्ड संवर्ग का गठन हुआ है उसके बाद से इसकी दिनोंदिन स्थिति बिगड़ती चली गयी है। मान्यवर, आज प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है और पुलिस बल के पास पहले से ही इतने काम है कि वह सब काम नहीं कर सकती है और उनके कामों में यह पी0आर0डी0 बल के लोग सहायता करते हैं जैसे चुनाव के संचालन में। मान्यवर, राज्य में लगभग 36 हजार के आसपास पी0आर0डी0 के नौजवान रजिस्टर्ड है, यह ग्रामीण क्षेत्र में भर्ती है। इनकी स्थिति यह है कि इन्हें प्रतिदिन 160 रुपये वेतन दिया जाता है, जबकि प्रदेश में अकुशल श्रमिकों को 245 रु0 रोज दिया जाता है। मान्यवर, यह पी0आर0डी0 एक अनुशासित दल है। इनके पास हथियार है और यह ड्रिलमार्च कर सकते हैं और पुलिस बल की मदद कर सकते है। मान्यवर, अगर आप पी0आर0डी0 में नौजवानों की प्रदेश भर के सभी जनपदों में भर्ती करने का कार्य करेंगे तो इससे प्रदेश को लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करें।

श्री मनीष असीजा-

माननीय मंत्री जी, क्या आप इनका मानदेय कम से कम 300 रु0 प्रतिदिन किये जाने पर विचार करेंगे। आप इनकी समय सीमा तय करेंगे। मान्यवर कार्यपालन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो इन्हें मात्र बीस हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या ऐसी दुखःद स्थिति में इन्हें पांच लाख रु0 अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे।

वाह्य सहायतित परियोजना समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण (राज्य मंत्री) (श्री राम करन आर्य)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा तो मेरी बात खुद ही आपने बता दिया शेष मैं बता रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी 1989 में पी0आर0डी0 जवानें का 22 रुपया था जिले में जिनकी ड्यूटी होती थी और जनपद के बाहर जो जाते थे 30 रुपया था और यही होमगार्ड का भी था जो जिले में ड्यूटी करते थे 22 रुपया था और 35 था और अभी आपने जो बात कहा, डिफरेंसी जो हुई है कहीं से आंकड़ा मिल गया होगा मेरे ही विभाग से। यह 66 से बिगड़ गया। आज की जो स्थिति है जिस सम्बन्ध में हम लोग चिन्तित है। मान्यवर, इस समय जो पी0आर0डी0 के जवान जिनकी जिले में ड्यूटी लगती है उनका 160 रुपया है बाहर भी 160 ही है होमगार्ड का जो जिले में ड्यूटी लगती है 200 रुपया है और बाहर जो जाते हैं उनका 210 है। मान्यवर, इस डिफरेंसी के लिये हमने वित्त विभाग को पत्र लिखा है कई पत्र लिखा है। अभी जो अंतिम हमारा पत्र गया है, लेटेस्ट हमारा इसी माह में गया है और वित्त विभाग से आया है थोड़ी कहीं कोई बात रह गयी है दुबारा उसने हमसे मांगा है और वह हमारे विभाग की तरफ से जा रहा है, वह जल्दी ही निस्तारण हो जायेगा। हम चाहते हैं कि इन जवानों का तनख्वाह इनका उतना ही दिया जाय मानदेय जितना होमगार्डों का है जैसा शुरू से अन्त तक है।

मान्यवर, जो आपने बीमा दुर्घटना की बात किया हम उसके लिये चिन्तित है और इसीलिये हमारी मान्यता है हमने जो डिमाण्ड किया है, हमने जो लिखा है कि 5 लाख मरने के बाद और ऐसी स्थिति हो कि मरने के समान ही अपंग हो जाये तो भी 5 लाख, इसके साथ ही साथ एक आंख की हानि हो जाय एक अंग की हानि हो जाय, उसके लिये ढाई लाख, इसके साथ ही साथ ऐसी स्थिति हो कि किसी काम के लायक न हो तो भी हम 5 लाख के लिये लिखत-पढ़त में हम लोग प्रयत्नरत है। हमने बीमा दुर्घटना के बारे में जो आपने कहा हम लोग बीमा कम्पनियों को लिखा है कि हम आपको उसके लिये 13 लाख कुछ हजार रुपये हम दे रहे है आपने जो बीमा की बात किया है उसमें हमारे पास लोगों के प्रस्ताव आये है जिसमें से दुर्घटना के लिये जो 5 लाख की बात किया इन लोगों से हमने मांगा है बीमा दुर्घटना के लिये। जिसमें इंश्योरेंस कम्पनी ने हमको स्वीकृति दे दी है तो मान्यवर, उस सम्बन्ध में भी कार्यवाही चल रही है क्योंकि मैं कोई बिरला के घर का नहीं हूं, मेरे घर का भी कोई बेटा भाई होगा जो पी0आर0डी0 में काम करता है तो जितना आप चिन्तित हैं उतना मैं भी चिन्तित हूं और मेरी समझ से पूरा सदन इसमें चिन्तित है क्योंकि 160 रुपये का कोई महत्व नहीं है यह तत्काल बढ़ोत्तरी के लिये विचाराधीन है।

प्रदेश बजट में उद्योगों को बढ़ावा व विकसित करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

*05-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10433148/2014, जो वर्ष 2014-15 के बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजनाएं तथा विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं एवं औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 बनायी गयी है। उक्त नीति में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक वातावरण में

सुधार, 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0)' को प्रोत्साहन, पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट, मानव शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दक्षता एवं क्षमता विकास, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु विशेष नीतियों का निर्धारण की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ-साथ सड़क परिवहन के लिए विस्तृत कार्य योजना तथा उद्योगो को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ऊर्जा क्षेत्र के विकास को शीर्ष प्राथमिकता में रखा गया है। प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को और अधिक विकसित एवं सुदृढ़ बनाने हेतु 'उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष' का गठन करते हुए वर्ष 2014-15 के बजट में इस प्रयोजनार्थ रु0 500.00 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के मद में वर्ष 2014-15 के बजट में रु0 2680.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नये औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2014-15 के बजट में विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रु0 2070 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

2-सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है जैसे-नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, गीडा, लीडा एवं सीडा। इन प्राधिकरणों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाए उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, गीडा, लीडा और सीडा की स्थापना की गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि इनके अन्तर्गत पिछले दो वर्ष में कितने नये उद्योग लगे है तथा क्या इसमें कुछ मल्टीनेशनल कम्पनियों को भी साथ में लिया गया है। दूसरा प्रश्न, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है या करने पर सरकार विचार कर रही है ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

मान्यवर, इसके अलावा जनपद औरय्या में 127.074 हेक्टेयर भूमि में प्लास्टिक सिटी विकसित की जा रही है। बरेली जनपद की तहसील बहेड़ी में मेगा फूड पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा जनपद आगरा में थीम पार्क योजना प्रस्तावित है। इस तरीके से हम लोग इस दिशा में कार्यवाही करने का काम कर रहे है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त किसी जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है या सरकार विचार कर रही है तो आपने जवाब दिया है कि बरेली में कर रहे है तो यह तो अभी प्रस्तावित है, काम चालू नहीं हुआ है। हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों में दिल्ली जयपुर हाईवे के दोनों तरफ बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं जिनको एन0एच0 जैसी सड़कें एवं नाले आदि की सुविधा, 24 घन्टे बिजली उपलब्ध कराई गयी है इसके अलावा रुड़की के पास भगवानपुर में भी ऐसा किया गया है। हमारा कहना यह है कि हजारों की संख्या में उद्योग वहां लग चुके हैं तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आप औद्योगिक क्षेत्र

स्थापित करेंगे जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उद्योग पलायन न कर सकें, आपकी वहां कोई नई योजना है कि नहीं, यह आता बता दें।

श्री राममूर्ति वर्मा-

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह जो आगरा से लखनऊ हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसमें जो प्रमुख शहर है, जैसे आगरा है, फिरोजाबाद है, इटावा है, कन्नौज है, औरय्या है, कानपुर है, लखनऊ है इसके आसपास के क्षेत्रों को इनसे जोड़ा जा रहा है और जो माननीय सदस्य द्वारा जानने की कोशिश की गयी है, इनको इससे पूरी तरह से बल मिलेगा और इस दिशा में हमारा प्रयास है कि इस एक्सप्रेस वे से हैन्डलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयां, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृह, मन्डी, दुग्ध आदि उद्योगों की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में यह सहायक होगा, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे है।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है, उद्योग यहां से पलायन कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते है कि क्या बरेली में सेज डेवलप करेंगे, आगरा में सेज डेवलप करेंगे, मुरादाबाद में सेज डेवलप करेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि दो कटेगरी के उद्योग हैं, 100 मजदूरों से 500 मजदूरों तक काम करने वाले उद्योग कौन-कौन से लगे हैं और 5 सौ से 1 हजार मजदूर जिसमें काम करते हैं वह उद्योग कौन से लगे है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि 100 मजदूर से 500 मजदूर तक जिस उद्योग में काम करते हों इस उद्योग का नाम बता दें और 5 सौ से 1 हजार मजदूर जिसमें काम करते हों उस फैक्ट्री का नाम बता दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, यह सूचना कहां मंत्री जी के पास होगी।

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी, यह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वेल्ट है हरियाणा से लगती हुई और उत्तराखण्ड से लगती हुई, बिजली में बहुत अन्तर है, यदि एक पेपर मिल का औसत निकाला जाए तो 25 से 30 लाख रुपये का मासिक अन्तर आता है। इतना बड़ा बिजली की दरों में अन्तर है पहले तो यह क्राइसिस है। मैंने सवाल उठाया था कि शामली में जो औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग बन्धु द्वारा भी प्रस्ताव हुआ लेकिन पिछले 12 साल से उसकी सड़क का प्रस्ताव आज तक लटका हुआ है। अभी मैं पिछली बार गया तो डेढ़-डेढ़ फिट पानी वहां औद्योगिक क्षेत्र में भरा हुआ था तो ऐसी स्थिति में कैसे उद्योग चलेंगे। तो मेरा मा0 मंत्री जी से सीधा सवाल है कि जो हरियाणा और उत्तराखण्ड के आसपास का क्षेत्र है उनकी सुविधाओं को देखते हुए क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार की सुविधाएं देने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री राममूर्ति वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार उद्योगों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और हमने इसके लिए बजट में व्यवस्था करने का प्रावधान किया है। बिजली हो या भूमि की उपलब्धता

हो, दस दिशा में भी सरकार ने तमाम राहत देने का काम किया है। मा0 सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमारी नीति 2012 बनाई गई है इसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा विकास पर ध्यान दिया गया है और उद्योगों की स्थापना करने का काम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा है।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैंने शामली का कहा है, एक बार मा0 मंत्री जी से कहलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर देना मा0 मंत्री जी का काम है, इसमें मैं कैसे कहलवा दूं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, एक बार कहलवा दीजिए। मा0 मंत्री जी कह देंगे तो काम हो जायेगा, एक बार शामली के बारे में कह दें। मान्यवर, मैंने नाम लेकर कहा है जरा सा कह देंगे तो काम हो जायेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, शामली का क्वैश्चन है क्या आप उस सड़क को बनवा देंगे, इसका जवाब दिलवा दें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैंने शामली का नाम लेकर कहा है, कृपा हो जायेगी तो काम हो जाएगा। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा विनम्र आग्रह है, आप एक बार मंत्री जी से कहलवा दो, शामली की औद्योगिक क्षेत्र की सड़क बन जायेगी तो कुछ काम तो हो जायेगा। मान्यवर, आप तो हमारे संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी को जो जवाब देना था दे दिया, अब मैं कैसे कह दूं।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं और मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आप उद्योगों की बात कर रहे है अच्छी बात है और उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगे यह भी अच्छी बात है। उद्योगों में कोई नीति ऐसी नहीं बनी है, सबसे ज्यादा शोषण मजदूरों का हो रहा है। हमारा विधान सभा क्षेत्र लगता है हरियाणा से, एक तरफ हरियाणा लगता है एक तरफ राजस्थान लगता है। ताज ट्रिपेजियम जोन के कारण पूरी इण्डस्ट्री हमारे यहां लगी है हरियाणा बार्डर से लेकर यू0पी0 में कोसी के आसपास तक। सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि वहां मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा है। 10-10, 20-20 साल उनको काम करते हो गये फिर भी उनकी हाजिरी ठेकेदार के यहां भरी जाती है और फैक्ट्री/कम्पनी की तरफ से उनको आज तक नहीं लिया गया है। इस पर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मजदूरों का शोषण हो रहा है वह बंद हो और फैक्ट्रियों पर लगाम लगायें और उनको नियमित मजदूरी करने का अधिकार फैक्ट्री की तरफ से हो न कि ठेकदार की तरफ से। तो मान्यवर, इसको मा0 उद्योग मंत्री जी देखें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि एन0एच0-91 पर जो सिकन्द्राबाद इण्डस्ट्रियल एरिया है, वह बहुत पुराना है और वह बिल्कुल ग्रेटर नोयडा और नोयडा से सटा हुआ है, मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या उस इण्डस्ट्रियल एरिया को जो कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की जमीन पर बना हुआ है उसका भी ग्रेटर नोयडा और नोयडा की तर्ज पर विकास किया जायेगा ?

श्री राममूर्ति वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही अवगत कराया है कि अवस्थापना सुविधाओं एवं औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति, 2012 बनायी गयी है और इसमें 2014-2015 के बजट में भारी बजट का प्राविधान किया गया है और जहां-जहां पर भी आवश्यकता होगी उसको निश्चित रूप से सरकार पूरा करने का काम करेगी।

श्री रविन्द्र भडाना-

माननीय अध्यक्ष जी, कृषि के बाद उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है। प्रदेश वास्तव में चिन्तित रहता है कि हमारे यहां प्रदेश में किस प्रकार से उद्योग बढ़े इसके लिए सारा सदन चिन्तित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उद्योग धन्धे पलायन कर रहे हैं वह बहुत चिन्ता का विषय है। खासतौर से मैं सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरठ के अन्दर एक सरकारी कताई मिल वर्षो से बंद पड़ी है, क्या सरकार इसको पुनः चलाने का काम करेगी ? मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, यह उद्योग से संबंधित प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण सरकारी मिल है.....

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए अलग से सवाल लगाना चाहिए था, यह इसमें कैसे आयेगा।

श्री रविन्द्र भडाना-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति खुर्द-बुर्द हो रही है, मिल बेकार पड़ी है उसको चलाने हेतु क्या सरकार विचार करेगी ? दूसरे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर मेरठ में क्या कोई और ऐसा बड़ा उद्योग लगाने का सरकार विचार कर रही है ?

(डा0 मो0 अयूब के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब बैठ जांए।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, उद्योगों से संबंधित मामला बड़ा गम्भीर है। दो प्रश्न इधर से आये, एक सिकन्दराबाद का आया और एक शामली का, लेकिन दोनों प्रश्नों का कोई स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। यह केवल एक किताब लेकर कि एक उद्योग नीति बनायी गयी है तो केवल उससे उद्योगों का बढ़ावा नहीं मिलेगा, इन दोनों प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर आना चाहिए था, जो नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपकी बात ठीक है लेकिन जो वोट डालने के लिए अन्दर हाल में चला जाता है वह वोट डाल करके ही आता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में विगत दो वर्षो के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष-

महाना जी अब बैठिये, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसके ऊपर चर्चा स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

जब बजट आयेगा तो इसके ऊपर जितना चाहे बोल लीजिएगा।

*06-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[2सरे शुक्रवार के तारां0प्र0सं0-04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में नावार्ड द्वारा बेरोजगारों को कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु परियोजना क्रियान्वित का कथित प्रकरण

*07-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाबार्ड योजना द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों को अत्याधुनिक कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु कोई परियोजना क्रियान्वित की जा रही है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नाबार्ड द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में घाटे पर चल रहे सिनेमा हाल को बन्द कर व्यवसायिक जरूरतों के अनुसार उपयोग में लाने की मांग

01-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर के घाटे में चलने वाले सिनेमा हाल बन्द होने के पश्चात अपनी भूमि को बेच नहीं पाते हैं अथवा उसका दूसरा उपयोग नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बन्द पड़े सिनेमा मालिकों को अपनी भूमि को अपनी व्यवसायिक जरूरतों के अनुसार उपयोग में लाने हेतु नये नियम बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अखिलेश यादव-

घाटे में चलने वाले सिनेमा हाल के बन्द होने के पश्चात् भूमि के बेचने पर मनोरंजन कर विभाग द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिनेमा हाल के बन्द होने के पश्चात् दूसरे उपयोग के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-2436/9-आ-3-98-78 काम्प/87 दिनांक 28-08-1998 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार पुराने सिनेमा हाल को तोड़कर उसके स्थान पर व्यवसायिक काम्पलेक्स अथवा किसी अन्य निर्माण के प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा विचार किया जाता है।

जनपद फिरोजाबाद में विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत हेतु धनावंटन करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

02-श्री मनीष असीजा-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत नवीन 700 लाभार्थियों हेतु धनराशि 25,20,000/- (पच्चीस लाख बीस हजार मात्र) का धनावंटन करने विषयक जिलाधिकारी, फिरोजाबाद का पत्र संख्या-334-35/वि0क0/पेंशन/मांग/2013-14, दिनांक 22-7-2013 निदेशक विकलांग कल्याण उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद के सभी 700 नवीन लाभार्थियों के लिए कुल रु0 25,20,000/- की धनराशि जारी की जा चुकी है और यह धनराशि सम्बन्धित लाभार्थियों के खातों में अन्तरित हो चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम बेल्तुआ में मानक के अनुरूप निर्मित सड़क की मरम्मत कार्य की मांग

03-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम-बेल्तुआ, विकास खण्ड-ईसानगर में 3 वर्ष पहले बनी मण्डी परिषद् की सड़क मानक के अनुरूप न बनने के कारण उखड़ कर ध्वस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही करेगी तथा मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्ष 2007-08 में कराया गया था। गांव के अन्दर निर्मित भाग पर जल भराव एवं ट्रैक्टर ट्राली के आवागमन के कारण गड्ढे हो गये हैं। गांव के बाहर निर्मित भाग का लेपन समय अन्तराल के कारण कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता के दृष्टिगत मार्ग की मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में पेंशन सुविधा उपलब्ध सम्बन्धी जानकारी

04-श्री काली चरन सुमन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं कर्मचारियों को पेंशन सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान प्राप्त निजी प्रबंधाधिकरण द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की सेवा शर्तें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती, सेवा शर्ते और अन्य शर्तें) नियमावली-1975 से नियंत्रित है। वित्त विभाग द्वारा प्रख्यापित नई पेंशन नीति के आलोक में भी समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों को सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रदेश के सभी जनपदों में ओलम्पिक साइज के तरणताल बनवाये सम्बन्धी जानकारी

05-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में ''ओलम्पिक साइज'' के ''तरणताल'' (स्वीमिंग पुल) बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

खेल विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 33 तरणताल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की दृष्टि से निर्मित किये जा चुके हैं तथा 05 अन्य जनपदों में निर्माणाधीन हैं। 01 तरणताल ओलम्पिक/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर निर्माणाधीन है।

जनपदों में तरणताल का निर्माण भूमि की उपलब्धता एवं वहां खेल की लोकप्रियता के दृष्टिगत बजटीय प्राविधान उपलब्ध होने पर कराया जाता है।

मण्डी परिषद् उ0 प्र0 में कतिपय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण न कर आउट सोर्सिंग से भरने विषयक पत्र पर कार्यवाही

06-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् उ0 प्र0 में जून, 1991 के उपरान्त नियुक्त नियत, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज एवं मस्टर रोल आदि कर्मचारियों का विनियमितीकरण न कर आउट सोर्सिंग से विभिन्न पदों पर कार्य करने हेतु कर्मचारी नियुक्ति करने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-2-2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 18-02-2014 में वर्णित दिनांक 29 जून, 1991 के उपरान्त नियुक्त/कार्यरत दैनिक वेतन, नियत वेतन, वर्कचार्ज/मस्टर रोल आदि कार्मिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में मण्डी परिषद् के संचालक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विनियमितीकरण पर अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 29-06-1991 के बाद नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज/मस्टर रोल, दैनिक वेतनभोगी आदि कार्मिकों के विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में अभी तक शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जहां तक आउट सोर्सिंग से विभिन्न पदों पर कार्य करने हेतु कर्मचारी नियुक्त करने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्यों हेतु एक वर्ष के लिए कुल 83 कम्प्यूटर आपरेटर आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये हैं। अन्य पदों पर आउटसोर्सिंग से कार्मिक नहीं रखे गये है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनद मेरठ के स्वीमिंग पुल की नींव धसने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

07-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0-10435058/2014 पर दर्ज जो जनपद मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेशन में पांच साल पहले बने स्वीमिंग पुल की नींव धंस गयी इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद मेरठ में तरणताल का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लि0 द्वारा कराया गया था अतएव सन्दर्भित पत्र में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण निदेशक सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को सन्दर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

08-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-54 के अन्तर्गत स्थानान्तरण]

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या एवं उनके पद सृजित कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

09-श्री राधेश्याम-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ में दिनांक 29 जून, 1991 से पूर्व के कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों को दैनिक वेतन विनियमितीकरण नियमावली, 1998 में निहित

व्यवस्थानुसार विनियमित किया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि निदेशालय में पद रिक्त न होने की दशा में उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2063/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08-09-2010 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिसंख्य पद सृजित कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ में वर्तमान में दिनांक 29-06-1991 के पूर्व से 08 दैनिक वेतन भोगी कार्मिक (समूह-'ग') कार्यरत हैं ?

जी हां।

जी नहीं।

समूह 'ग' के 08 दैनिक वेतन भोगी सामान्य वर्ग के कार्मिकों को उद्यान विभाग में रिक्त 24 पदों में से सामान्य वर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष नियमावली के अनुसार समायोजित/विनियमितीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किये जाने हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को शासनादेश संख्या-1513/58-2014-341/2012, दिनांक 23-06-2014 द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र पुरोनिधानित पोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन रिफार्म्स योजनान्तर्गत जनपद फैजाबाद में लाभान्वित किसानों का विवरण

10-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र पुरोनिधानित सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन रिफार्म्स योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद का चयन किया गया है ? यदि हां, तो इस योजनान्तर्गत जनपद के कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा इसकी समयावधि क्या है ? क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

केन्द्र पुरोनिधानित सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजनान्तर्गत जनपद-फैजाबाद में कुल 37039 किसानों को वर्ष 2008-09 से वर्ष 2013-2014 की समयावधि में लाभान्वित किया गया है।

जी हां। लाभार्थी किसानों का सम्पूर्ण विवरण अत्यधिक विस्तृत (लगभग 1800 पृष्ठों का) है। अतएव इसकी सूची मा0 राज्य मंत्री, कृषि के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को पेंशन की सुविधा

11-श्री मनीष असीजा-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मानसिक रूप से विकलांग 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चों के लिये कोई पेंशन की सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार

ऐसे बच्चों के लालन पोषण के लिये उनके अभिभावकों को कोई आर्थिक सहायता दिलवाने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

18 वर्ष से कम आयु के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के गरीब माता-पिता को समाजवादी पेंशन से लाभान्वित किये जाने की योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलों के विकास हेतु ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना का विचार

12-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलों के विकास हेतु ''ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना'' योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

भारत सरकार के स्तर पर ब्लाक स्तर पर स्पोटर्स काम्पलेक्स की योजना प्रस्तावित है। उक्त योजना का पूर्ण स्वरूप आने के पश्चात् राज्य सरकार की ग्रामीण स्टेडियम योजना पर यथोचित विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांग पेंशन का बजट बढ़ाये जाने की मांग

13-श्री मनीष असीजा-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़ी संख्या में विकलांगजन जो कि ''विकलांग पेंशन'' प्राप्त करने की पात्रता रखने के बावजूद भी बजट के अभाव में पेंशन पाने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बजट बढ़ाकर सभी पात्र आवेदकों को विकलांग पेंशन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

नवीन पात्र आवेदकों को विकलांग पेंशन प्रदान करने हेतु प्रति वर्ष बजट में वृद्धि की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में राजकीय कन्या स्नातक विद्यालय खोलने की मांग

14-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में कोई राजकीय कन्या स्नातक विद्यालय खोलने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में 02 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 06 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। इस प्रकार क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद मथुरा में नवनिर्मित उप कृषि मण्डी परिषद् को शीघ्र चालू कराये जाने की मांग

15-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में नवनिर्मित उप कृषि मण्डी परिषद् राया पिछले वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी चालू न होने के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी को शीघ्र चालू कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर बनाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

16-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सीएम/वि0 को0/एम0/पी0 जी0 10435072/2014 जो जनपद मेरठ स्थित कैलाश प्रकाश स्टेशन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का रूप देने तथा दिन-रात मैच खेलने हेतु फ्लड लाइट लगाने व क्रिकेट अकादमी की स्थापना से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अकादमियों की स्थापना विभाग द्वारा नहीं करायी जाती है वरन् सम्बन्धित खेल संघ द्वारा कराया जाता है। जहां तक कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम मेरठ को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का रूप देने तथा दिन-रात मैच खेलने हेतु फ्लड लाईट लगाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आय-व्ययक व्यवस्था न होने के कारण प्रश्नगत मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

17-श्री जय प्रकाश निषाद-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्पसंख्यक बहुल्य जनपदों में नये माडल राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद झांसी को सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

18-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 36 अल्पसंख्यक बाहुल जनपदों में नये मॉडल राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने का निर्णय वित्तीय वर्ष 2013-14 में लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड के जनपद-झांसी को सम्मिलित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में क्या सरकार उक्त महाविद्यालय का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। प्रदेश के न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें अल्पसंख्यक बाहुल्य 05 जनपद सम्मिलित हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में 01 विश्वविद्यालय, 02 राजकीय महाविद्यालय, 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 19 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। इस प्रकार जनपद झांसी में शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः जनपद झांसी में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में किसान दिवस को पुनः चालू कराये जाने की मांग

19-श्री दीपक पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में प्रत्येक माह की 22 तारीख को प्रत्येक जनपदों में पूर्व की भांति संचालित हो रहे किसान दिवस को पुनः प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रत्येक माह की 22 तारीख को संचालित किये जाने वाले किसान दिवस के स्थान पर अब वर्तमान में प्रत्येक माह की तृतीय बुधवार को मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[12.20 बजे] चीनी मिल एसोसियेशन द्वारा मुख्य मंत्री व मुख्य सचिव को दिये पत्र में जबरदस्ती किसानों को गन्ने मूल्य का भुगतान कराने पर अगले सत्र में पेराई नहीं होने देंगे के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बताइए क्या व्यवस्था है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आज पूरा सदन पक्ष और विपक्ष दोनों, बड़ा चिन्तित था गन्ना किसानों के बकायों को लेकर आज ही एक धमकी भरा समाचार पूरे मीडिया में आया है। जो चीनी मिल एसोसिएशन इप्सा के अध्यक्ष है उन्होंने मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा है यदि हमको जबरदस्ती गन्ना भुगतान कराया गया और हमको जिस प्रकार से कोआपरेटिव की फैसिलिटी दी गई है, नहीं दी गई पैसा भुगतान करने के लिए तो हम अगले सत्र में पेराई नहीं करेंगे। इस पर हम जानना चाहते हैं कि क्या यथार्थ है क्योंकि बहुत गम्भीर विषय है। क्योंकि अगर गन्ना किसानों का न भुगतान करने की धमकी दे रहे हैं या आगे चीनी मिल न चलाने की धमकी दे रहे है तो एक गम्भीर विषय मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाकर मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य अपना पक्ष रखे।

श्री अध्यक्ष-

यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है इसलिए यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

सरकार केवल स्थिति बता दें। यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

इसको आप नियमों में उठाएं। अभी बैठ जाएं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

आपने आश्वासन दिया था इसको मैंने नियमों में उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

अखबारों का संज्ञान लिया नहीं जाता मीडिया का संज्ञान लिया नहीं जाता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मैंने कहा कि यह मीडिया में भी आया अखबारों में भी आया। यह गम्भीर विषय है आप सरकार से कह दें वह किसी दिन इस पर बता दें कि क्या ऐसा है। जैसे ही किसानों को पता लगेगा वह और गम्भीर होंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात पूरा सदन सुन रहा है आपकी बात सरकार सुन रही है चूंकि यह मेरे संज्ञान में नहीं है इसलिए इस पर मैं क्या व्यवस्था दे सकता हूं। आप इसको नियमों में लाइए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

आप सरकार को निर्देशित कर दें कि वह बता दें कि क्या ऐसा है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें हम कैसे निर्देश दें जब हमारे संज्ञान में नहीं है।

[12.24 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 26-6-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 46 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गई :-

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में सीवर लाइन तथा एस0टी0पी0 सहित सीवर लाइन का प्रथम चरण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम पावर ऑफ अर्टानी के माध्यम से कब्जा धारकों को सीधे रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

भदौरिया जी वैसे तो बहुत हल्ला मचाते है लेकिन मौके पर नहीं रहते है।

(इसी मध्य श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया उपस्थित हो गए)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, मुझे भूख लगी थी इसलिए कुछ खाने के लिए मैं चला गया था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। तीसरी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर महानगर स्थित छावनी क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण महामारी फैलने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री लोकेन्द्र सिंह की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर जनपद बिजनौर की ग्राम सभा किवाड़ की चीलों की मंडेया से कांठ मार्ग पर रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

पांचवी सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली में बल्दीराय ब्लाक को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अनीसुर्रहमान का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

सातवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज की नदियों में पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली में नरवन क्षेत्र के नरायनपुर पम्प कैनाल को चक्का बांध लिफ्ट जमनियां से सिंचाई हेतु पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

नवीं सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद की नदियों के किनारों पर ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य द्वारा सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई गई)

दसवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री तेजपाल सिंह की जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा के सरकारी चकरोड व तालाब पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री मो0 गाजी की है। (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे)। तेरहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के कैमुआ नाले का चौड़ीकरण एवं नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में व्याप्त विद्युत संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 के अन्तर्गत निर्माण इकाई के उप परियोजना प्रबन्धक के द्वारा किये गये गम्भीर घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। (कई माननीय सदस्यों के अपनी अपनी सूचना लिये जाने का आग्रह करने पर) श्री अनीसुर्रहमान के स्थान पर माननीय सदस्य श्री राजबली जैसल की क्योंकि यह कम देते है और श्री मो0 गाजी की सूचना के स्थान पर माननीय सदस्य श्री राधेलाल रावत, यह भी बहुत कम देते है, की सूचनाएं स्वीकार की जाती है। (माननीय सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा का अपनी सूचना लिये जाने का आग्रह करने पर) आपकी सूचना आज नहीं आई है, कल थी। आप सूचना लिखकर दे देते है और उपस्थित नहीं रहते हैं। इस तरह से सूचना देने का क्या फायदा है। चलिये हो गया। जिन माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार है। श्री सतीश महाना, डा0 अरूण कुमार, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री संत प्रसाद, श्री जय प्रताप सिंह, श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री गोरख पासवान, श्री दलजीत सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री अनिल कुमार, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री बृजेश कुमार, श्री संतराम कुशवाहा, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री दलवीर सिंह, श्री भगवती प्रसाद, श्री अली युसूफ अली, श्री ओम कुमार, श्री जाकिर अली, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री उमेश पाण्डेय, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री रामहेत भारती, श्री उमाशंकर, श्री पंकज मलिक, श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन। माननीय सदस्य जिनकी सूचनाएं स्वीकृत की गई वह पढ़ी हुई मानी गईं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद शाहजहांपुर में सीवर लाइन तथा एस0टी0पी0 सहित सीवर लाइन का प्रथम चरण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 135-शाहजहांपुर में सीवर लाइन पिछले 30 वर्षों से अधूरी पड़ी है। लगभग 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं परन्तु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट न बनने के कारण सीवर लाइन अभी क्रियाशील नहीं हो पायी है। आबादी बढ़ रही है उसके अनुरूप ड्रेनेज सिस्टम तथा सीवरेज सिस्टम होना चाहिए जिसका पूरी तरह से अभाव है। यदि इस सीवर लाइन को शीघ्र क्रियाशील नहीं किया जाता है और एस0टी0पी0 नहीं बनाया जाता है तो जो धन खर्च हो चुका है वह भी बर्बाद हो जायेगा। जनहित में शाहजहांपुर नगर में जो सीवर लाइन बिछी है उसका क्रियाशील होना

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा एस0टी0पी0 बनना आवश्यक है और शेष आधे शहर में जहां पर सीवर लाइन नहीं पड़ी है वहां पर भी सीवर लाइन पड़ना आवश्यक है। अतः हमारी मांग है कि जो अधूरी सीवर लाइन बनी है उसको क्रियाशील करने के लिए जो औपचारिकताएं हों उसको पूरा करके चालू कराया जाय।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि एस0टी0पी0 सहित सीवर लाइन का प्रथम चरण पूरा किया जाय।]

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम पावर ऑफ अर्टानी के माध्यम से कब्जा धारक की सीधे रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[महोदय,

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में गरीब व्यक्तियों हेतु एक कमरे के मकान बनाकर आवंटित किये गये थे। इन मकानों में ज्यादातर मजदूरी करने वाले, सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले एवं अन्य छोटे-छोटे कार्य करने वाले व्यक्तियों को आवंटित किये गये। यह सब लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। कम आमदनी होने के कारण ज्यादातर व्यक्ति इन मकानों का पूर्ण भुगतान नहीं कर पाये जिसके कारण ब्याज पर ब्याज लगकर धनराशि मकान की कीमत से कई गुना ज्यादा हो गयी हैं। इन गरीब व्यक्तियों को इतनी धनराशि का भुगतान करना मुश्किल है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपनी विभिन्न योजनाओं में इस तरीके के बकाया धनराशि के लगभग 30 हजार नोटिस जारी किये हैं। इन मकानों में एक समस्या यह भी है कि इनमें से अधिकतर मकान री-सेल हो चुके हैं। प्रथम आवंटी का कोई पता नहीं है जिस कारण जो भी थोड़ा बहुत पैसा किश्तों का जमा हो रहा है वह प्रथम आवंटी के नाम जमा हो रहा है। इस समय मकान में रहने वाले व्यक्तियों ने प्रथम आवंटी से पॉवर ऑफ अटार्नी अथवा सेल डीड या नोटरी के आधार पर कब्जा ले रखा है। आवंटियों से धनराशि न वसूल कर पाने के कारण सरकार को राजस्व भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल प्रभाव से वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लागू कराने एवं पॉवर ऑफ अटार्नी, सेल डीड, नोटरी के आधार पर कब्जाधारक को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर महानगर स्थित छावनी क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण महामारी फैलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय,

कानपुर महानगर के छावनी क्षेत्र के कोयला नगर, न्यू आजाद नगर, सतबरी रोड, हंसमंदिर के पीछे, सी0ओ0डी0 कालोनी, शिवपुरम्, राधापुरम्, चर्च के पास, स्वर्ण जयंती विहार, मंगला विहार प्रथम एवं द्वितीय, मानस विहार, भवानी नगर, राजपूत नगर, जवाहरपुरम्, रामपुरम्, तुलसीनगर, गिरिजा नगर, गदियाना, चाणक्यपुरी, नेताजी नगर, सुधल्लापुर, सिंघा टटिया, भल्ला टटिया, खेवरा गांव,

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डी-ब्लाक, राजीव नगर, ओम पुरवा, चंद्र नगर, चन्द्रनगर खलवा, पोखरपुरवा, हरियाणा दाल मिल के पीछे, के0डी0ए0 कालोनी, गज्जू पुरवा, शीतलाबाजार, बगाही, बाबू पुरवा, खटिकाना, आजाद नगर, बाकरगंज, बेगमपुरवा, अजीतगंज, चिडीनगर मोहल्ला तथा बाबू पुरवा में श्रमिक कालोनी के पीछे के इलाकों में जल निकासी न होने के कारण नालियां बजबजा रही हैं। नालियां साफ न होने के कारण पानी निकल नहीं पा रहा है। गंदा पानी सड़क पर बहता है। जिस कारण बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

यह लोक महत्व का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र नूरपुर जनपद बिजनौर की ग्राम सभा किवाड़ की चोलों की मंडेयों से कांठ मार्ग पर रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र सिंह-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र नूरपुर जनपद बिजनौर की ग्राम सभा किवाड़ की चोलों की मंडेयों से कड़ूला नदी काठ मार्ग पर यातायात की अत्यधिक समस्या है। रपटा निर्माण न होने से ग्रामवासियों को नूरपुर से काठ जनपद मुरादाबाद जाने में असुविधा होती है। यह मार्ग जनपद बिजनौर को जनपद मुरादाबाद जोड़ने वाला मार्ग है। स्थानीय ग्रामीण इसी मार्ग से होकर मुरादाबाद जाते हैं। रपटा निर्माण कराये जाने हेतु शासन एवं प्रशासन स्तर पर कई बार अनुरोध करने के बाद भी आज तक कार्यवाही नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने भी कई बार स्थानीय प्रशासन से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया और धरना प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों में अत्याधिक रोष व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम सभा किवाड़ की चोलों की मंडेयों से काठ मार्ग पर रपटा निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली में बल्दीराय ब्लाक को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबरार अहमद-

[महोदय,

आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र 187, इसौली जनपद-सुल्तानपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र के तमाम गांव जो मुसाफिरखाना तहसील जनपद-अमेठी के अन्तर्गत थे जहां जनता को आने जाने में सुविधा थी और लोगों को कोई परेशानी नहीं होती थी किन्तु सुल्तानपुर जनपद से मुसाफिरखाना तहसील अलग होने के बाद सभी गांव शहर तहसील सुल्तानपुर से जोड़ दिये गये जिसकी दूरी काफी ज्यादा है इसलिए हमारे क्षेत्र के बल्दीराय, धनपतगंज ब्लाक के लाखों की आबादी की सुविधा के लिए बल्दीराय ब्लाक को तहसील बनाया जाना अति आवश्यक है। तहसील बनाये जाने से क्षेत्रीय नागरिकों को सुविधा मिल जायेगी। तहसील न बनाये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी असंतोष व्याप्त है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मेरा आपसे इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर ध्यान दिलाते हुए बल्दीराय ब्लाक को तहसील बनाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज की नदियों में पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[महोदय,

मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर में जनता को आवागमन में पुलों के अभाव में आने-जाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि बांसी नदी के गौरी घाट पर इसी नदी के पिपराघाट के गोलाघाट तथा इसी बांसी नदी के टी0पी रोड पर पुल न होने के कारण लोगों का आवागमन बाधित रहता है। वर्षाकाल के दौरान नदी में बाढ़ आने पर स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाती है। पुल के अभाव में लोगों का जहां आवागमन बाधित रहता है वहीं कृषि कार्य भी प्रभावित होता है। इससे इस क्षेत्र की गन्ने की फसल पूरी तरह से प्रभावित होती है जिसके कारण गन्ना किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही कभी-कभी गंभीर रूप से बीमार लोगों की चिकित्सा के अभाव में मृत्यु भी हो जाती है। इन स्थानों पर पुल का निर्माण किये जाने हेतु काफी समय से जनता मांग करती रही है। इन स्थानों पर पुल न होने के कारण यहीं के निवासियों में चिन्ता एवं आक्रोश व्याप्त है। इन स्थानों पर सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण कराये जाने हेतु आगणन प्राप्त हो चुका है। आगणन की धनराशि को शासन द्वारा आवंटित किया जाता है। इस संदर्भ में शासन का पत्र सं0-90 नियम/23-10-2012-39 नियम/12 लो0नि0अनुभाग-10, लखनऊ दिनांक 03-12-2012 एवं प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लो0नि0वि0 लखनऊ का पत्रांक-635/मा0 जनप्रतिनिधियों गोरखपुर/सेतु 6/12 दिनांक 16-07-2012 के क्रम में मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0 गोरखपुर के पत्रांक 2978/1 नाबार्ड-गो0दो0/13 दिनांक 27-02-2013 द्वारा उक्त कार्य हेतु आगणन प्रस्तावित कर धन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः जनहित में इन तीनों पुलों को शीघ्र निर्माण कराये जाने के लिए प्राप्त आगणन के आधार पर शीघ्र धन आवंटित करने का कष्ट करें।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्य की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के नरवन क्षेत्र के नारायनपुर पम्प कैनाल को चक्का बांध लिफ्ट जमनियां से सिंचाई हेतु पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद चन्दौली के नरवन क्षेत्र के नारायनपुर पम्प कैनाल से सिंचाई हेतु पानी मिलता है जो नरवन क्षेत्र नारायनपुर पम्प कैनाल से टेल अन्तिम छोर पर है। नरवन क्षेत्र से सटा चक्का बांध लिफ्ट जमनियां है। नरवन क्षेत्र (बरहनी, सैयदराजा) को चक्का बांध जमनियां से सिंचाई हेतु पानी देने के लिये लगभग 35 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी है लेकिन अभी तक

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनहित में उक्त परियोजना को लागू कराने में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः सदन के माध्यम से लोक महत्व एवं अविलम्बनीय के विषय पर सादर अनुरोध है कि नरवन क्षेत्र को चक्का बांध लिफ्ट जमनियां से सिंचाई हेतु पानी देने व परियोजना को चालू कराने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद की नदियों के किनारो पर ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड मिर्जापुर, के ग्राम मौजमपुर से कीलापुर गांव तक रामगंगा नदी भीषण कटान करती है। जिसके कारण गांवों का अस्तित्व खतरे में है ही। साथ ही साथ तमाम अन्य गांव भी खतरे में बने हुए हैं। जिसके कारण ग्राम व क्षेत्र वासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोष व्याप्त है।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान ाकृष्ट कराते हुए ग्राम मौजमपुर से कीलापुर तक राम गंगा के किनारे ठोकरे बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा-

[महोदय,

1-ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम नाहली से ग्राम अमीपुर तक सड़क।

2-ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम ईसापुर से ग्राम भदौला होते हुए ग्राम त्यौड़ी-13 बिस्वा तक सड़क।

3-ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम किल्हौड़ा में बम्बे की पटरी से ग्राम कस्तला तक सड़क।

4-ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम तिबड़ा से ग्राम जहांगीरपुर होते हुए ग्राम अमराला तक सड़क।

5-शहर मोदीनगर में मोहल्ला देवेन्द्रपुरी में मकान नं0 सी-534 राजेन्द्र के मकान से गिन्नी देवी जूनियर हाईस्कूल तक सड़क।

6-ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत हापुड़ रोड पर ग्राम गदाना से मोदीनगर-कलछीना रोड तक बम्बे की पटरी का निर्माण।

7-मोदीनगर से ग्राम सौंदा तक सड़क।

8-ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम शाहजहांपुर से ग्राम हृदयपुर भंडौला तक सड़क।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-गंग नहर निवाड़ी के पुल से ग्राम पूठरी-सुहाना-भनैड़ा मार्ग।

10-ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम ईशाकनगर से ग्राम नाहली तक सड़क।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन से उक्त मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने एवं व्यक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा के सरकारी चकरोड व तालाब पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजपाल सिंह-

[महोदय,

जनपद इलाहाबाद के तहसील मेजा के अन्तर्गत ब्लाक उरूवा के ग्राम औता में तालाब संख्या-1026क तथा इसके दो तरफ सं0-1019 व 1021 सरकारी चकरोड अभिलेख में दर्ज है। उक्त तालाब तथा सरकारी चकरोड पर गांव के शोरेपुस्त लोगों ने उक्त तालाब एवं चकरोड पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से कई बार किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ग्राम वासियों को आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त तालाब एवं चकरोड पर अवैध रूप से कब्जा हटवाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के कैमुआ नाले का चौड़ीकरण एवं नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय,

कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जिला-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर अत्यन्त पुराना सकरा पुल अत्यन्त जर्जर/क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जो कि कभी भी गिर सकता है। उक्त पुल के जर्जर होने के कारण क्षेत्रीय वासियों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता में हमेशा किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। उक्त पुराने पुल के अत्यन्त छोटा एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय राहगीरों के साथ आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन तथा सरकार से शाहजहांपुर बीसलपुर राज्य मार्ग पर निगोही के पास कैमुआ नाला पर पुराना जर्जर/क्षतिग्रस्त सकरा पुल का यथाशीघ्र नवनिर्माण कराये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक पुल निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का कैमुआ नाला पर पुल बनवाये जाने हेतु ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में व्याप्त विद्युत संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड-ईसा नगर के अन्तर्गत ग्राम खमरिया पंडित में विद्युत आपूर्ति की दशा अत्यन्त दयनीय है। यहां पर सब विद्युत पावर स्टेशन नहीं होने से क्षेत्र में विद्युत सप्लाई अक्सर बाधित रहती है। क्षेत्रीय जनता ने कई बार उक्त ग्राम में एक सब पावर विद्युत स्टेशन स्थापित किये जाने का अनुरोध स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से किया है परन्तु अभी तक पावर स्टेशन निर्माण हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 के अन्तर्गत निर्माण इकाई के उप परियोजना प्रबन्धक के द्वारा किये गये घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[अवगत कराना चाहूंगा जनपद-जौनपुर उत्तर प्रदेश सेतु निगम लि0 के अन्तर्गत निर्माण जौनपुर में जनहित को नजरन्दाज करके सेतु निगम द्वारा निर्मित व निर्माणाधीन सेतु में मानक व गुणवत्ता को प्रभावित करके आमजन के जीवन से खिलवाड़ करते रहते है। उप प्रबन्ध परियोजन प्रबन्धक द्वारा 3.5 करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें उनको दि0 22-03-13 को निलम्बित किया गया। ईकाई के उप परियोजना प्रबन्धक के द्वारा भारी पैमाने पर किया जा रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 के अन्तर्गत निर्माण ईकाई के उप परियोजना प्रबन्धक के द्वारा किये गये गम्भीर घोटालों की जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के कतिपय ब्लाकों में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेलाल रावत-

[महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के अन्तर्गत निम्नलिखितत अति क्षतिग्रस्त मार्गों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :-

1-ब्लाक नवाबगंज में सोहरामऊ से गोरिन्दा मार्ग तक सड़क की अति जर्जर हालत,

2-ब्लाक नवाबगंज में बल्ला फार्म से कटेहल मार्ग तक की सड़क की अति जर्जर हालत,

---

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-ब्लाक नवाबगंज में अजमैन से बीर सिंह मार्ग तक की सड़क की अति जर्जर हालत,

4-ब्लाक हसनगंज में नवई से मदनापुर नरायनपुर तक निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग,

5-ब्लाक औरास में शाहपुर तोदा से बयारी गांव तक के सम्पर्क मार्ग की जर्जर हालत।

उक्त ब्लाकों में अर्धनिर्मित टूटी फूटी सड़कों के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिससे वहां के निवासियों में अत्यन्त रोष व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड माण्डा अन्तर्गत ग्राम सभा मझिगवा का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना है कि मेरे जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोराव के विकास खण्ड माण्डा अन्तर्गत ग्राम सभा मझिगवा का विद्युतीकरण देश के इतने दिन आजादी के बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया है। जिससे ग्राम सभा एवं समस्त मजरों के लोगों को आज भी अंधरे में रहना पड़ता है। उक्त ग्राम सभा में विद्युतीकरण न होने से लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ विज्ञान के युग में भी लोगों को टेलीविजन एवं मोबाइल जैसे चीजों का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उक्त ग्राम सभा में विद्युतीकरण न हो पाने से समस्त ग्राम सभा के लोगों में आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युतीकरण कराने एवं कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

[12.29 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

[आज दिनांक 26 जून, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 5 सूचनाएं प्राप्त हुईं और पांचों अस्वीकार हुईं। पहली सूचना श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत की जनपद उन्नाव में अधिकारियों द्वारा जन शिकायतों पर समुचित एवं प्रारम्भिक कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न हुए गम्भीर मामलों के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन में क्षेत्रीय विधायक की राय न लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की कोठियों की भूमि पर अवैध कब्जे, बन्द पड़े नलकूपों एवं जनपद गोण्डा के अन्तर्गत एल्गिन ब्रिज चरसंडी तटबन्ध के बाढ़ कार्य हेतु हुए अनुबन्ध घोटाला विषयक सूचनाओं के सम्बन्ध में जान बूझकर जानकारी न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की लोक सभा के सदस्यों के समान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों को मिलने वाले वेतन भत्ता आदि सुविधाओं को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री रामहेत भारती की प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप कोटा पूरा किये जाने के सम्बन्ध में है। यह सभी सूचनाएं अस्वीकार हुईं।]

[12.30 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 131वां (एक सौ इकतीसवां) प्रतिवेदन

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 131वां (एक सौ इकतीसवां) प्रतिवेदन जो महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, नगर विकास, लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा, गृह तथा बेसिक शिक्षा विभागों के वर्ष 1991 से वर्ष 2012 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का तृतीय प्रतिवेदन

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित आबकारी विभाग तथा कर एवं निबन्धन (स्टाम्प रजिस्ट्रेशन) विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

[12.32 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का चतुर्थ प्रतिवेदन

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-14) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित गृह (पुलिस) विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

[12.33 बजे] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अजय कपूर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन जो नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन निकाय नगर पालिका परिषद्, मथुरा से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री अजय कपूर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का द्वितीय प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष (1999-2000) में उल्लिखित ग्राम्य विकास विभाग के अधीन क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का तृतीय प्रतिवेदन

श्री अजय कपूर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का तृतीय प्रतिवेदन जो मण्डी समिति, गोरखपुर द्वारा ग्राम-पटना, विकास खण्ड-बड़हलगंज, तहसील गोला, जनपद-गोरखपुर में एक मार्ग का निर्माण दिखाकर लगभग 23 लाख रुपये का अनियमित व्यय किये जाने विषयक श्री कल्पनाथ सिंह, पूर्व सदस्य, विधान सभा, गोरखपुर के शिकायती-पत्र पर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग से प्राप्त आख्या पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री अजय कपूर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013-2014) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन निकाय-सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), जौनपुर तथा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

[12.35 बजे] जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत पुरदिल नगर मुख्य सड़क से ग्राम शंकरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बृज बिहारी कौशिक आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत पुरदिल नगर मुख्य सड़क से ग्राम शंकरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बृज बिहारी कौशिक व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत जरेरा चौराहे से ग्राम नगला वीर सहाय तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नवीन पाराशर आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत जरेरा चौराहे से ग्राम नगला वीर सहाय तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नवीन पाराशर व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम पिछोती से ग्राम धुबई होते हुए सिकन्दराराऊ-हसायन मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री आरिफ अली बेग आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम पिछोती से ग्राम धुबई होते हुए सिकन्दराराऊ-हसायन मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री आरिफ अली बेग व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[12.37 बजे] जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर राजमार्ग पर निगोही के पास कैमुआ नाले पर पुराना जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पुल का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री जितेन्द्र गुप्ता आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर राजमार्ग पर निगोही के पास कैमुआ नाले पर पुराना जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पुल का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री जितेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम जहांनपुर से ग्राम नेकापुर तक की क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सड़क का जनहित में निर्माण एवं डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री उमेश यादव आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम जहांनपुर से ग्राम नेकापुर तक की क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सड़क का जनहित में निर्माण एवं डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री उमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[12.38 बजे] जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा विद्यापुर-बखरवा में मोदीनगर विद्यापुर मार्ग पर स्थित गन्दे नाले के टूटे हुये पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगपाल आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा विद्यापुर-बखरवा में मोदीनगर विद्यापुर मार्ग पर स्थित गन्दे नाले के टूटे हुये पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगपाल व मास्टर ओमपाल सिंह निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद गाजियाबाद में विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा त्योड़ी-13 विस्वा में इदरीश के मकान से ग्राम तलहटा तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शहजादा प्रधान आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद में विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा त्योड़ी-13 विस्वा में इदरीश के मकान से ग्राम तलहटा तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शहजादा प्रधान व श्री ताहिर निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[12.39 बजे] जनपद मथुरा के राया बाईपास का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निर्माण कराये जाने विषयक श्री मानसिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मथुरा के राया बाईपास का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निर्माण कराये जाने विषयक श्री मानसिंह व श्री वीरपाल सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के महुअन टोल टैक्स पर स्थानीय निवासियों का आवागमन निःशुल्क कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मथुरा के महुअन टोल टैक्स पर स्थानीय निवासियों का आवागमन निःशुल्क कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह व श्री भीम सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[12.40 बजे] जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के विकास खण्ड रूधौली के अन्तर्गत ग्राम कुड़ी से सेहुडा होते हुये नकहा जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मधुसूदन यादव आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के विकास खण्ड रूधौली के अन्तर्गत ग्राम कुड़ी से सेहुडा होते हुये नकहा जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मधुसूदन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के विकास-खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पिरैला नरहरिया में सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 जर्रार आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के विकास-खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पिरैला नरहरिया में सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 जर्रार व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

[12.41 बजे] जनपद मोदी नगर में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के मजदूरों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में संसदीय समिति का गठन

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 16 में कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना सदन को देनी है।

विधान सभा के दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 के उपवेशन में मा0 सदस्यगण श्री सुदेश शर्मा, श्री त्रिलोकीराम तथा श्री तेजपाल सिंह द्वारा विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में अभिसूचित सूचना पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने अपना मत व्यक्त किया था कि इस सम्बन्ध में यदि कोई समिति बनाने की आवश्यकता है तो मा0 अध्यक्ष को इस हेतु अधिकृत कर दिया जाय या जिस भी तरीके से बेहतर हल निकल सकता हो, निकाला जाय।

तद्नुसार मोदीनगर में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के मजदूरों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में जांच, अन्वेषण तथा प्रतिवेदन हेतु एक संसदीय समिति गठित किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि सदन सहमत हो तो इसकी जांच हेतु संसदीय समिति गठित कर दी जाये। सदन सहमत है ?

(सभी मा0 सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की।)

श्री अध्यक्ष-

सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18 में कुछ नहीं है।

[12.42 बजे] उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014†

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 8-7-2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[12.43] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

अब नियम-56 की सूचना है। मा0 सदस्यगण, आज साधारण चर्चा का आखिरी दिन है। इसलिए इसमें बहुत से मा0 सदस्य हैं जो बोलने के लिए बच गये हैं तो इसमें जितने आये हैं, हर मा0 सदस्य का महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको शिथिल करते हुए हमने दो-तीन सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए ले लिया है। मा0 सदस्यों से हम अनुरोध करेंगे कि बहुत से मा0 सदस्य जनरल डिबेट में भाग नहीं ले पाये है। वह अपनी बात कह लें। क्योंकि तीन बजे मा0 मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। उसके पहले नेता विरोधी दल भी आधा घण्टा, पन्द्रह मिनट या जो भी समय लेना चाहें।

तो अभी हम लोगों के पास दो घण्टा समय बच रहा है, तो इस दो घण्टे में हम कम से कम 10-12 मा0 सदस्य जो बोलने के इच्छुक हैं, उन्हें हम बोलवा देंगे, इसलिए सभी मा0 सदस्यों से जिन्होंने नियम-56 में सूचनाएं दी हैं, अनुरोध करते है कि आज इसको स्थगित कर दें, तीन सूचनायें हमने ले ली है, उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है और आगे जरूरत होगी, तो आगे के दिनों में देंगे जिससे कि हम उस पर चर्चा करा सकें। जो तीन हमने लिया है उसमें पहली सूचना श्री रवि शर्मा की जनपद बुन्देलखण्ड में हो रहे अवैध खनन एवं गुण्डा टैक्स की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर मैंने शासन का ध्यानाकर्षण कर दिया।

दूसरी सूचना श्री सुदेश शर्मा की प्रदेश के अस्पतालों में 24 घण्टे में एक ही शिफ्ट में पोस्टमार्टम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर मैंने शासन का ध्यानाकर्षण कर दिया है।

तीसरी सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जिला हाथरस की तहसील सादाबाद में वर्ष 2010-11 में बनी पानी की टंकियों को चालू न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर भी मैंने शासन का ध्यानाकर्षण कर दिया है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं :-

1-श्री प्रदीप माथुर, श्री दिलनवाज खां, श्री अजय कुमार 'लल्लू', 2-डा0 धर्मपाल सिंह, 3-श्री सतीश महान, 4-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 5-श्री धर्मपाल सिंह, 6-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, 7-श्री रामचन्द्र यादव, 8-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, 9-श्री इन्द्र पाल सिंह, 10-श्री तेजपाल सिंह, श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट', 11-श्री अगयश राम सरन वर्मा, 12-श्री संजय प्रताप जायसवाल, 13-श्री उमाशंकर, 14-श्री रामहेत भारती, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, 15-श्री रोशन लाल वर्मा, 16-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज।

अब बजट पर चर्चा प्रारम्भ की जाय।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है उस पर कुछ नहीं बोलना है, मेरा एक निवेदन है जो श्री सुदेश शर्मा जी की सूचना पर आपने शासन का ध्यानाकर्षण किया है, तो उसको कल आप नियम-56 में ले लें, उसके ऊपर चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

जब उनकी सूचना को आज हमने ले लिया और शासन का ध्यानाकर्षण कर दिया तो कल कैसे उसको फिर लिया जायेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप इसे कल ले लें, यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, अब बजट पर चर्चा प्रारम्भ।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मेरी सूचना को भी आप कल ले लीजिएगा।

[12.44 बजे] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अध्यक्ष-

अब बजट पर चर्चा प्रारम्भ, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' पहले अपनी बात रख दें, यह नई सदस्य हैं, इसके बाद श्रीमती रजनी तिवारी। पहले महिलाओं को बोल लेने दीजिए। अराधना मिश्रा जी, पांच मिनट का समय है, इसमें आप अपनी बात रख दें।

*श्रीमती अराधना मिश्र 'मोना'-

मान्यवर, मैं प्रयास करूंगी कि निर्धारित समयावधि में अपनी पूरी बात रख दूं। माननीय अध्यक्ष जी देश के सबसे बड़े प्रदेश की इस पंचायत में मुझे पहली बार चुनकर आने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा का देश में एक स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास है, मेरा सौभाग्य है मा0 अध्यक्ष जी मैं पहली बार बोलने जा रही हूं आपकी अनुमति से इसलिए आदरणीय अध्यक्ष मैं आपके प्रति सबसे पहले पूरा सम्मान एवं आदर व्यक्त करती हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 नेता विरोधी दल सभी दलों के मा0 नेता एवं मंत्रि-मण्डल के सभी सम्मानित मंत्रीगण विधान सभा के सभी मा0 सदस्यों को मैं सादर प्रणाम करती हूं, मैं आप सभी के समक्ष पहली बार बोलने जा रही हूं यदि कोई कमी हो तो अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। मा0 अध्यक्ष जी, आज महिलाओं की आबादी इस प्रदेश में 50 प्रतिशत की है, इस देश की कई महत्वपूर्ण और ख्याति प्राप्त महिलाएं इस उत्तर प्रदेश से गई हैं, आज जब महिलाओं पर अत्याचार की खबर सुनने को मिलती है तो बहुत कष्ट होता है। मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में इस वक्त मौजूद नहीं हैं, पर मैं यह संज्ञान दिलाना चाहती हूं कि इसी सदन में समाजवादी नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने महिला प्रधान बजट रखा था और मा0 अध्यक्ष जी उस समय सम्भवतः आप मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी थे। आदरणीय श्री आजम खां जी, मा0 श्री शिवपाल जी, मा0 श्री अम्बिका चौधरी जी आप सब मंत्री रहे होंगे उस वक्त, मैं उनकी दूरदर्शिता को जो उन्होंने सोचा था उसका मैं बहुत सम्मान करती हूं और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि इस बात पर चर्चा करना कि महिलाओं पर किस तरह से उनका शोषण हो रहा है इस बात पर चर्चा करना कि उनके प्रति कितने अपराध हो रहे हैं, उनकी संख्या देना आंकड़े देना ये इस सदन में मैंने सुना पर मेरा अपना विचार है कि अगर महिलाओं को सशक्त बनाया जायेगा, उनको आत्मनिर्भर बनाया जायेगा, उनको अपने पैरो पर खड़ा किया जायेगा, तो महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न अपने आप कम हो जायेंगे। मेरा एक सुझाव है जो भारत के संविधान और मा0 उच्च न्यायालय के अनुरूप होगा। जिस वर्ग में आरक्षण है उसको बिना घटाये और बढ़ाये जो 33 प्रतिशत आरक्षण की बात हो रही है। मैं यह नहीं कहती कि उसको 33 प्रतिशत दिया जाये। जो भी विचार कर लें 30 प्रतिशत, 25 प्रतिशत जो आरक्षण हो सके, उस आरक्षण में महिलाओं को, उसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाये ताकि उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इस पर मा0 मुख्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह विचार करें। इसके लिये न तो किसी अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, न ही

---

† दिनांक 23 जून, 2014 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसाधन की आवश्यकता है, केवल एक राजनैतिक दृढ़ता की आवश्यकता है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो वित्त मंत्री के रूप में प्रयास किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। कुछ सीमित संसाधनों की वजह से कुछ जगहों पर उतनी प्रमुखता और प्राथमिकता नहीं मिल पायी। मैं उनकी तरफ अपना सुझाव रखना चाहती हूं। हमारे युवा मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं मा0 पीठ के माध्यम से कि युवाओं के भविष्य को खास प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे उनके हाथों को रोजगार मिल सके और उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बन सके। पर रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार लाने के लिये हमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो शान्त वातावरण दूसरा सस्ती नहीं पर निरंतर बिजली आपूर्ति की जरूरत है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो आगरा समिट में और दिल्ली समिट में पहल की है मैं उसका स्वागत करती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि उत्तराखण्ड जाने के बाद हमारे पास हाइड्रो पावर की कोई गुंजाइश नहीं बची। आज हम थर्मल पावर पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में निर्भर हैं। अगले 5 वर्षों में हमारी प्राथमिकता बिजली की आपूर्ति की होनी चाहिये। इसी प्रकार केंद्रित होनी चाहिये, सर्वोच्च प्राथमिकता बिजली उत्पादन को देनी चाहिए। जहां से भी मिल सके, जैसे भी मिल सके, हमें बिजली की आपूर्ति पूरी करनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली होगी तो फिर बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिल सकेगा। अधिक पूंजीनिवेश हो सकेगा और बेरोजगारी का समाधान हो सकेगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख होता है जब उद्योग लगने लगते है, बिजली की परियोजनायें लगने लगती हैं और उसमें अड़ंगे डाले जाते हैं। यह हमारा उत्तर प्रदेश है आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें राजनैतिक रूप से एक होना पड़ेगा। जहां भी उद्योग लगें, बिजली की परियोजनायें लगें वहां कम से कम विरोध होना चाहिये। मैं आपसे एक बहुत छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूं। मैं नई-नई चुनकर आयी हूं, मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र है रामपुर खास। इसके बारे में छोटी सी चीज कहना चाहती हूं कि पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत गरीब क्षेत्र है और वहां किसान पानी की समस्या से बहुत ग्रसित है। वहां पर एक लिफ्ट कैनाल की आवश्यकता है मैं अनुरोध करूंगी आपसे, मा0 मुख्य मंत्री जी से कि उसको स्वीकार करें। पिछली बार मा0 मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने त्वरित योजना शुरू की थी, आर्थिक विकास योजना शुरू की थी। उसी योजना से हमारे यहां भी बहुत सारी सड़कें बनीं। ऊसर सुधार योजना से बनीं, मण्डी परिषद् से बनीं। पर आज पिछले पांच, छः वर्षों से धन के अभाव से उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है और उनकी मरम्मत नहीं करायी गयी, जल्द नहीं करायी गयी तो ये सड़कें समाप्त हो जायेंगी। इससे जनता को भी परेशानी होगी और प्रदेश को भी क्षति होगी। इसके लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाये ताकि मार्गों की मरम्मत हो सके। अन्त में मैं एक आग्रह करना चाहती हूं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से, वह नहीं है लेकिन आप सब वरिष्ठ हैं। आप मेरा संदेश उन तक जरूर पहुंचा दीजियेगा कि जब से अच्छे दिन वाली सरकार आयी है तो कुछ अच्छा होता तो नजर नहीं आ रहा है, पर हां कुछ न कुछ अप्रिय घटना रोज सुनाई दे रही है। सूखे ने भी दस्तक दे दी है। पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। नलों में पहले पानी जहां पर होता था, आज वहां कीचड़ निकल रहा है। यह मेरी ही समस्या नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह शायद इस सदन में बैठे सभी सदस्यों की समस्या है, मैं अनुरोध करती हूं कि कम से कम विधायकों को 100-100 हैण्डपम्प जरूर दे दिये जायें ताकि प्यासी जनता को पानी मिल सके। यही मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। मैं पहली बार अनुरोध कर रही हूं मेरा अनुरोध स्वीकार किया जाये, आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

कल तक तो कोई बोलने वाले थे नहीं, जब मैं खोज रहा था बोलने वालों को इस समय सभी आ गए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी आपने बजट के समर्थन में जो मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कल शाम को मैं चाहता था कि बोलें तब आपकी सरकारी बेंचों के थे ही नहीं, अब आज थोड़ा समय बचा है तो सब बोलने के लिए तैयार हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, समाज के कमजोर, शोषित, पीड़ित बेसहारा और असहाय लोगों को इस बजट से बहुत सी आशाएं बधीं हैं, जो समाज के सबसे पिछड़े लोग थे। उनको उनका हक दिलाने के लिए इस बजट में बहुत सी योजनायें प्रदेश की सरकार ने लागू करने के लिए अपनी बात कही है, जो समाज के सबसे ज्यादा कमजोर लोग हैं, जो वृद्ध हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको पेंशन मिलने का काम होगा 1613 करोड़ रुपये में। जो समाज की कमजोर निराश्रित विधवा महिलायें हैं, उनको इस बजट के माध्यम से पेंशन मिलने का काम होगा, जो समाज की उपेक्षित महिलायें है, उनके लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है। उसके माध्यम से पूरे प्रदेश के 40 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन मिलने का काम होगा। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनको आज तक कोई सहारा नहीं मिला है, जो लोग झुग्गी और झोपड़ी में, नाले के किनारे, खुले आकाश के नीचे, फुटपाथ पर रहते हैं, उनको आसरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार अवस्थापना के ऊपर 49 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। हर गांव में, हर गली में, हर मुहल्ले में लोगों को विकास का काम दिखायी पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश की सरकार ने 24 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। मा0 अध्यक्ष जी, उसके बाद शिक्षा की समस्या है, उसका हल करने के लिए.....

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप अपने क्षेत्र की बात बता दें, जिससे अधिक से अधिक लोग बोल पायें। जनरल बजट पर तो मुख्य मंत्री जी बोलेंगे ही। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बोल दीजिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहनी है आज देश का वह काला दिन है आज से 39 साल पहले इस देश में आज के ही दिन आपातकाल लगाया गया था और उस पूरे आपातकाल में यह पूरा देश जेलखाना बना दिया गया था। बजट के माध्यम से जो लोकतंत्र के सेनानी हैं, जिनको प्रदेश की सरकार ने 3 हजार रुपये मासिक सम्मान राशि देने की घोषणा करने काम किया था। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि यह सम्मान की राशि बढ़ायी जाये। यह केवल पैसे और सम्मान की बात नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, आपने खुद आपातकाल में 20 महीने जेल में काटने का काम किया था, पूरा देश जेलखाना बन गया था। इस विधान सभा के अन्दर सिर्फ एक पक्ष

के लोक बैठते थे, दूसरा पक्ष खाली था। पूरे देश में बर्बर, क्रूर और जालिम तरीके से जुल्म और अन्याय करने की सारी सीमायें तोड़ने का काम किया था। हमारे सामने बैठे हुये हैं प्रतिपक्ष के उन्होंने भाषण में अपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के बजट का प्रावधान नहीं किया है। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकतंत्र के सेनानियों के लिए उनको सम्मान प्रदान करने के लिये पेंशन की योजना लागू की थी, 31 मार्च, 2007 मान्यवर, जब बी0एस0पी0 की सरकार आयी तो उसने इस पेंशन योजना को समाप्त कर दिया और वह पांच साल तक बन्द रही। उसके बाद जब पुनः हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तो तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना लागू की गयी है। मान्यवर, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पेंशन योजना को दस हजार रुपये प्रति माह किया जाये और सुविधायें बढ़ाई जायें। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि उस लोकतंत्र बहाली की लड़ाई में, जो आजादी के बाद दूसरी सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जनेश्वर मिश्र जी, लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण जी, चौधरी चरण सिंह जी, राजनारायण जी, मधुलिमये जी ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था और उस आपातकाल के समय में बीस माह तक जेलों में बन्द रहे। मैं भी पूरे बीस महीने जेल में बन्द रहा। वहां एक घण्टे की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। मेरा यह भी अनुरोध है कि इस पेंशन-व्यवस्था को और सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए विधान सभा से एक एक्ट पास कराया जाय, ताकि कोई भी सरकार सत्ता में आये वह इन लोकतंत्र के सेनानियों की पेंशन व अन्य सुविधाओं को समाप्त न कर सके। धन्यवाद।

श्रीमती रजनी तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे 2013-14 के बजट पर हो रही साधारण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। मान्यवर, इस पूरे बजट को पढ़ने के बाद उसके अवलोकन के बाद और किसी निष्कर्ष पर पहुचने से ऐसा लगा कि जैसे जली हुई सब्जी को गार्निश करके परोस दिया गया हो। माननीय मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकतायें उनकी आवश्यक योजनायें इसमें दिखाई नहीं दीं। मान्यवर, पूर्ण बहुमत प्राप्त करके यह सरकार सत्ता में आई है और उसने जो घोषणायें की थीं चाहे वह बेरोजगारी भत्ता हो, लैप-टाप, टेबलेट का वितरण हो, कन्या विद्या धन देने की बात हो या साड़ी कम्बल के वितरण की बात हो उन योजनाओं से सरकार ने हटने का काम किया है। ऐसा लगता है कि सरकार को यह योजनायें लाभ नहीं पहुंचा पाईं और अच्छी नहीं लगीं इसलिए उसका प्राविधान इसमें नहीं किया गया है। श्रीमन् मान्यवर, सरकार को अपनी यह योजनायें ही अनावश्यक लगी हैं। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कानून-व्यवस्था की बात आती है। सबसे पहले यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की हालात बहुत खराब है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है कि जब भी यह कमजोर होती है तो उसकी सबसे पहले शिकार यह महिलायें ही होती हैं। मान्यवर, इससे पहले हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था इतनी अच्छी थी और वह इसलिए थी कि यहां पर हमारी माननीया मुख्य मंत्री मायावती जी का शासन था। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर, इस बजट में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र की बालिकायें आज शहरों में उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आती है और उन्हें यहां रहने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, तो मेरी मांग है कि हर शहर में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए छात्रावास बनवाये जायें यह अति आवश्यक है। मान्यवर, सरकार ने बजट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जायेगा और प्रत्येक वर्ष में कितने बेरोजगरों को रोजगार दिया जायेगा। मान्यवर, बजट की राशि को समता के

आधार पर समान व्यय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि वोट के आधार पर। होता यह है कि सरकार की योजनाओं का अधिकतर लाभ सत्तापक्ष के लोगों को मिलता है, जबकि विपक्ष या अन्य दलों के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 5 नदियां बहती हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण मेरा क्षेत्र कई भागों में विभाजित हो गया है उसके लिए मेरे क्षेत्र में अर्जुनपुर और बड़ागांव के मध्य राम गंगा नदी पर पुल के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। इसमें कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं कई बार इस मुख्य आवश्यकता को मैंने यहां उठाया भी है और जब इसका जवाब आया तो उसमें कहा गया, मुझे अवगत कराया गया कि उक्त पुल के स्थान पर राम गंगा नदी में बेड़ीजोर में पक्के पुल का निर्माण किया जायेगा मान्यवर, आप ही बताइये कि जहां पर 30 वर्षो से जिस स्थान पर पैन्टून पुल बन रहा है आज भी वहां पैन्टून बना हुआ है उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर पुल स्थानान्तरित करना क्या न्यायोचित है। मान्यवर, बेड़ीजोर का पुल बन जाय उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बेड़ीजोन का पुल बनने से सिर्फ 10 गांव लाभान्वित होते हैं और अर्जुनपुर के पुल बनने से सैकड़ों गांव लाभान्वित होते हैं उस पुल के बनने से हमारे क्षेत्र को तो लाभ होगा ही, सैकड़ों गांवों को लाभ होगा ही, हरदोई जनपद और फर्रूखाबाद जनपद दो जनपदों को लाभ होगा मान्यवर, हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस पुल की उपयोगिता को देखते सरकार इस पर आवश्यक विचार करे।

†श्री प्रभूदयाल बाल्मीकि-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभरी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2014-2015 के उत्तर प्रदेश के बजट भाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट किसान और मजदूरों का बजट है, नौजवानों का बजट है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए विकास की अनेकों योजनाएं चलाने का इसमें प्राविधान किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो स्थानीय निकायों में अपनी पुरानी सरकार में, 2003 की सरकार में 60 हजार सफाई मजदूरों की भर्ती करके गरीब मजदूर और दलितों के लिए ऐतिहासिक काम किया वही इस बार माननीय नगर विकास मंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने 2012 की सरकार में 40 हजार सफाई मजदूरों की भर्ती करने की घोषणा की। माननीय अध्यक्ष जी, जहां सफाई मजदूरों की भर्ती करने की घोषणा की है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय नगर विकास मंत्री जी का और यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने जहां ठेके पर काम करने वाले लोगों को 100 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाकर ढाई सो रुपया प्रतिदिन मजदूरी करने का काम किया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मान्यवर, उन्हीं सफाई कर्मियों में संविदा सफाई कर्मी जो आपने पिछली बार भर्ती किये थे उनकी भी मजदूरी बढ़ाने का काम करेंगे तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में गंगा नदी का पुल है और यह गंगा नदी का पुल दो विधान सभाओं को जोड़ने का काम करता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस गंगा नदी के पुल को जो चेता घाट के नाम से जाना जाता है इस पुल को बनवाने का काम करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय नगर विकास मंत्री ने रिक्शा चालाकों के लिए सौर ऊर्जा बैटरी का रिक्शा देने का काम किया है उससे अनेकों मजदूरों को लाभ मिला है। मान्यवर,

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हस्तिनापुर की धरती महाभारत काल की धरती भगवान श्रीकृष्ण की धरती है और इस धरती को पर्यटन विभाग से जोड़ा जाय। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट किसानों, मजदूरों का बजट है और नौजवानों का बजट है और इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनेकानेक योजनायें चलाकर गरीबों को, मजदूरों को, किसानों और दलितों के हित में एक ऐतिहासिक काम किया है माननीय अध्यक्ष जी, आपकी कृपा रहेगी आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कालेज की भी आपके माध्यम से मांग करता हूं और बजट भाषण का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। और बजट भाषण का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सीमा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं। अध्यक्ष जी, हम आपके प्रति आभारी इसलिए भी हैं कि कल हमने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आपने आज माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं के ऊपर बड़ी कृपा की है, इसके लिए भी हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का या यूं कह लीजिए कि इस पूर्ण बहुमत सरकार का यह तीसरा बजट है और इस बजट में पिछले साल के बजट से 24 प्रतिशत ज्यादा धनराशि की व्यवस्था की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है कि जब हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, जब गांव में प्रचार की गाड़ियां आती थीं तो प्रचार हुआ करता था रोटी, कपड़ा और मकान। मुझे लगता है कि तब खाली एक ही समस्या थी रोटी, कपड़ा और मकान की। लेकिन आज की तारीख में तमाम समस्यायें हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं, पर्यावरण की समस्या अलग है, बेरोजगारी की समस्या अलग है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या अलग है, भ्रष्टाचार की समस्या अलग है, तमाम समस्यायें आज की तारीख में हमारे सामने खड़ी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कोई हो, जनता की उम्मीद होती है कि सरकार आयेगी और कुछ ऐसा कार्य करेगी जिससे जनता को लाभ होगा। मान्यवर, हम उस पर नहीं जाते, सारे विद्वान विधायकगण यहां बैठे हुए हैं। सब अपने-अपने क्षेत्र की बात करेंगे, हम भी अपने क्षेत्र की तीन-चार बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार के बजट में अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं गया है तो वह सड़क के लिए गया है, टूटी-फूटी रोडों के लिए गया है, नयी रोडों के लिए गया है। अध्यक्ष जी, आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं और हम सभी पूर्वांचलवासियों का यह सौभाग्य है कि आप पूर्वांचल के हैं। मान्यवर, जो पूर्वांचल विकास निधि हम सबको प्राप्त होती है, आज के कुछ साल पहले पूर्वांचल विकास निधि का काम हम किसी भी कार्यदायी संस्था को देते थे, वह काम कराती थी। लेकिन अभी पिछले दो बार से ऐसा कोई आदेश हो गया है कि पूर्वांचल विकास निधि का काम खाली पी0डब्लू0डी0 तथा आर0ई0एस0 ही करेंगे। मान्यवर, इससे बहुत व्यवहारिक कठिनायी है। हम गांव के रहने वाले हैं किसी गांव में जाते हैं, कही 200 मी0 खड़न्जे की आवश्यकता है, कहीं 100 मीटर नाली की आवश्यकता है। कहीं 150 मी0 खड़न्जे की आवश्यकता है तो पी0डब्लू0डी0 उसका निर्माण नहीं करती और आर0ई0ए0 उसको नहीं बनाती। इन छोटे-छोटे कामों को कराने के लिए हमें और भी कार्यदायी संस्थायें चाहिए जो कि पहले काम करती थीं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस बार जब पूर्वांचल विकास निधि जाये तो उसके साथ-साथ वह आदेश जरूर होना चाहिए कि आर0ई0एस0 और पी0डब्लू0डी0

की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि पी0डब्लू0डी0 का अपना मानक है। गांव में जहां छोटे-छोटे मार्ग हैं, जहां 2 मीटर का मार्ग है, वहां 6 मी0 का खड़ण्जा नहीं बन सकता और पी0डब्लू0डी0 खड़ण्जा बनाती भी नहीं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाय और जैसा पहले था वैसा ही किया जाय।

मान्यवर, दूसरी बात बिजली की आती है, बिजली की समस्या से सब त्रस्त हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर है, वहां की समस्या अनन्त हैं। कोई विधायक ऐसा नहीं होगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यह बता दें कि उसके क्षेत्र में बिजली ज्यादा आती है। हम अध्यक्ष जी, 12-13 घण्टे ही लाइट की मांग करते हैं, लेकिन लाइट आने का समय तो ठीक होना चाहिए। आप लोगों के क्षेत्र में क्या आता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे क्षेत्र में दोपहर ढाई बजे लाइट आती है और शाम को 8 बजे चली जाती है, उसके बाद रात को भोर में सवा चार बजे लाइट आती है और 8 बजे सुबह फिर लाइट चली जाती है। हमारे क्षेत्र के लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि आखिर यह बिजली की कौन सी व्यवस्था है, कि जब आदमी सोने को हो, जब खेती करने का वक्त आये, जब काम करने का वक्त आये, तब बिजली न हो, यह सवेरे चार बजे लाइट आने का क्या औचित्य है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो हमारी लाइट की व्यवस्था दो बजे से 8 बजे तक है और भोर में चार बजे से लेकर 8 बजे तक है इसका समय बदलकर मान्यवर, सुबह दिन में 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे और रात्रि में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट की व्यवस्था अगर हो जाय तो क्षेत्र की जनता की समस्या का थोड़ा समाधान हो जायेगा।

(इस समय 01 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से कहना, चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में 35 के0वी0ए0 के दो पावर हाउस हैं एक सुजानगंज में, एक मुंगरा बादशाहपुर में। सुजानगंज से भी 4 फीडर निकलते हैं और मुंगरा-बादशाहपुर से भी 4 फीडर निकलते हैं। लेकिन जो मेन पावर हाउस है उसका जो ट्रांसफारमर लगा है, उसकी क्षमता 5 एम0वी0ए0 है। 5 एम0वी0ए0 से चार फीडर नहीं चलाये जा सकते। इसी वित्तीय वर्ष में जो आपने बजट प्रस्तुत किया है हमारे दोनों ब्लाकों मुंगरा बादशाहपुर और सुजानगंज में 5 एम0वी0ए0 को हटाकर यदि 8 एम0वी0ए0 कर दिया जाता है तो हमारे क्षेत्र के जो चार फीडर हैं वह सुचारु रूप से चलने लग जायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मा0 मंत्री जी बैठे हैं मैं उनका सम्मान करती हूं उनकी ईमानदारी और कर्मठता में कहीं कोई प्रश्नचिह्न नहीं है। मान्यवर, हम भी जौनपुर में रहते हैं हमारे जनपद जौनपुर में 9 विधान सभा क्षेत्र हैं 7 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं सातों विधायकों को आपने 8-8 गांव लोहिया के दिये हैं। मान्यवर, नाम किसका है लोहिया का, लोहिया किसी के नहीं थे उनका न कोई अपना था न पराया था जिनके नाम पर आपने लोहिया समग्र ग्राम की स्थापना की है उनके नाम को बदनाम न होने दीजिये। 7 विधान सभा क्षेत्रों में तो आपने दिया मान्यवर, क्या मेरा यही कसूर है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक हूं क्या यह मेरे क्षेत्र में नहीं हो सकता था, इस विसंगति को मा0 अध्यक्ष जी आप अपने स्तर से दूर करें। विधायक इस सदन का सदस्य है चाहे वह किसी भी दल का हो, ठीक है जिसकी सरकार होती है अपने को ज्यादा पैसा देते हैं, आप उनको 7 दे दीजिये लेकिन कम से कम हमको दो तो देना चाहिए या चार तो देना चाहिए, यह मेरी पीड़ा है, इस बजट में ऐसी व्यवस्था की गयी है इसको भी निर्देशित कर दें कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो। मान्यवर, सिंचाई के सम्बन्ध में मैं

कहना चाहती हूं, मा0 मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, शारदा सहायक खण्ड-39 आज हमारे क्षेत्र में बन्द है, सिंचाई नहीं हो रही है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, बिजली नहीं आ रही है, नहरों में पानी है नहीं आखिर मान्यवर धान की रोपाई कैसे की जाये, शारदा सहायक खण्उ-39 में एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहां पानी की व्यवस्था की जाये। मा0 अध्यक्ष जी, हमारा जनपद जौनपुर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ऐसे प्रदेश के सबसे बड़े जिले के जिला चिकित्सालय में आज की तारीख में भी सी0टी0 स्कैन की मशीन नहीं है आप कल्पना कर सकते हैं कि यहां के मरीजों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। हमारा जनपद प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, साहित्य, संगीत, पढ़ाई-लिखाई, सामाजिक जीवन के मामले में हमारे जनपद का बहुत ऊंचा स्थान रहा है, जौनपुर जिला अस्पताल जो शहीद उमानाथ चिकित्सालय के नाम से है उसमें सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था इसी बजट में जरूर कर दी जाये ताकि वहां के लोगों को इलाज कराने में कोई परेशानी न हो। मान्यवर, हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत अच्छी योजना है। जब प्रधानमंत्री योजना से रोड बनती है तो बहुत खुशी होती है, इसका अपना एक मानक है, अपनी अलग उपयोगिता है और यदि इसमें खराबी आयेगी तो ठेकेदार उसे दूर करायेगा। सिर्फ दो साल की रोड है मुंगरा बादशाहपुर से नीभापुर होते हुए जंघई, इस बात की शिकायत मैंने कई बार की, अपनी मीटिंगों में की डी0एम0 ने भी कहा कि संस्था को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाये, इसने काम अच्छा नहीं किया लेकिन काई कार्यवाही नहीं हुई, आप अपने स्तर से इस रोड की जांच करा लें। अगर दो साल में पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड की यह दुर्गति है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा संदेश नहीं जायेगा। आप इसकी जांच करा लें और अगर यह रोड समय से पहले टूटी है तो जिसकी भी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये और यह रोड अविलम्ब ठीक करायी जाये। मछलीशहर से बेलवार, सरांय काशी सम्पर्क मार्ग, भिखारीपुर से सरांयबीका सम्पर्क मार्ग, यह तीन सम्पर्क मार्ग हमारे यहां ऐसे हैं जिन पर आप पैदल नहीं चल सकते हैं, हम आपके माध्यम से इसे ठीक कराने की मांग करते हैं। जो बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम बुराई करें। आपने अच्छा काम भी किया है ट्रांसफारमर के सम्बन्ध में, जो ट्रांसफारमर पहले लाइन लगाने के बाद भी नहीं मिलता था आज ट्रांसफारमर की कोई कमी नहीं है जब भी ट्रांसफारमर जल जाता है तो तुरन्त मिल जाता है, इसकी हम प्रशंसा करना चाहते हैं। मान्यवर, आपको खुश होना चाहिए, हम विपक्ष के लोग कुछ कहते हैं तो हम आपको बताते हैं आप उन्हे देखिये। मान्यवर, रि-बोर के सम्बन्ध में कहना है, नये हैण्डपम्प तो मिले नहीं लेकिन आज की तारीख में हम अपने जिले की बात बता रहे हैं एक भी रि-बोर हम नहीं करा सकते क्योंकि विभाग कहता है कि रि-बोर कराने के लिए हमारे पास एक पैसा नहीं है। हमने अधिकारियों से पूछा कि आपने डिमाण्ड किया कि नहीं, अधिकारियों ने कहा कि मैंने शासन को कई बार अवगत कराया है। लेकिन शासन से कोई पैसा अभी तक मिल नहीं पाया है।

श्री अधिष्ठाता-

सीमा जी, अब समाप्त करें।

श्रीमती सीमा-

किसान दुर्घटना बीमा की राशि आपने बढ़ा दी, उसके लिए बधाई देती हूं। हमारे क्षेत्र में सगारी में अभी 9 महीने पहले एक नौजवान की मृत्यु हो गयी उसकी विधवा है शशि प्रभा, सगारी गांव

की रहने वाली है, 9 महीना गुजर गये लेकिन आज तक उसको किसान दुर्घटना बीमा का पैसा नहीं मिल पाया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करिये। श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, जौनपुर।

श्रीमती सीमा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मुख्य मंत्री जी के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी सर्वत्र चर्चा है। अच्छे विद्वान, अच्छे अर्थशास्त्री, अच्छे किसान, अच्छे वकील इन सबों ने एक स्वर से इस बजट का स्वागत किया है, उसकी वजह है कि लोगों की कठिनाइयों को, उनकी रोजमर्रा की चीजों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का इस बजट में टैक्स नहीं लगाया गया, यह अनुपम चीज है। इस बढ़ती हुई मंहगाई में इसका होना बहुत जरूरी था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में कोई लोक-लुभावन चीजों का जिक्र नहीं था लेकिन लोगों के विकास पर फोकस किया गया है। चाहे वह पावर सेक्टर हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इन सबों का उचित एलोकेशन हुआ है। इसमें औद्योगिक क्षेत्रों, ग्रामीण एवं शहरी विकास का पूरा का पूरा ध्यान दिया गया है। इस बजट में चाहे चिकित्सीय क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो उसमें काफी धन दिया गया है। ला-एण्ड-आर्डर को सुधारने के लिये 12,400 करोड़ रुपया दे करके यह संदेश है कि लॉ एण्ड आर्डर अच्छे ढंग से चल रहा है और अच्छे ढंग से चलेगा। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। अब रही बात सड़कों की तो सड़क पर भी बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। आशा है कि पूरे प्रदेश के हर जनपद फोरलेन से जुड़ेंगे। हमारे यहां 22-23 कि0मी0 सिंगिल लेन की सड़क है उसमें 15.50 कि0मी0 का चौड़ीकरण होना है। मैं यह विश्वास करता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में सुजानगंज और मछलीशहर का अवशेष भाग मड़ियाहूं-जलालपुर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाये यह इस बजट में जुड़ जाता है तो मुख्य मंत्री जी बजट में चार चांद लग जायेंगे। बेसिक शिक्षा में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने हर विधायक को एक पत्र लिखा था कि आप जा करके अपने क्षेत्रों में अध्यापकों, विद्यालयों को चेक करें लेकिन लोग यहां भाषण जरूर देते हैं, बड़े जोर से भाषण देते हैं कि यह कमी है, यह नाकामियां हैं इसको दूर किया जाये लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि मैं फलां स्कूल में गया था या हमारे मंत्री जी को इस तरह का कोई पत्र दिया हो। विरोध-विरोध के लिए नहीं होता है बल्कि हकीकत को बयां करना चाहिए। विधायक का जो दायित्व था, मैं विद्यालय जिस दिन गया था मैंने मंत्री जी को सूचित किया था, अधिकारियों को सूचना दिया था उसमें सुधार हुआ था। मैं इसी के साथ हमारी कुछ समस्यायें हैं इस बजट भाषण में अगर वह सब सुविधायें जोड़ दी जाती हैं तो निश्चित रूप से बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण का पुरजोर ढंग से स्वागत होगा हमारी विधान सभा जफराबाद दो विशाल नदियों के मध्य अवस्थित है सई एवं गोमती उसमें पेयजल की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भीषण समस्या है सोच रहा हूं कि पेयजल के लिए अच्छी व्यवस्था है पुनः अगर ज्यादा हो जायेगी जो निश्चित रूप से इसे और अच्छा माना जायेगा मैं ज्यादा वक्त नहीं जाया करना चाहूंगा और पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण का पुरजोर समर्थन करते हुए आशा करता हूं कि और लोग भी इसका समर्थन करेंगे।

*श्री सुरेश बंसल-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे वर्ष 2014-15 के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद जो उद्योग में उत्तर प्रदेश में दूसरे नम्बर का जनपद है और राज्य सरकार को राजस्व की सबसे ज्यादा आय मेरे जनपद से प्राप्त होती है किन्तु मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में जहां की आबादी अत्याधिक अधिक है और शहर का एक हिस्सा विजय नगर क्षेत्र जहां की आबादी लगभग 5 लाख से ऊपर है वहां की जनता को गाजियाबाद शहर जाने के लिए रेलवे लाइन पर बने अण्डर पास जो काफी गहरा व सकरा बना हुआ है, से जाना पड़ता है इसका मुख्य कारण प्रायः जाम लगा रहता है तथा बरसात के दिनों में तो पानी भर जाने से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है तथा दूसरा रास्ता लालकुआं से होकर जाता है यदि इस रास्ते से शहर जाते हैं तो लगभग 6 कि0मी0 अधिक का सफर तय करना पड़ता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए यहां के निवासियों व मेरे प्रयास से रेलवे प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में 100 करोड़ रुपये का स्टीमेट कोट गांव रेलवे फाटक पर एक रेलवे ओवरब्रिज जो धोबी घाट तक बनाया जाना था तैयार किया गया रेलवे ने धन जमा करने के लिए राज्य सरकार को स्टीमेट दिया था जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा वर्ष 2012-13 व 2013-14 में सदन की बैठक में अपने बजट भाषणों में इस रेलवे ओवरब्रिज को बनाये जाने हेतु प्रस्ताव रखा था इन्हीं वर्षों में जिला योजना की बैठकों में भी प्रभारी मा0 नगर विकास मंत्री मो0 आजम खां जी से भी अनुरोध किया गया और सभी जनप्रतिनिधियों ने दलीय भावना से ऊपर उठकर मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया एवं मा0 मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करायेंगे। वर्तमान में उत्तर रेलवे ने वर्तमान इस्टीमेट का 50 प्रतिशत हिस्सा रेलवे द्वारा वहन किये जाने और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा जमा कराये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। उपरोक्त क्षेत्र औद्योगिक नगरी है और मलिन बस्तियां व कमजोर वर्ग के विजय नगर निवासियों को मुख्य शहर से जोड़ने व छात्र-छात्राओं के आवागमन को देखते हुए उक्त ओवरब्रिज का बनाया जाना अति आवश्यक है। कृपया 2014-15 के इस बजट में प्राविधान कराये जाने हेतु अनुरोध करता हूं। इस वर्ष स्वास्थ्य व चिकित्सा के बजट में यह प्राविधान है कि एक लाख से ऊपर की आबादी पर सामु0 स्वा0 केन्द्र बनेंगे परन्तु मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के विजयनगर में जिसकी आबादी 5 लाख से अधिक है यहां पर सिर्फ एक प्राथमिक हेल्थ सेन्टर है आपसे विजयनगर क्षेत्र में जनहित में एक सामु0 स्वा0 केन्द्र बनाये जाने का अनुरोध करता हूं जिससे कि वहां के गरीब कमजोर दलित वर्ग के लोगों को मुफ्त व उचित इलाज मिल सके। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि होम्योपैथिक पद्धति जो एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसमें बहुत से लाइलाज रोगों का निदान इस पद्धति से हुआ है तथा यह पद्धति सस्ती भी है परन्तु इस वर्ष के बजट में इस पद्धति के लिए कोई धन का आवंटन नहीं किया गया है। कृपया इसकी भी व्यवस्था कराएं। बजट में मलिन बस्तियों व अल्पसंख्यक समाज की बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए 375 करोड़ रुपये का प्राविधान है। यह राशि बहुत कम है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र विजयनगर के नगर निगम के वार्ड नं0 3 जो क्रिश्चयन नगर बागू, इन्द्र कालोनी लठमार कालोनी सिद्धार्थ बिहार आदर्श कालोनी बिहारी पुरा सुदामापुरी में सीवर लाइन नहीं है यह पूरा वार्ड मलिन बस्ती में आता है। इसी प्रकार वार्ड सं0 23 डूण्डा हैडा, सैन बिहारी शान्ती नगर महाराणा विहार भीमनगर में से सिर्फ एक कालोनी भीमनगर में ही सीवर लाइन है। परन्तु उपरोक्त सभी कालोनियों में पानी की लाइन नहीं है। एक कालोनी डूण्डा हेडा को छोड़कर बाकी सब मलिन बस्ती हैं। इसी प्रकार वार्ड नं0 6 में अकबरपुर, बहरामपुर, राहुल बिहार बौद्ध बिहार संदीप इन्क्लेव, संदीप गार्डेन इस पूरे वार्ड में न तो सीवर की लाइन न ही पानी की लाइन है। उपरोक्त तीनों वार्डों की आबादी एक लाख से ऊपर है। यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन कालोनियों में सीवर की लाइन व पानी की लाइन डलवाने की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध करता हूं। मेरे क्षेत्र का कैला भट्टा जो कि अल्पसंख्यक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जिसकी आबादी लगभग डेढ़ लाख है, यहां पर अधिकांश गरीब लोग रहते हैं इस मुस्लिम बाहुल्य आबादी के लिए शादी विवाह के लिए कोई भी सामुदायिक केन्द्र नहीं है जबकि पूर्व में नवम्बर 2013 में नगर निगम द्वारा एक प्रस्ताव इस्लाम नगर कैला भट्टा में कम्युनिटी सेन्टर के निर्माण हेतु बनाया गया था जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं मानीय मुख्य मंत्री जी की योजनाओं की कद्र करते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कैला भट्टा में एक कम्युनिटी सेन्टर बनाये जाने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

बंसल जी, अब समाप्त करिये। एक तो यह पढ़ने की परम्परा नहीं है। अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश बंसल-

मान्यवर, बस दो मिनट में खत्म करता हूं। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र जिसमें 30 प्रतिशत के गरीब मलिन बस्तियों में गरीब अल्पसंख्यक व अनुसूचित वर्ग के लोग रहते हैं यहां पर शिक्षा के लिए कोई भी राजकीय, माध्यमिक व उच्च शिक्षा हेतु लड़कों का कोई भी विद्यालय नहीं है जिससे यहां के छात्राओं को एडमिशन न मिलने के अभाव में शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। जबकि सरकार की प्राथमिकता अनिवार्य शिक्षा दिलाना है जिससे समाज का उत्थान हो सके।

श्री अधिष्ठाता-

बंसल जी आप समाप्त करें। हाशमी साहब आप अपनी बात कहें।

श्री सुरेश बंसल-

इन गरीब छात्रों के हित को देखते हुए कृपया वर्तमान बजट में इस क्षेत्र में छात्रों के लिए माध्यमिक व उच्च शिक्षा हेतु राजकीय विद्यालय खुलवाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, आपने हमको 2014-15 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतने बड़े बजट की व्यवस्था की है मान्यवर, जो इससे पहले इस सूबे में कभी नहीं की गयी थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस बल को मजबूत करने के लिए जो धन 23928 करोड़ रुपये दिये गये हैं मान्यवर, यह सराहनीय है। नेता विरोधी दल द्वारा कानून व्यवस्था का बार-बार सवाल उठाया गया है लेकिन मान्यवर, हम उन्हें स्मरण कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहराइच में धन्नीडीह में कानून व्यवस्था तार-तार करके और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के साथ बदसलूकी की गयी थी। यही नहीं मान्यवर, लखीमपुर खीरी में एक लड़की के साथ जो घटना घटी और उसको मार करके थाने में ही डाल दिया गया। दूसरी घटना हमें याद आती है कि सीतापुर जनपद में एक माननीय मंत्री जी के यहां जो फोर्स तैनात थी, उसने ए0टी0एम0 की तिजोरी काटकर के चोरी कर ली। ऐसी उत्तर प्रदेश में हजारों घटनाएं हैं मान्यवर, उस सरकार की, जहां गरीब कराह रहा था उसकी आवाज दबा दी जाती थी सिर्फ उदंडवश कि यहां कोई बोलने वाला नहीं है। मान्यवर, इस बजट पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 359 करोड़ गांव के शौचालय के लिए, समाजवादी पेंशन योजना के लिए, उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए 2424 करोड़, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा में सुधार के लिए 14377 करोड़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग और अल्पसंख्यकों के लिए 25522 करोड़ रुपये गन्ना किसानों के लिए 400 करोड़ रुपये मान्यवर, गांव की सड़कों पी0एम0जे0एस0वाई0 के लिए 2593 करोड़ रुपये, इंदिरा आवास के लिए 188 करोड़ ग्रामीण पेयजल के लिए 1598 करोड़ की व्यवस्था की है मान्यवर, यही नहीं मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र में किसान को पेंशन योजना के लिए व्यवस्था निराश्रित विधवाओं के लिए व्यवस्था, विकलांगों के लिए व्यवस्था की गयी है। अधिवक्ताओं के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। पंचायती राज के लिए बहुत बड़े धन की व्यवस्था की गयी मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था सहकारिता कार्य के लिए कृषि समितियों के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था। मत्स्य पालन के लिये सिंचाई योजनाओं के लिये 7587 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। डा0 राम मनोहर लोहिया नलकूप पुनर्निर्माण योजना में 356 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, सड़कों के सुदृढ़ीकरण और बनाने के लिये 15100 करोड़ की व्यवस्था जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने के लिये 656 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, अकलियतों के लिये मान्यवर, 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के लिये, उच्च शिक्षा के लिये, चिकित्सा शिक्षा के लिये बहुत बड़े धन की व्यवस्था की गयी है। पिछली सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी और इण्टरमीडिएट की मान्यता पाने के लिये और उच्च शिक्षा में सम्बद्धता के लिये खुलेआम इसी सचिवालय में मान्यवर, जो उस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने भारी मात्रा में रिश्वत ले करके गरीबों के स्कूलों को मान्यता दी है। मान्यवर, मैं उसकी सीमा नहीं बता पा रहा हूं, उस सरकार के मंत्रियों ने मान्यवर, एन0आर0एच0एम0 का करोड़ों-करोड़ों रुपये लूट लिया, उत्तर प्रदेश का करोड़ों-करोड़ों रुपया लूट लिया। उत्तर प्रदेश के आबकारी में उत्तर प्रदेश के खनन में मान्यवर, एक सिंडीकेट बना करके इन्होंने उत्तर प्रदेश का खजाना लूटने का काम किया और ये लोग समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम की योजना बना रहे हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल और बहुजन समाज पार्टी के लोग तथा अन्य विरोधी दलों के लोग यह साबित नहीं कर सकते कि शिक्षा विभाग में चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, एन0ओ0सी0 के लिये या सम्बद्धता के लिये उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को एक पैसा भी रिश्वत समाजवादी पार्टी की सरकार में देनी पड़ रही है। इसलिये मान्यवर, यह जो बजट मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा रखा गया है, अद्वितीय है और उत्तर

प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिये यह बहुत काफी है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी और संवरेगी और अन्त में मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, उतरौला विधान सभा क्षेत्र में जिला मुख्यालय बलरामपुर से सड़क बहुत जर्जर है, इसको बनाये जाने की आवश्यकता है और बलरामपुर से सिद्धार्थ नगर तक राप्ती नदी की बाढ़ से पूरा क्षेत्र जलप्लावित हो जाता है, लोग बहुत परेशान होते हैं, इसके बन्धों का निर्माण कराना बहुत जरूरी है। आपने हमें बोलने का मौका दिया, मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण का और रखे गये बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। शुक्रिया।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2014 और 15 के बजट पर बोलने का मौका दिया है, आपको धन्यवाद, मैं अपने प्रतिपक्ष के नेता के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सच बात है कि जितना पैसा बजट में रखा गया है यदि ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अन्दर जिन-जिन कार्यों के लिये जिन-जिन विभागों के जिन-जिन कार्यों के लिये बजट निर्धारित किया गया है, यदि वह धरातल पर, जमीन पर यदि लग जाए तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास हो जायेगा। लेकिन स्थिति यह है कि बजट चाहे जितना बड़ा बना लिया जायेगा, योजना चाहे जितनी अच्छी बना ली जाए, हम सब लोग धरातल की राजनीति करने के बाद इस विधान सभा के अन्दर पहुंचे हैं। धरातल की स्थिति परिस्थिति को हम सब लोग जानते हैं और यह भी मानना है कि विपक्ष में बैठने के बाद मैंने कभी नहीं देखा है कि सत्ता पक्ष के बजट के समर्थन की बात विपक्ष के लोग करते हों कटौती की बात हमेशा विपक्ष करता है लेकिन यह सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाएं चलायीं, यह मानते हुए कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा, बेरोजगारी भत्ता आपने दिया, लैपटाप दिया, आपने टैबलेट देने का काम किया और यह सारी योजनाएं आपने दीं, लेकिन उसके बावजूद यह क्या स्थिति, परिस्थिति बनी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर से आपका सूपड़ा साफ हुआ है। मुझे लगता है कि सपा-बसपा के लोगों में इस बात की होड़ मची है कि अगर पिछली सरकार में वहां के स्थानीय विधायक और मंत्री ने दो हजार करोड़ रुपये कमाये हैं तो हम इस बार चार हजार करोड़ रुपये कमाने की व्यवस्था करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जो बसपा की सरकार में हुआ उसमें और आपकी सरकार में कोई अन्तर नहीं है। पहले जिले बिकते थे तो आज भी जिले बिकते हैं, पहले थाने बिकते हैं तो आज भी थाने बिकते हैं पहले पुलिस चौकी बिकती थी तो आज भी चौकी बिक रही है। कोई अन्तर नहीं आया है। पहले अगर आय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये, विकलांग प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये कोई गरीब आदमी एप्लीकेशन देता है तो जब तक लेखपाल को सुविधा शुल्क न मिल जाये वह उस पर अपनी रिपोर्ट नहीं लगाता है। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक आपकी ऐसी स्थिति बनी है। अभी प्रदूषण से सम्बन्धित पर्यावरण बोर्ड से सम्बन्धित विषय चल रहा था। उत्तर प्रदेश के अन्दर सैकड़ों स्लाटर हाउस को आपने अनुमति दे दी और आप सबको मालूम है कि जो एन0ओ0सी0 दी जाती है वह किस प्रकार दी जाती है। आज स्थिति यह है कि मेरी विधान सभा के अन्दर आवश्यकता इस बात की थी कि 314 गांव हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक भी लघु उद्योग या कोई बड़ा उद्योग नहीं है, आपने कटान घर के लिये 1500 पशु काटने के लिये तो आपने उद्योग लगवा दिया लेकिन आपको आवश्यकता नहीं हुयी कि कोई गन्ना चीनी मिल वहां पर लगवा दी जाये। जो पहले से प्रस्तावित है जमीन खरीदी हुयी है तो आपने चीनी मिल लगवाने के बजाये वहां कटानघर लगवाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारी सदस्य ने कहा था कि अगर

आप 12 घण्टे भी लाइट दे देंगे तो उसमें भी गांव-शहर का आदमी संतुष्ट हो सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि बिजली का तार टूटे हुए चार दिन हो जाते हैं लेकिन उसको ठीक करने वाला नहीं आता। ट्रांसफार्मर 8-10 दिन तक फुंका पड़ा रहता है लेकिन उसको ठीक करने वाला नही आता है। इसलिये गांव के अन्दर 8-10 दिन तक बिजली नहीं होती है। इससे सरकार का संदेश गलत जाता है। जब सरकार का गलत संदेश जाता है तो वही स्थिति होती है जो लोक सभा के चुनाव में आपकी हुयी है। आज बैंकों के अन्दर पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार है। किसानों का क्रेडिट कार्ड तब तक नहीं बनता है जब तक बैंकों के अन्दर सुविधाशुल्क न दिया जाये। जब तक बैंक के मैनेजर को सुविधाशुल्क न दे दिया जाये तब तक वह कार्ड रिनेवल नहीं होता है। चाहे आप जितना बजट दे दीजिये काम चलने वाला नहीं है। जब तक बुनियादी ढांचे को आप ठीक नहीं करेंगे। मैं पहली बार विधायक बना तो मुझे लगा कि मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा। चाहे वह पी0एम0जी0एस0वाई0 हो पी0डब्ल्यू0डी हो, गन्ना विभाग हो, मण्डी परिषद् हो, चाहे मण्डी समिति हो या कोई भी विभाग हो।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें। बस समाप्त करें।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह डेढ़ करोड़ रुपये हमें क्षेत्र के विकास के लिये देते हैं और उसमें भी 25 लाख रुपये के लिये आपने कह दिया कि जो क्षेत्र के अन्दर बीमार होगा, मरीज होगा, उसकी बीमारी के लिये दीजिये। अरे एक-एक बीमारी ऐसी है कि जिसमें 25-25 लाख रुपये खर्च होते हैं। किन्तु उसका समाधान नहीं होता। मा0 मुख्य मंत्री जी आप अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं और हमारे साथ भी स्थिति यह कर दी है कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति हो गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही है।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

आपके विभाग के बारे में भी मैं बताऊंगा और प्रूफ सहित बताऊंगा कि आपके विभाग की स्थिति क्या है।

श्री शंखलाल मांझी-

सरकार ने जिम्मेदारी से हटने का काम नहीं किया है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं की है।

(मा0 सदस्य श्री लोकेन्द्र सिंह जी और मा0 मंत्री श्री शंखलाल मांझी जी एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई और किसी की भी बात स्पष्ट नहीं हो सकी।)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य लोकेन्द्र सिंह जी अब आप समाप्त करें मा0 सदस्य मदन चौहान जी आप शुरू करें।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

हम लोग आपस में लड़ते हैं, इसीलिये तो आई0पी0एस0 देश का मौजमस्ती कर रहा है, हमको पांच वर्षों में फिर यही परीक्षा देनी है और पांच वर्षों में हम परीक्षा देंगे और परीक्षा देने की स्थिति यह है कि टोपी भी जनता चेक करती है। इसलिये अधिष्ठाता महोदय कहना चाहूंगा कि यह बुनियादी चीजें ठीक होनी चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री मदन चौहान-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने 2014-15 के बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बजट का मतलब, बजट का आशय एक प्रदेश का विकास होना और जिस जनता के द्वारा हम चुनकर आते हैं इस विधान सभा में उनको राहत देने से सम्बन्ध रखता हो। मान्यवर, बजट अगर सम्बन्धित है गरीब से, कमजोर से, किसान से, रिक्शावाले से और वह बजट उसको लाभ देता है और उसमें बहुत सारी आशायें होती हैं, गरीब की भी आशा जुड़ी है, महिला की भी आशा जुड़ी है, कमजोर की भी आशा जुड़ी है तो उसी प्रकार का बजट मैं इस बजट के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में उन सब बिन्दुओं को छुआ गया है जिनकी बहुत नितान्त आवश्यकता थी, जिनको पूर्व में छोड़ दिया गया था, जब वंचित थे वह बिन्दु मान्यवर, यह बजट 2014-15 का जो 274704 का है वह 2013-14 के बजट से 24 परसेण्ट अधिक है। इसका मतलब बजट में बढ़ोत्तरी हुई है उसी में ही 2957 करोड़ की नई योजनाएं हैं तो वह किसी न किसी को तो लाभ देंगी, किसी न किसी को तो फायदा करेंगी उससे हमारे प्रदेश का विकास होगा। अगर कृषि में देखें 7625 करोड़ रुपये जो 2013-14 से 15 परसेण्ट अधिक है तो कृषि को फायदा होगा। शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता में सुधार के लिये 41538 करोड़ रुपये जो 15 परसेन्ट अधिक है पूर्व के बजट से, उसमें शिक्षा का विस्तार और गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। उसी तरह चिकित्सा में 34 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई है। मान्यवर, जो अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए गरीब बच्चों के लिए 25522 करोड़ की व्यवस्था की गयी है और वह 26 परसेन्ट ज्यादा है, उसका लाभ किसको मिलने जा रहा है मान्यवर सड़क, सेतु, सिंचाई, ऊर्जा उसमें 49 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो पूर्व के बजट से 82 परसेन्ट ज्यादा है। तो मान्यवर, विपक्ष ने देखा जरूर होगा इस बजट को और उन्होने भी बहुत सारी योजनाएं महसूस की होंगी, जो आज उपलब्धि के रूप में मौजूद हैं आज नोएडा में गाजियाबाद में लखनऊ में एक बहुत बड़ी योजना मेट्रो रेल योजना शुरू की जा रही है और पूर्व में भी संचालित हुई थी, मैं बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नोएडा में मेट्रो रेल की योजना शुरू हुई थी और आज भी समाजवादी सरकार में ही उसकी इतनी बढ़ोत्तरी हो रही है कि आज हमारे बड़े-बड़े शहरों में एन0सी0आर0 में गाजियाबाद और नोएडा का बहुत बड़ा महत्व है मान्यवर, उसमें इस योजना को संचालित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर अगर कृषि को ले लिया जाय तो कृषि में आज खाद की किल्लत नहीं है, खाद वितरण की उचित व्यवस्था हो रही है और कृषि की विकास दर बढ़ने की ओर है। मान्यवर, बीजों के, प्रमाणित बीजों के उपयोग के लिए आज अनुदान के रूप में 81 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। कई कृषि विश्वविद्यालयों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया गया है जिसमें 227 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, रासायनिक उर्वरक के अग्रिम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भण्डारण के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, सिंचाई चाहे नलकूप की हो, चाहे नहरों से हो, आज मुफ्त है, इसका फायदा किसको जा रहा है, किसान को। हमारी कृषि की दर बढ़ेगी तो किसान की व्यवस्था सुधरेगी।

श्री अधिष्ठाता-

आज मा0 अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी है कि 5 मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री मदन चौहान-

महिलाओं के लिए आज 1090 हेल्पलाइन शुरू की गयी है। आज सड़क दुर्घटना के लिए 1073 टेलीफोन व्यवस्था शुरू की गयी है। मान्यवर, आज मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर घट रही है। जो पहले 345 प्रति लाख थी आज 300 हो गयी है। मान्यवर, आज 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था है उसका फायदा किसको जा रहा है। आज ये सब सुविधायें हैं। ग्रामों में शौचालय के लिए 359 करोड़ की व्यवस्था है। आज जिसको कोई पेंशन या लाभ नहीं मिलता, उस व्यक्ति को जो वंचित रह गया है समाजवादी पेंशन के द्वारा उसको लाभ देने की योजना है। उसी योजना में 2425 करोड़ की व्यवस्था है। मान्यवर, ग्रामीण आवास में गरीब, कमजोर जिसको आज तक कहीं आवास की व्यवस्था नहीं हो पायी, आज उसके लिए लोहिया ग्रामीण आवास की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, हमको यह नहीं भूलना चाहिए जो गरीब और कमजोर की योजनाएं हैं उनका भी यहां जिक्र आना चाहिए। मान्यवर, शहर में जो रिक्शा चालक है, अगर उसको एक रिक्शा मिल जायेगा तो हम सब लोगों को लगेगा कि किसी गरीब का हम लोगों ने फायदा किया है। मान्यवर, आसरा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आवास जिसके लिए 335 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, पेयजल की व्यवस्था के लिए 1598 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ बात रखना चाहूंगा। आज चिकित्सा के क्षेत्र में फीडर अलग हो। हमारे जो राजकीय चिकित्सालय हैं उसमें आपरेशन की व्यवस्था हो और उसमें 2513 करोड़ का बजट रखा गया है ताकि आपरेशन हो सके, 24 घण्टे बिजली आ सके। आज मैं बताना चाहता हूं कि गौतमबुद्ध नगर में आज एक नया विश्वविद्यालय चिकित्सा के क्षेत्र में खोला गया है तो इन योजनाओं का लाभ किसे मिलने जा रहा है। मान्यवर, जिला संयुक्त चिकित्सालयों में मशीन, उपकरण और संयंत्रों के क्रय के लिए 144 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। ये बहुत सारी व्यवस्थायें आज हमारे बजट में हैं। मान्यवर, लेकिन इसके साथ-साथ मैं अपने गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के बारे में कुछ रखना चाहूंगा। गढ़मुक्तेश्वर एक पौराणिक स्थान है, गंगा किनारे है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, वहां गंगा स्नान का मेला नवम्बर में लगता है। जो बहुत बड़ा मेला लगता है, मैं समझता हूं कि हमारे पूरे भारत का एक मात्र ऐसा मेला है जो प्रतिवर्ष सबसे बड़ा लगता है। अगर वह प्रांत के नक्शे पर आ जाये तो उसकी महत्ता बढ़ जायेगी, उसक रखरखाव में इजाफा होगा तो मेरा अनुरोध है कि यह मेला प्रांतीय मेलों की सूची में आ जाये। मान्यवर, दूसरी मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे गढ़मुक्तेश्वर में बृज घाट है जहां पर स्नान करने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। वहां पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था न होने से कुछ लोग डूब जाते हैं, वहां बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो जाये, सरकारी गोताखोर हो जायें, सरकारी नौका हो जाये तो उससे बहुत लोगों को, श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं कि गंगा नदी में ही एक कूंट नामक जगह है मेरे क्षेत्र में गंगा टीला के नाम से वहां गुरूकुल है, अगर उसका सुधार हो जाये, घाट बन जाये तो बहुत श्रद्धालुओं को बहुत मदद

मिलेगी। मान्यवर, एक और बात कहना चाहूंगा। मान्यवर, आप भी जाते होंगे मुरादाबाद से जैसे ही निकलते हैं तो नेशनल हाई वे पर एन0एच0 24 पर गढ़मुक्तेश्र के पास स्याना चौराहे पर लम्बित पड़ा है, 6-7 साल हो गये उसको। उसमें सैंक्चुरी भारत सरकार का कोई छोटा मोटा लेकुना है उसकी वजह से वह लम्बित है। मेरा अनुरोध है कि अगर विधान सभा के माध्यम से उस सैंक्चुरी की जो अनापत्ति है, अगर वह दूर हो जाये तो वहां पर हाई वे, फ्लाई ओवर का काम हो जायेगा और यह हमारा लम्बित प्रोजेक्ट पूरा होगा। मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

*श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या-

मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे 2014-15 के बजट अनुमानों पर मुख्यमंत्री जी द्वारा पेंशन बजट भाषण जो उन्होंने पेश किया है उसका हमारे दल के नेता मा0 स्वामी प्रसाद मौर्या जी द्वारा विरोध रखा गया है मैं आपने आप को उन्हीं से सम्बद्ध कर रहा हूं। मान्यवर, मैं इस बजट का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि विरोध करना है बल्कि बजट के पेज संख्या-4 पर लिखा है हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अनेक नई एवं महत्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की है। हमने प्रदेश के विकास के लिए एजेण्डा तैयार किया है जिसमें औद्योगिक निवेश हेतु अनुकूल वातावरण सृजित कर निजी निवेश आकर्षित करने, किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र के विकास, सड़कों के विकास, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों, युवाओं का उत्थान एवं कौशल विकास, ग्राम्य तथा नगरीय विकास की योजनाओं के साथ-साथ प्रशासन तंत्र को कुशल एवं प्रभावी बनाने के प्रयास शामिल हैं। मान्यवर, मैं बताना चाह रहा हूं औद्योगिक विकास, उद्योग तब लगेंगे, उद्योगपति तब आयेंगे, जब इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था सही होगी। आज कानून-व्यवस्था प्रदेश की किस हाल में है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुझे इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रतिदिन समाचार पत्र और टी0वी0 इसके बारें में रोज बता रहे हैं। मान्यवर, सड़कों का क्या हाल है यह भी छिपा हुआ नहीं है। पीठ से अध्यक्ष जी द्वारा, जब हमारे वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि उस सड़क का क्या हाल है। मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी बहस हुई। मा0 मुख्यमंत्री जी ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन उस दिन जिस तरह वे हमारे नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी नेता विरोधी दल से जिस तरह के प्रश्न कर रहे थे, उससे लग रहा था कि इस सदन के नेता आदरणीय मौर्या जी हैं और प्रतिपक्ष के नेता मुख्यमंत्री जी हैं। मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे में वह कहना चाहता हूं कि आये दिन अखबारों में निकल रहा है कि किसी को जो चेयर लेकर जायी जाती है, उस पर प्रसव हो रहा है, कहीं पुरूषों के वार्ड में प्रसव कराया जा रहा है, कहीं अस्पताल के बरामदे में प्रसव हो रहा है। मान्यवर, श्रमिक और युवाओं की जो हालत है उनका बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप जो सरकार ने योजनायें चलायी थीं, उसको देने के बाद उसको जब बन्द किया है, तो युवा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मान्यवर, मैं एक और चीज की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज सरकार में सरकारी कर्मचारियों की कमी है। विद्युत विभाग के काम के लिए लाइनमैन वहां पर नहीं मौजूद है। सभी को मालूम है, हमारे मा0 सदस्यों को कि लाइनमैन प्राइवेट रखे गये हैं ठेके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर रखे गये हैं, उनके सहारे विद्युत सप्लाई की व्यवस्था है, इंजीनियर मान्यवर हैं नहीं। ग्राम्य विकास विभाग की हालत यह है कि वहां पर इंजीनियर नहीं हैं, यहां तक की एक-एम बहुउद्देशीय के पास 10-10 गांव दिये गये हैं। खाद्य आपूर्ति में मान्यवर, सप्लाई इन्सपेक्टर नहीं हैं। एक-एक जनपद में एक-एक या दो-दो हैं। मान्यवर, पुलिस की व्यवस्था भी कम है, शिक्षक कम हैं हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी है। 5 हजार प्रिंसिपल की कमी है। हालात यह है कि प्रिंसिपलों के लिए जो एक हमारे अध्यक्ष जी चुने गये हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। वे सरकार के फैसले के विपरीत समानान्तर अपनी बात चलाने के बाद वे प्रिंसिपलों की भर्ती के लिए अपना विज्ञापन निकालते हैं और उनका साक्षात्कार लेते हैं। मान्यवर, लगभग हर विभाग का यही हाल है। जब तक हर विभाग में कर्मचारी नहीं होंगे, हर विभाग में काम करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक उस विभाग में बजट देना उस विभाग का काम करा पाना मान्यवर, संभव नहीं है। चूंकि मैं किसान हूं गन्ना किसानों के बारे में बताना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक रिजर्वेशन की बैठकों में नहीं आते। सरकार के बुलावे पर वह किसी भी कार्यक्रम में नहीं आते। वह अपनी आंकड़े दिखाते हैं आज श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, यहां पर एक व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से रख रहे थे कि चीनी मिल मालिक धमकी दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कितना लाभ पहुंचाया गया है। गन्ना क्रय पर 2 रुपये क्विंटल देकर 160 करोड़, चीनी प्रवेश कर पर 2 रुपये 73 पैसे देकर 219 करोड़, समिति कमीशन में 6 रुपये 30 पैसे देकर 500 करोड़, शीरा बिक्री को शिथिल करके 167 करोड़, यू0पी0ए0 सरकार का ब्याज मुक्त ऋण से 7200 करोड़, एन0डी0ए0 सरकार का ब्याज मुक्त ऋण लेकर के 4400 करोड़ इस समय 12 हजार 646 करोड़ रुपये के सहायता लेने के बाद वे आंख दिखा रहे हैं। मान्यवर, गन्ना किसानों का भुगतान उन्हें नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से यह धमकी दे रहे हैं। मान्यवर, किसान की हालत यह है कि वह शादी-ब्याह नहीं कर पा रहा है, बीमारी-वीमारी से नहीं निपट पा रहा है। अपने जेवर गिरवी रख रहा है। मान्यवर, शिक्षा के अधिकार का कानून लागू हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिये हैं कि पब्लिक स्कूलों में पचीस प्रतिशत गरीब बच्चों को उसमें शिक्षा दी जायेगी। लेकिन गरीब बच्चों को उसमें रखने के बजाय अमीर बच्चों को रखा जा रहा है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने एक बच्चे की सिफारिश की थी लेकिन वह अनसुनी कर दी गयी। तो मान्यवर, तब आम विधायक और आम आदमी की सिफारिश कैसे मानी जायेगी और उसके बच्चे का उसमें दाखिला कैसे हो पायेगा। मान्यवर, पूरे सदन को इसमें दृढ़ संकल्पित होकर निर्णय लागू करना पड़ेगा और पब्लिक स्कूलों मे 25 प्रतिशत गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाई जायेगी। मान्यवर, बेसिक शिक्षा में काफी प्रयास किये गये हैं, लेकिन उसमें जो शिक्षा का स्तर है वह पब्लिक स्कूलों के मुकाबले कम होता जा रहा है। मान्यवर, शहरों में जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, उसमें बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं होती है। खेलने के लिए खेल मैदान नहीं हैं। मान्यवर, जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं या विश्वविद्यालय हैं या इंजीनियरिंग कालेज हैं उनमें प्राइवेट कालेजों के मुकाबले फैकेल्टी अच्छी हैं, टीचर अच्छे हैं परन्तु अभी भी वहां पर शिक्षा के स्तर को सुधारे जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर काला बाजारी हो रही है। अभी एक माननीय सदस्य ने हमारे जनपद लखीमपुर खीरी का नाम लिया था वहां पर भी घोटाला हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि इस काला बाजारी को रोका जाय। मान्यवर, हमारे यहां बाढ़ की समस्या हर वर्ष आती है, क्योंकि यह घाघरा और शारदा के बीच का क्षेत्र है। मान्यवर, शारदा नदी पर और घाघरा नदी पर दो तट-बन्ध बनने हैं।

जिन पर आठ साल से काम चल रहा है और वह अधूरे हैं। मेरी मांग है कि उनको शीघ्र बनवाया जाय। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में नदी के कटान से काफी लोग बेघर है उनके पुनर्वासन के लिए उनको जमीन दिलाई जाय। धौरहरा में सूपा कण्डा में सड़क का निर्माण कराया जाय, वह बहुत दुर्दशा में है। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में खेल का मैदान, मण्डी परिषद की स्थापना महिला विद्यालय और रमिया बेहड़ में इण्टर कालेज की व्यवस्था करायी जाय। मान्यवर, आप मुझे बैठने की लिए कह रहे हैं जो बिन्दु रह गये हैं मैं उन्हे लिख करके दे दूंगा। आप उसे कृपा पूर्वक मेरे बजट भाषण में सम्मिलित कराने का कष्ट करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। अब मैं सत्यवीर मुन्ना जी को बुला रहा हूं।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय, अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की साधारण चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। मान्यवर, यह बजट उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह लगभग 2 लाख 74 हजार करोड़ रुपये का बजट है। यह बजट हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को स्वतः ही प्रदर्षित करता है। लगभग पिछले वर्ष से इसमें 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह भी सराहनीय है। मान्यवर, बजट चूंकि सरकार का लेखा-जोखा होता है लेकिन केवल सरकारी लेखा-जोखा ही नहीं अपितु सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास का स्वरूप भी होता है। इस बजट में राजकोषीय घाटा 2.7 प्रतिशत है। यदि राष्ट्रीय मानक के संदर्भ में इसे देखा जाये तो यह तीन प्रतिशत के अन्तर्गत है। यह हमारी सरकार का सराहनीय कार्य है। मान्यवर, राजस्व में 11-12 प्रतिशत की वृद्धि है जो कि सराहनीय है। राज्य की विकास दर देश के विकास दर से बेहतर है यह भी हमारी सरकार का सराहनीय कार्य है। मान्यवर मैं अपनी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विधायक निधि से 25 लाख रुपये की खर्च करने की अलग से अनुमति प्रदान की है जिसके द्वारा गम्भीर रूप से बीमार गरीबों की हम लोग विशेष तौर से सहायता कर सकते हैं। अभी हमारे विपक्ष के साथी इस प्राविधान की आलोचना कर रहे थे मैं बड़े ही अदब से बताना चाहता हूं कि इसके पहले आप एक पैसा अपने क्षेत्र के गरीब, अपने क्षेत्र के जरूरतमंद को देने के लिए हाथ मलते रहते थे ऐसा कहा जाता है जब कोई बीमार होता है और उसको एक रुपये की भी मदद हो जाती है तो वह जिन्दगी भर आपका एहसान मानता है और आपको दुआ देता है। हम सभी जो उस माध्यम से मदद कर रहे हैं इसके माध्यम से हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री को लाखों दुआएं प्राप्त होगी। अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र में त्वरित विकास के माध्यम से लगभग 5 नई सड़कें 8 करोड़ की लागत से दिये जाने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को विशेष तौर से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। लोहिया ग्राम और जनेश्वर ग्रामयोजनाओं के माध्यम से हमारे खेत्र का समग्र विकास हो रहा है इसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री और अपनी समाजवादी सरकार को विशेष तौर से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। 108 जैसी एम्बुलेस सेवा बहुत ही शानदार है और इसका पूरे भारत में कोई तोड़ नहीं है अगर आप विदेशों में जायें तो ऐसी सेवायें उपलब्ध होती हैं। यूरोपीय और अमेरिकी देशों में ऐसी निःशुल्क सेवायें उपलब्ध होती हैं जो हमारे मुख्य मंत्री और समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में लागू कर रही है इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और समाजवादी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विशेष तौर से अपने सोरांव विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के0वी0ए0 के 4 करोड़ की लागत से नये

विद्युत उपकेन्द्र के पास हो जाने और उसके लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो जाने के लिए अपने मुख्य मंत्री का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो सफाई मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था की गयी उनको नियमित किया गया है इसके लिए मैं माननीय नगर विकास मंत्री, अपनी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सोरांव में अग्नि काण्ड से बहुत नुकसान हो जाता था। आग लगने पर शहर से गाड़ियां आने में 2-3 घण्टे लगते थे तब तक पूरी फसल और मकान नष्ट हो जाते थे। इसके लिए एक फायर स्टेशन 4 करोड़ की लागत से हमारे सोरांव में स्वीकृत होकर उसका निर्माण हो रहा है इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, अन्त में मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं का जिक्र करते हुए और उनके निवारण आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा हमारे क्षेत्र में सड़कों की कुछ समस्यायें हैं मरम्मत के लिए खासतौर से सोरांव बलईमऊ मार्ग, कटभर-धीनपुर मार्ग, हरखुपर से मऊआइमा और इस तरह की कुछ सड़कें हैं जिनके मरम्मत की आवश्यकता है। हमारा क्षेत्र बहुत ही कृषि सम्पन्न क्षेत्र है शिवगढ़ में एक कृषि मण्डी की आवश्यकता है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा चुकी है वह शीघ्र ही स्वीकृत हो ऐसी हम आशा करते हैं। इसके अलावा मऊआइमा टाउन एरिया है और उस टाउन एरिया से जुड़े हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर विद्युत की बहुत समस्या रहती है अगर उसकी फीडर सपरेशन हो जाय तो टाउन एरिया का अच्छी बिजली मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र को भी अच्छी बिजली मिलेगी। मान्यवर, उमरन ताल में जल भराव की समस्या रहती है जिसको सफाई और साइफन की मरम्मत आदि करके दूर किया जा सकता है इसको कराया जाय। साथ ही मनसइता एक बरसाती नदी है जिसके प्रवाह क्षेत्र अन्तर्गत 25 स्थानों पर चेकडैम निर्माण एवं कुसुंमुर डेरागदाई के बीच एक पुल निर्माण की मांग करता हूं। मान्यवर, दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारीडोर जो 12 जनपदों को जोड़ेगा उसमें इलाहाबाद जनपद के मऊआइमा और नैनी औद्योगिक क्षेत्र को भी जोड़े जाने का आग्रह करता हूं। मान्यवर, हमारे विधान सभा सोरांव में 3 स्थानों पर काफी जाम लगता है मऊआइमा रेलफटकी, सोरांव रेलफटकी एवं मलाक चतुरी-भदरी रेलफटकी पर ओवर ब्रिज निर्माण की मांग करता हूं। इसके साथ ही मैं सम्पूर्ण बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

आदरणीय अधिष्ठाता जी, आपने आय-व्ययक 2014-15 पर अभिव्यक्ति हेतु मुझे अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं और कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष, नेता भाजपा तथा अन्य नेताओं द्वारा आय-व्ययक पर प्रस्तुत वक्तव्य का समर्थन करता हुआ उल्लेख करना चाहूंगा। मान्यवर, ब्रह्माण्ड में पांच कारक नितान्त आवश्यक होते हैं और जब उनका ह्रास होने लगता है तो निश्चित रूप से देश में और विश्व में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन पांच कारकों में नं0 1 जंगल, नं0 2 जल, नं0 3 जमीन, नं0 4 जलवायु और नं0 5 जानवर, इन पांचों कारकों का आज लग रहा है कि लोप होता जा रहा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन पांचों विषयों पर बजट में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि चार-चार मुख्यमंत्री हैं और छीनाझपटी में इन पांचों विषयों पर कोई व्यवस्था नहीं हो सकी होगी।

(इस समय 02 बजकर 06 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हमारा जनपद पीलीभीत है जहां का 20-22 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से नक्षत्र और चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं ठीक उसी प्रकार से वनों के द्वारा प्राणियों को प्राणदान मिलता है। हमारे जनपद पीलीभीत में बहुत समय से मांग चली आ रही थी कि वन आरक्षित घोषित किया जाय, जिससे वहां जो दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी पाये जाते हैं वह सुरक्षित रह सकें। पिछली बार मई, जून में तीन शेरों की हत्या कर दी गयी थी तब से यह मांग और प्रबलता की ओर बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जनपद पीलीभीत में वनों को आरक्षित घोषित करके हमारे पीलीभीत की जनता का जो सपना था, उसको साकार किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, मैं इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, हमारा जनपद पीलीभीत उपजाऊ जमीन की दृष्टि से खास क्षेत्र है और जहां कि गन्ना ही नहीं, बहुत सारी फसलें उत्पादित होती हैं। इसमें गन्ना प्रमुख रूप से पैदा होता है। इसीलिए हमारे जनपद पीलीभीत में सहकारिता क्षेत्र की तीन चीनी मिलें और निजी क्षेत्र की पांच मिलें गन्ना पेरने का काम करती हैं। इन चीनी मिलों पर 13419.68 करोड़ रुपया अवशेष है यह रुपया 260 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से है जिस पर ब्याज 781.99 लाख रुपया बनता है यह भुगतान सरकार नहीं करा पा रही है, यह जो अवशेष है, इसका भुगतान करा पाना सरकार के लिए मुझे लगता है, असंभव सा होगा। हम लोग जानते हैं कि पिछली सरकार जो बसपा की थी उसने चीनी मिलें बेचने का काम किया और इस कारण उन्हें उधर से इधर बैठना पड़ा। मुझे लग रहा है कि यह सपा की सरकार भी यदि गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करा पायेगी तो निश्चित रूप से जो हालत बसपा की हुई है, उन्हें उधर से इधर बैठना पड़ेगा अभी लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति और प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, लग रहा है कि आगे जब विधान सभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का बसपा की तरह खाता भी नहीं खुल पायेगा। इस तरीके से हमारे जनपद में गन्ना ही उत्पादित नहीं होता है बल्कि दुग्ध उत्पादन की प्रबल सम्भावनायें हैं।

श्री अध्यक्ष-

तीन मिनट आपका समय था वह समाप्त हो गया है, कृपया समाप्त करें।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

अभी दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से हमारे जनपद में 1 करोड़ 27 लाख 33 हजार रुपया डी0आर0डी0ए0 से दिया गया लेकिन दुग्ध विकास विभाग ने बार-बार पत्राचार करने के बाद भी अवशीतन केन्द्र नहीं खोला, पहले से जो चल रहे थे, उन्हें भी बन्द कर दिया गया। इस प्रकार से मान्यवर हमारे जनपद में मैं भूमियों के बारे में कहना चाहता हूं, भूमि पर अवैध कब्जे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कीजिए, आपका समय समाप्त हो गया।

(मा0 सदस्य श्री अगयश सरन वर्मा के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

फातिमा जी आप बोलना शुरू कीजिए, वह बैठ जायेंगे।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2014-15 के बजट भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। साथ ही मैं मुबारकबाद देना चाहती हूं अपने युवा एवं ऊर्जावान मा0 मुख्य मंत्री जी को, जिन्होंने बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा। क्योंकि बजट सिर्फ एक कागजी दस्तावेज नहीं होता है बल्कि बजट आइना होता है किसी भी सरकार के उस सरकार की मुखिया के सोच का। सरकार क्या सोचती है, सरकार ने अपने पुराने बजट पर कितना अमल किया है, सरकार जनता की आवश्यकताओं के प्रति कितनी कटिबद्ध है, कितनी जागरूक है, इन सारी चीजों का दस्तावेज होता है हमारा यह बजट। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे अपने उस लक्ष्य का प्राप्त किया है। यह मैं इसलिए कह सकती हूं कि अगर आप बजट को उठाकर देखेंगे तो वित्तीय घाटा हमारा तीन प्रतिशत से कम रहा टोटल जी0डी0पी0 के, यह 2.97 प्रतिशत रहा। इसके साथ ही जब प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश आर्थिक झंझावात से जूझ रहा था और हिन्दुस्तान की विकास दर घट करके 4.9 प्रतिशत हो गयी थी, ऐसे विकट समय में भी उत्तर प्रदेश ने आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए 5.2 प्रतिशत की विकास दर को हासिल किया। यह हमारे ऊर्जावान मुख्य मंत्री जी के हौसले थे और मैं इसके पक्ष में कह सकती हूं आपसे कि वर्ष 2012-13 में जो प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 33 हजार 137 रुपये होती थी वह पिछले वर्ष बढ़ करके 37 हजार 589 रुपये हुई। यह किस प्रकार मुमकिन हुआ, क्योंकि साधन वही थे, प्रदेश वहीं था हां यह सही है कि प्रदेश के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की नीयत उनके अन्दर थी और यकीकन यह उनके जज्बों की सदाकत की, उनकी नेकनियति की दलील है और इसलिए है कि अगर दिल में जज्बा हो और इंसान सच्चे जज्बों के साथ में आगे बढ़े तो यकीनन मंजिल मिल जाती है और इसी लिए कहा है कि-

ऐ जज्बे दिल अगर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए,
और मंजिल के लिए दो गाम चलूं सामने मंजिल आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अध्यक्ष जी, बस एक बात मुझे कहनी है कि यह बजट अपनी प्राथमिकताओं के लिए जाना जायेगा क्योंकि इस बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा कृषि, गांव और किसान के ऊपर खर्च हुआ। सामने बैठे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी समाजवादी सोच की सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगी कि इसके पहले कौन सा बजट आया था जिसमें 75 प्रतिशत की धनराशि कृषि और किसानों के ऊपर खर्च हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

जहां तक सवाल रोजगार देने की है तो मैं इतना कह सकती हूं आप लोगों से कि रोजगार देने की दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध थे और जो प्रतिबद्धता इसमें नजर आती है हम उस निवेशक सम्मेलन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी बात हो चुकी है लेकिन यह जरूर कहेंगें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, बस समाप्त कर रही हूं अपने क्षेत्र की बात कह लूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी तक तो आप जनरल बजट पर बात कर रही थीं, जल्दी खत्म करिये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मैं निवेशक सम्मेलन की बात नहीं कर रही हूं लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि जो नीति थी उस नीति के बदौलत 45 हजार नयी औद्योगिक इकाईयां लगीं, 4 लाख 81 हजार लोगों को रोजगार मिला और पूर्वांचल की मैं हूं इसलिए मेरा एक निवेदन है कि 291 करोड़ रुपये की धनराशि जो पूर्वांचल विकास निधि के लिए रखी गयी है मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाये और इसलिए बढ़ा दिया जाये कि उद्योगों के लिए आपने प्रोत्साहन धनराशि रखी है, पूर्वांचल में उद्योग नहीं है, ब0स0पा0 की सरकार में कोई उद्योग नहीं लगने पाये लेकिन इस समय मेरा निवेदन है कि पूर्वांचल में मेरे जनपद गाजीपुर में मेरी विधान सभा में बहादुरगंज के पास एक कस्बा पड़ता है वहां पर 80 एकड़ भूमि है और मैं खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित उद्योग लगाने के लिए आपसे अनुरोध कर रही हूं क्योंकि पूर्वांचल में हमारे यहां चाहे आलू हो या टमाटर हो, इन सब चीजों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। अगर उस पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वहां पर लगाये जायेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये। श्री बंशी सिंह पहाड़िया।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, आखिर में इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि प्रदेश के प्रगति का जो सपना देश के कर्णधारों ने देखा था उसको साकार करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरी बातों को एतराज के तौर पर कम सुझाव के तौर पर ज्यादा लिया जाये। प्रदेश के विकास की बात सरकार ने की, आगरा में सम्मिट की बात सरकार ने की और अभी दिल्ली में 12 जून, 2014 को निवेशकों के सम्मेलन की बात की। जो सम्मेलन हुआ उसका रिजल्ट क्या आया, 150 कम्पनियों ने भाग लिया और 23 कम्पनियों से लगभग 54,606 करोड़ रुपये

के समझौते हुए। आज कानून-व्यवस्था की बात सरकार कर रही है लेकिन कानून-व्यवस्था की स्थिति यह है कि चार वर्ष की अंशिका गगनलता थाना कांठ की यह लड़की 05 माह से गायब है और इसी तरह से अतीकुरनिसा एक वर्ष का बच्चा थाना मडियांव लखनऊ से गायब है, यह आपकी सरकार की कानून-व्यवस्था है। मान्यवर, विश्वस्तीय पाटरी, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का हब खुर्जा में है यह सभी लोग जानते हैं। पिछले 30 वर्ष से इस पाटरी उद्योग के बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कभी सिकन्दराबाद और खुर्जा ने इस खेत्र में बड़ा नाम हासिल किया था। माननीय अध्यख जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वहां के महाप्रबन्धक ने उसकी आंकलन रिपोर्ट भी नहीं भेजी है। भारत सरकार से जो कोयले की आपूर्ति होती थी वह भी उसकी नहीं आवंटित किया गया है। अध्यक्ष जी, आज यह सरकार नगरों के विकास की बात कर रही है।.....

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज कुछ आबादी का हिस्सा नगर और गांवों के बीच में पड़ता है, न वह देहात में आते हैं न शहर में।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, बैठिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, न तो उनके जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाये जाते हैं न उनको सुविधायें मिलती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बजट में अल्पसंख्यक भाईयों के लिए कब्रिस्तान की चाहरदीवारी के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और बहुसंख्यक समाज के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मा0 अध्यक्ष जी पिछले 2 वर्ष से इन्दिरा आवास और गरीबों को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री अध्यक्ष-

पहाड़िया जी अब आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

*श्री श्याम बहादुर यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये किसी भी राज्य के बजट से बड़े बजट 2 लाख 74 हजार 459 करोड़ रुपये का जो बजट रखा गया है उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक शानदार बजट रखा है वह प्रदेश के चहुंमुखी विकास का प्रदेश के सर्वांगीण विकास का आइना है पीछे भी जो बजट आये हैं उन बजट पर हमारी सरकार ने माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री जी ने प्राथमिकतायें तय की थीं उन प्राथमिकताओं पर हमारी सरकार ने दृढ़ता से काम किया है। कई बार इधर से बातें आई थीं कि झुनझुना कहा गया था लैपटाप के लिए 15 लाख से भी ज्यादा की संख्या में लैपटाप का वितरण करके गरीबों, मजलूमों, किसानों के बेटों को नयी विधा से जोड़ने का, टेक्नालाजी से परिचित कराने का उन्हें देश की मुख्य धारा से पढ़ाई लिखाई से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें जड़ नहीं होती हैं सरकारों के चिन्तन का विषय होता है सरकारें गतिमान होती हैं विचारशील होती हैं आज हमारी सरकार ने जो प्राथमिकताएं तय की हैं उन प्राथमिकताओं में गावों के गरीबों के लिए बजट का करीब 75 प्रतिशत हिस्सा हमारी सरकार ने गांव गरीब किसानों को प्रमुखता से दिया है। विचारशील सरकार है जैसे-जैसे प्राथमिकतायें तय होंगी वैसे-वैसे उस दिशा में बजट को ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस नीति, नीयत और निष्ठा से माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं उसी नीति, नियत और निष्ठा से हम चाहते हैं कि हमारे जो विपक्षी साथी हैं वह बजट का समर्थन करें सरकार का समर्थन करें और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करो कल इतना समय था उस समय तो बोले नहीं।

श्री श्याम बहादुर यादव-

मान्यवर, अभी तो एक मिनट भी नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्राथमिकतायें दी हैं उससे नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। समय कम है इसलिए मैं अपने क्षेत्र पर विशेष फोकस करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में एक ऐसी सड़क है जो आप जब शुरू-शुरू में आये होंगे वर्ष 1971-72 में एक योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 27 सड़कों का निर्माण किया गया था। सभी सड़कें उच्चीकृत और चौड़ी हो गयी माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हुए हैं प्रदेश में उस योजना की सिर्फ एक सड़क बाकी है आजमगढ़ में वह सदर विधान सभा माननीय परिवहन मंत्री जी की विधान सभा से शुरू होकर आदरणीय आलमबदी की विधान सभा से होते हुए मेरी विधान सभा फूलपुर पवई को क्रास करते हुए मुख्यालय से जनपद सुल्तानपुर को जोड़ने का मात्र 55 कि0मी0 का रास्ता है वह जनपद की बहुत महत्वपूर्ण सड़क है।

श्री अध्यक्ष-

सड़क के लिये लिखकर दे दीजिये।

श्री श्याम बहादुर यादव-

लोहिया आवास ग्रामों के लिये हमारी सरकार ने आवास देने का काम किया है नये आवास देने का काम किया है मछुआ आवासों के लिये 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख 60 हजार रुपये करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बिजली पर इतना बड़ा कभी किसी सरकार ने नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने महिला सदस्य को बुला लिया है उनको बोलने दें।

श्रीमती हेमलता चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं जिस क्षेत्र से आई हूं उसने बड़े नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री दिये हैं। फिर भी वह क्षेत्र बहुत उपेक्षित है।

श्री अध्यक्ष-

जितना समय था वह खत्म हो गया है। यह लिखा नहीं जायेगा, यह जो भी बोल रहे हैं। हेमलता जी आप अपनी बात बोलिये।

श्रीमती हेमलता चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं इस सदन में पहली बार चुन कर आई हुई हूं और पहली बार यहां पर बोल रही हूं। मैं जिस क्षेत्र से आई हूं उस क्षेत्र ने बड़े-बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री दिये लेकिन फिर भी आज वह क्षेत्र उपेक्षित है। मैं बागपत क्षेत्र से हूं जो कि दिल्ली से बहुताश से नजदीक होने के बाद भी बहुत पिछड़ा हुआ है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे यहां की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिये रोज लड़ती है। आज भी मेरे क्षेत्र में मेरी जनता बस स्टैण्ड के लिये प्रतीक्षा कर रही है। मेरे क्षेत्र को जिला बने हुए बहुत वक्त होने के बावजूद भी आज भी मुख्यालय में महिलाओं के लिये सुलभ शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगी और थोड़ा सा प्रार्थना करूंगी इस चीज के लिये कि वहां महिलाओं के लिये सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराई जाय। वहां पर सड़कों की हालत बहुत जर्जर है। तालाब हैं जो उपेक्षित रूप से भरे हुए हैं और उनका पानी सड़कों पर आ रहा है। उसके आस-पास जो विद्यालय बने हुए हैं वहां पर स्थिति इतनी खराब है कि बच्चों के डूबने की आशंका बनी रहती है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि उसकी चहारदीवारी बनवाई जाये। उसके पानी की निकासी की व्यवस्था की जाय। जो उसके आस-पास जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जो सड़ रहे हैं पानी से, जिससे जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसका थोड़ा सा समाधान किया जाय। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान है, वहां पर गन्ने की खेती होती है। शायद यही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां पर गन्ने की खेती होती है इसीलिये शायद उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। मजदूर मिल में काम करता है लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वह इसी प्रतीक्षा में रहता है कि उसे वेतन कब मिलेगा ? जब सरकार की तरफ से थोड़ा मेहरबानी हो जायेगी किसानों के लिये तब वहां पर मिल जायेगा उसे। तो आप लोगों से यही चाहती हूं कि किसानों को उनके गन्ने का भुगतान हो तो मजदूरों को भी उनकी मजबूरी मिले। मेरे क्षेत्र की जो मिल है, वह इतनी जर्जर अवस्था में हैं कि यह देखिये कि आजादी के बाद शायद यही एक मिल है। जो अभी तक चल रही है। लेकिन चल क्या रही है उसके पुर्जे कभी भी हिलते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर आप वहां जायं। उसकी स्थिति यह है कि वहां उस मिल के चलने के बाद जो धुआं उठता है उससे उसके आस-पास के गांव प्रभावित होते हैं। इतनी राख जाती है कि आस-पास के सभी गांव के बच्चे, घर और जो कपड़े धुलते हैं वह सब प्रभावित होते हैं। वह पूरी तरह से काले हो जाते हैं। जब भी मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो वहां की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इस मिल से यह जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाय। मेरे क्षेत्र में लड़कियों के लिये डिग्री कालेज नहीं है मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि वहां पर एक डिग्री कालेज बनवाया जाय ताकि वहां की लड़कियां पढ़ सकें जो कि

कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ने के बाद परिवारी का बोझ उठाने के लिये विवश हो जाती है। मेरे क्षेत्र का उद्योग मर रहा है। यहां का व्यापारी पलायन करने के लिये मजबूर हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए क्योंकि आप पहली बार बोल रही हैं, इसलिये टोका नहीं।

श्रीमती हेमलता चौधरी-

आपसे निवेदन है कि औद्योगीकरण के लिये बजट में आपने जो व्यवस्था की है, उसमें हमारे क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाए। मेरे क्षेत्र में 4 से 6 घण्टे तक बिजली आती है, जिसके वजह से वहां का व्यापारी उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जा रहा है। मेरे क्षेत्र में बच्चों के लिये स्टेडियम की व्यवस्था की जाए, मुख्य मंत्री जी मैं आपकी विशेष कृपा चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र बागपत पर आपकी कृपा दृष्टि हो, धन्यवाद।

*श्री सुरेश राणा-

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, बजट पुस्तिका में मैंने पढ़ा कि ग्रामीण जनता का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मुझे लगता है कि यह लाइन ही काफी है, इस बजट का विश्लेषण करने के लिये। यह धरती पुत्रों की सरकार है, मुलायम सिंह के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं यदि गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, मान्यवर, पलायन किसी कारण से होता है इसका मतलब यह है कि गांवों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है और मुझे याद है एक दिन मैं बैठा था, पढ़ रहा था ''तलवारों की नोंकों पर मौजों की जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है'' और जवानों के लिये मा0 मुख्य मंत्री ने लैपटाप दिया, एक योजना चलाई न जाने क्या कारण हुआ, उसे बन्द कर दिया, महिलाओं के लिये बजट में कुछ है नहीं, लैपटाप बन्द कर दिया गया, कन्या विद्या धन बन्द कर दिया गया, यह जो पलायन है, इसे रोकने के लिये कुछ तो विचार करना पड़ेगा। उद्योग की बात करते हैं। अभी दिल्ली में सेमिनार है, अच्छा विचार है, मैं स्वागत करता हूं, सेमिनार होनी चाहिए लेकिन जो अपना उद्योग था, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह मुरादाबाद का पीतल उद्योग, सहारनपुर का वुड क्राफ्टिंग उद्योग, मुजफ्फरनगर का पेपर का उद्योग, मेरठ का स्पोर्ट का उद्योग, आगरे का चमड़े का उद्योग, मान्यवर, इतनी अपने यहां सम्भावनाएं हैं, उन उद्योगों का आखिर क्या हुआ, कोई चिन्ता नहीं है। पिछले दिनों भी बहस के दौरान विषय आया कि उत्तराखण्ड के पास का क्षेत्र हरियाणा के पास का क्षेत्र, वहां बिजली मंहगी है, सुविधाएं हैं नहीं,। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि अपने क्षेत्र को सुविधा दी जाए, आज गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, हजारों गाड़ियां उत्तराखण्ड में रजिस्टर्ड होती हैं हजारों गाड़ियां हरियाणा में रजिस्टर्ड होती है। यदि अपने यहां वैट कम करके उस व्यवस्था को लागू किया जाए तो अपने यहां राजस्व की वृद्धि होगी। आज वहां पूरे डीजल की तस्करी होती है और जितने भी पेट्रोल पम्प है, चाहे उत्तराखण्ड के पास के हों, चाहे हरियाणा के पास के हों, सबकी स्थिति आप देख लीजिये, कोई तेल लेने को तैयार नहीं है, लाखों लीटर प्रतिदिन डीजल की तस्करी होती है यदि अपने यहां वैट को कुछ कम करके डीजल का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाव बराबर कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी और निश्चित रूप से अभी कल के आंकड़े मैं देख रहा था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, मा0 स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, केवल 5 लोगों की डेंगू से मौत हुई है, यह प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कोई प्रतिकार का विषय नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं और स्पष्ट जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा के एक गांव पदे में 25 लोग डेंगू से मरे हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप आंकड़ों की जादूगरी से उठाना चाहते हो, मा0 मुख्य मंत्री जी की सकारात्मक सोच है, वह आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप क्यों उलझा रहे हो ? आप आंकड़ों के आधार पर क्यों उलझाना चाहते हो ? मान्यवर, 25 लोग डेंगू से मरे हैं। मान्यवर, सहकारी मिलों के लिये 400 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान है वहीं 650 करोड़ चाहिए। आप तो किसानों के हितैषी हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बस अब हो गया। अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, निजी चीनी मिलों की भी यही हालत है।

(सत्ता पक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर-शराबा उत्पन्न हो गया। शोर-शराबा के मध्य)

श्री सुरेश राणा-

सुनिये। अध्यक्ष जी, व्यवस्थित करा दें। व्यवस्था बनाइये।

श्री अध्यक्ष-

राणा साहब अब खत्म करें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। इससे इनको पीड़ा हो रही है। मान्यवर, इसी सदन में मैंने मा0 आजम साहब का भाषण सुना था। मा0 आजम साहब ने भाषण दिया था और वास्तव में मैंने उनके विषय से अपने आपको जोड़ा और आज तक मुझे वह विषय याद है कि इन्होंने रामपुर का बताया था कि एक काली एम्बेसडर आयी थी और हत्या की भी आशंका थी। राजनीतिक आधार पर कार्रवाई हुयी थी। मैं कहना चाहता हूं कि जरा सा मुद्दा उठाया तो रासुका लगा दी गयी।

(सत्ता पक्ष के कई मा0 सदस्य एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया। इस बीच श्री सुरेश राणा बोलते रहे लेकिन उनका भाषण शोर-शराबे के कारण सुनाई नहीं दिया)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त। अब आपका लिखा नहीं जायेगा। श्री राजेन्द्र सिंह राणा साहब आप बोलेंगे। जरा कृपा करके बोलियेगा।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे प्रदेश के होनहार, यशस्वी मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जैसे कि सभी

बुद्धिजीवी सदस्य इस सदन के सदस्य हैं और सबने अपने-अपने विचार रखे। जैसे ही सदन प्रारम्भ हुआ। एक बात देखने को बहुत अच्छी मिली कि दोनों दलों में होड़ थी, आलोचना की और यहां तक कि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो गरिमा तार-तार की गयी एक राजनीतिक दल द्वारा और यह सर्वविदित भी है और यह आदत भी है कि एक फासिस्टवादी ताकत देश को लगातार अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। आज भी इनकी सोच उसी तरह की है जैसे कभी महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने बर्ताव किया था, इनकी सोच ने बर्ताव किया था।

श्री अध्यक्ष-

बजट पर बोलिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मुझे बजट पर ही बोलना है। मा0 अध्यक्ष जी, यहां पर होड़ लगी हुयी थी। हाथी इनका निशान है लेकिन हाथियों के बल इनमें आ गये थे। एक-दो लोग घायल भी हुए। आपके सदन के मार्शल व्यवस्था में जो लोग हैं। उनको मालूम है कि हाथी निशान उनका है और हाथियों के बल इनमें आ गये हैं और यह सारे सदन ने देखा और पहली बार नेता प्रतिपक्ष अपने आपको हताश निराश, परेशान, आपकी चालाकी, चापलूसी और चपलता से विधान सभा की कार्यवाही ठप्प करने में आप इस बार बाजी मारना चाहते हो। अभी तो रिजल्ट निकला है, अतीत भूल गये हो कि अतीत में क्या हुआ, हमारी कानून-व्यवस्था पर ऊंगली उठाते हो। किसी प्रदेश को चलाने के लिये एक इंगलिश का बहुत छोटा शब्द है वेयर जिसका मतलब है, यदि वेयर का अर्थ है कि सबसे पहली बुनियादी जरूरत इंसान की जो है वह पानी की है और इस बजट के बारे में, मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा हमारी सरकार द्वारा पूरा सोंच समझ कर इस बजट को प्रदेश की जनता को जिसमें 80 फीसदी से ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं, जिनको बुनियादी हक नहीं मिला है, जिन्होंने कभी जीवन स्तर को बढ़ाने के बारे में सोंचा लेकिन कभी बढ़ा नहीं पाये चूंकि व्यवस्था ऐसी थी गरीबों के नाम की राजनीति करने वाले, छलावा करने वाले, गरीबी को कलंकित करने वाले, गरीबी का मजाक उड़ाने वाले, गरीब को बेटा-बेटी कहने वाले लोग इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं और उन्होंने गरीबी का मजाक उड़ाया है। देश की जरूरत थी हेल्थ की, दूसरी सबसे जरूरी चीज है वह प्रदेश के लोगों के लिये हेल्थ की आवश्यकता है, आज सबको मालूम है कि कैसा मजाक हुआ पिछले पांच सालों में हेल्थ के साथ एन0आर0एच0एम0 जैसी महत्वाकांक्षी वर्ल्ड बैंक की परियोजना लगातार जिसमें हर वर्ष तक तीन हजार करोड़ रुपये आये हों और 09 हजार करोड़ रुपये दीमक भी खाने में टाइम लगाती है, लेकिन हमारे इन प्रतिपक्ष के लोगों ने दीमक को भी पीछे छोड़ दिया, लुटेरे को भी पीछे छोड़ दिया और 09 हजार करोड़ रुपये खा गये। प्रदेश के कई पूर्व मंत्री और कई सरकारी अधिकारी आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कमाल की बात है न शर्म आती है न लज्जा आती है। हमारी कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि हमारी कानून-व्यवस्था में क्या कमजोरी है, हमारे पास आंकड़े हैं, आप प्रदेश की जनता के हिसाब से प्रदेश के लोगों के हिसाब से यहां के देश का जो सिस्टम है पूरा सभी देशों के प्रदेशों के मुकाबिल यदि हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था का मुकाबला कर लिया जाय तो आपको मिलेगा बेहतर, आप कहते हो कि हम अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपसे बिल्कुल सीधे-सीधे कहना चाहता हूं कि ''आइना देखिये पता चल जायेगा, चेहरे पर लगी कालिख का भी पता चल जायेगा'' आपके समय में तो थानों में बलात्कार हुआ,

थाने के लोगों ने बलात्कार किया, इटावा में 7-7 लोगों की हत्याएं हुई, नादिर शाह की लूट हुई, आपके राज में जिस तरह से अधिकारियों ने नौजवानों के मान-सम्मान को मां-बहन की बेटियों को जिस तरह जूतों के नीचे रौंदा है आप भूल गये उस बात को, आपने देखा नही समझा नहीं किस तरह से पूरे प्रदेश में अघोषित इमरजेन्सी लोगों के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ आपने जैसा चाहा कानून के साथ खिलवाड़ किया, आपने कभी किसी के मान-सम्मान की हिफाजत तो छोड़ दो, उनका मान-सम्मान और इज्जत दागदार कर दिया, काफी बेगुनाह लोग जेल गये, लेकिन आज भी हमारे नेता जी द्वारा बनाई गई परम्परा को हमारे दल के हमारे साथी लोग, आज भी उनका निर्वाहन करना चाहते हैं और बार-बार आप हमें गुण्डाराज बताते हो, मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2012-13 की रेप की घटनाओं में यदि आज सही मायनों में देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध जो हुआ है तो उसमें श्रीमान् जी आपके चहेते और आपके आदर्श प्रदेश मध्य प्रदेश में हुआ है आंकड़े मेरे पास में हैं जिसमें 9.72 फीसदी महिलाओं के प्रति रेप की घटनायें कारित हुई हैं और उसके बाद जो दूसरा नम्बर आता है तो इसमें भी बड़ी इज्जत है आपकी, सम्मान है तो उसमें भी आपका छत्तीगढ़ आता है, यह आंकड़े हैं मेरे पास, मैं बहस करने आया हूं। छत्तीसगढ़ में 8.41 परसेण्ट की दर है रेप की और मध्य प्रदेश में 9.72 का। दिल्ली में 8.26 परसेण्ट है और ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी कम पुलिस होने के बावजूद भी हमारे उत्तर प्रदेश में 2.02 परसेण्ट है। आप देख लीजिए, आप कम्पैरिजन चार्ट देख लीजिये, नेशनल क्राइम ब्यूरो का मैं लेकर आया हूं। इन महत्वपूर्ण अपराधों में, डकैती में माइनस 12.71 प्रतिशत की कमी आयी है, आंकड़े हैं। किसी को चाहिए मैं प्रति दे दूंगा। हत्या में 1.20 की कमी आयी है, बलवे में 6.69 प्रतिशत की कमी आयी है। रोड होल्डअप, आपके राज में तो कमाल था। दिन दहाड़े ट्रक लुटते थे, दिन दहाड़े चोरियां होती थीं, दिन दहाड़े डकैती होती थी। हमारे यहां रोड होल्डअप में माइनस 100 प्रतिशत कमी आयी है। इसके अलावा, कुल मिलाकर मुकदमों में भी 9.36 प्रतिशत की कमी आयी है लेकिन ऐसा नहीं है हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और हमारी सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से कानून का राज हो। आपने बिगड़ी हुई परंपरायें, आपने भ्रष्टाचार की मर्यादायें तोड़ते हुए सभी अधिकारियों को ऐसी अफीम की लत लगा दी कि अब वे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन सुधरेंगे। मुख्य मंत्री जी, जितने सरल और सज्जन दिखायी देते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ऐसा तो काम करेंगे नहीं, जैसा आपके लोगों ने किया। हर हालत में कण्ट्रोल होगा और हर हालत में गुण्डागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। हमें मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बहुत महारत हासिल है। आपके बड़े नेता जब पैदा हुए होंगे तो मां ने घुट्टी पिलायी होगी कि बेटा सब हुछ बोलना लेकिन जिन्दगी में कभी सच नहीं बोलना, झूठ बोलना और घुट्टी ने असर किया, ऐसा नहीं कि घुट्टी ने असर नहीं किया। अभी सर क्या हुआ कि मुझे समने में भगवान जी दिखायी दिये।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, आप सपना यहां न बताओ, तथ्यपूर्ण बात करो।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मैं गलत बात नहीं कहूंगा, आप मुझे बोलने दीजिए। पहले अल्लाह मिले तो मैंने कहा कि कैसे हैं और मैंने कहा कि अल्लाह मियां कुछ ख्याल करियेगा। हमारी पोजीशन जो है लोगों ने, प्रेस वालों ने, सबने मिलाकर हमारी बहुत बेज्जती की। बोले तुम्हारा क्या, हमारा तो घर ही तबाह

कर दिया। हमने कहा कि घर किसने तबाह कर दिया तो कहा कि तुम्हारे ही प्रदेश में है सब। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया, विधान सभा में और जगह-जगह कह दिया कि कुछ नहीं करेंगे लेकिन घर हथौड़े से, छेनी से, दिमाग से उन्माद से अल्लाह का घर उजाड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब सुबह हुई तो भगवान जी मिले समने में, हमने कहा भगवान जी बताइये कैसे हैं तो उन्होंने कहा कि क्या कहूं, तुम्हारे प्रदेश में तो ऐसे लोग हैं कि मेरा मन्दिर, मेरा घर बनाना चाहते थे, उस घर के लिए जो पैसा हजारों करोड़ रखा हुआ था। वह भी डकार गये, हजम कर गये, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

अब आप ये बताइये कि इनके पास वह कौन सी चार्टर्ड कम्पनी है ये हिन्दू है और हिन्दू नहीं है। यही गले में फटका डाल सकते हैं। ये सामने कांग्रेस वाले शायद हिन्दू नहीं है मुझे लगता है। ये कल बहुजन समाज पार्टी वालों को भी कह रहे थे। ये राम के नाम का चंदा कटा के हजारों करोड़ रुपये खा गये। एक ईट वहां पर नहीं लगाई और आज तक राम का ही नाम ले रहे हैं, देखो राम के ही नाम से काम चला रहे हैं। अभी फिर बाजीगरी करी, नारे दिये झूठे। फिर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करीं कि देश की सूरत बदल देंगे, शक्ल बदल देंगे। तुम क्या बदलोगे, जब तुम्हारी खुद की सूरत नहीं बदली, खुद की सीरत नहीं बदली, खुद का काम नहीं बदला, खुद की सोच नहीं बदली तो कैसे आप ऐसा कर दोगे। हमें मालूम है कि हिन्दुस्तान 100 करोड़ का मुल्क है, ये ऐसे नहीं चल सहता है। इसकी एक बटा चार आबादी ऐसी है जिसने आपके देश के इतिहास में योगदान दिया है। जिसने आपके देश का निर्माण किया है आप उसको नहीं छोड़ सकते। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। राष्ट्रभक्त इतने राष्ट्रभक्त, देशभक्त दुनियां में कहीं नहीं हैं। इतने राष्ट्रभक्त, देशभक्त थे कोई कि भांग का गोला खाया और सोते रहे और पाकिस्तानी पहाड़ियों पर चढ़ते रहे कारगिल की लड़ाई करवा दी और हजारों सैनिक शहीद करवा दिये। इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त है कोई। आप से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है लेकिन ये बात मैं आज भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे समझ लें कि इस तरह की फॉसिस्टवादी सोच के आप लोगों के द्वारा बोये गये बीज इस देश को कभी सुखी और समृद्ध नहीं कर सकते। इस देश में अगर राम बसता है, तो रहमान भी बसता है, यहां हर जाति का, हर कौम का इंसान बसता है, जो हिन्दू हो तो क्या तुम फखत हिन्दुस्तानी हो, यहां हरेक मुस्लिम के दिल में भी एक हिन्दुस्तान बसता है। आपको समझना होगा, जानना होगा, अब मुझे महाना जी ये सारा सदन तो दो-एक तो चला गया अब आप रह गये। अब आप ही सारा समय अकेले ही बोलते हो, हमें तो अभी दो मिनट बोलने को मिला है। आपका नजरिया देखकर तो हम बहुत खुश होते हैं जिस तरह से आप घूम-घूम कर बात करते हो मजा लेते हो, कसम से हम तो फिदा हैं आपके ऊपर और क्या करें यह तो अखिलेश जी ने पाबंदी लगा दी पहले हम सारे डांस-वांस देख ही लेते थे। तो मा0 अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं ये हमारे मा0 नेता प्रतिपक्ष अभी प्रदूषण पर बात हो रही थी बहुत तेवर दिखा रहे थे और बहुत-सारी लूट, डकैती, गुण्डाराज, तमाम ऐसे विभूषणों में हमें विभूषित करते हैं, लेकिन इन्हें अपना कभी नहीं दिखायी दिया। अपना नहीं दिखायी दिया तो यह दुर्गति हुई। हमें बार-बार पिछली विधानसभा में कहते रहे और अभी एक नया काम हुआ है अभी इन्होंने राजनीति छोड़ दी लेकिन छोड़ी किसके चक्कर में आपके चक्कर में। (भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करते

हुए) साइलेंट फीचर है ये इनका। ये इनका साइलेंट फीचर है। (हंसी) इन्होंने कहा कि भाई हम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जायेगी, इसलिए कभी अल्लाह वालों से भी सोंचे कभी मद्द कर दें, तो इन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम बिल्कुल वाकओवर कर रहे हैं और बी0जे0पी0 लड़े चुनाव और समाजवादी लड़े। देखो हम तो लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे और अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष आप बहुत सम्मानित हो, बहुत वरिष्ठ हो और नौकरी तो आपकी चलेगी अभी लग रहा है मुझे जितना जोर आप लगा रहे हो पार्टी के लिए। नौकरी में तो कोई खतता है नहीं लेकिन एक सलाह मेरी जरूर है आप एक यूनिवर्सिटी आफ इक्सीलेन्स एण्ड करप्शन यूनिवर्सिटी खुलवा दो। नाम तो किसी का हो लेकिन यूनिवर्सिटी आफ करेप्शन जब खोलोगे, उसमें आने वाली पीढ़ी को बताना कि मूर्ति का घोटाला कैसे किया जाता है, कैसे ज्यादा-से-ज्यादा पैसे लेकर घटिया से घटिया मूर्ति लगायी जाती है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे भी लड़के-बच्चे, बहुत-से ईमानदार हैं, आजम भाई और सारे लोग हैं लेकिन कुछ लोग तो इस स्कूल में 6 महीने का डिप्लोमा करके.....

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 मंत्री जी, आपका समय समाप्त हो गया है, दूसरों को बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

स्वास्थ्य विभाग में कैसे कम्बल खाया जाता है, कैसे चश्मा खाया जाता है, कैसे दवाइयां खायी जाती हैं। एक सब्जेक्ट तो इसका हो जायेगा और.....

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। आप बैठ जाइये।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के एक साथ खड़े होकर मा0 मंत्री जी के भाषण के विरोध के कारण व्यवधान की स्थिति।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए।

(बसपा की तरफ से आवाज आयी कि एम0पी0 का चुनाव भी तो लड़े थे।)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

[पैसे दिये थे, कोई मुफ्त में लड़े थे। पैसे दिये थे। भाई पैसे दिये थे वोट नहीं दिये। भाई पैसे लिये थे,] बताओ दोबारा क्या पूछ रहे हो।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। अब आपका हो गया, बहुत हो गया, आप बोल लिये, अब बैठिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

अभी मा0 अध्यक्ष जी, पूरी बात कहां हुई है।

नोट [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री जी को 3.00 बजे बोलना है, 5 मिनट बचे हैं, दो-एक सदस्य और बोल लें आप बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

इनकी यूनिवर्सिटी के तीन-चार सब्जेक्ट रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, वो सब्जेक्ट पब्लिक मीटिंग में वह सुनाना।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मुझे दुःख होगा कि जब मुझे आपकी बातों को लिखने के लिए मना करना पड़ेगा। आप समाजवादी पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। आप कृपया बैठ जायें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपको एक मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि उनकी बात नहीं लिखी जायेगी। मान्यवर, उस दिन आपने हम लोगों की बात कार्यवाही से निकालने की बात कही थी। आज आप इनकी बातें कार्यवाही से निकालने का आदेश दें। मान्यवर, मुझे वाइण्ड अप करने दें।

श्री अध्यक्ष-

देखिये अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलना है उसके बाद चाहे तो आप स्पष्टीकरण पूंछ लीजिएगा। इसमें वाइण्ड अप की बात नहीं होती है।

श्री सतीश महाना-

[मान्यवर, जब यह इधर रहे तो बाल काटते रहे नाई की तरह अब उधर बाल काट रहे हैं। इन्होंने यूनिर्वसिटी में भ्रष्टाचार की बात कही। अभी इन्होंने कहा कि पैसा देकर वोट खरीदे हैं। तो कितना पैसा दिया है] यह बतायें यह सब कार्यवाही में है आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही देख लूंगा। आप बैठें। जब माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण हो जाये, तो आप उसके बाद अपना स्पष्टीकरण पूंछ लीजिएगा। माननीय मुख्य मंत्री जी।

(श्री अखिलेश यादव, मुख्य मंत्री जी के खड़े होने पर सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थप-थपाहट)

नोट [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बजट पर माननीय नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सतीश महाना, कांग्रेस दल के नेता श्री प्रदीप माथुर जी लोकदल के नेता श्री दलबीर सिंह जी, डा0 अयूब जी, डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी, श्री जाहिद बेग जी, श्री राम करन आर्य जी, श्री राम लाल अकेला जी, श्री राधे श्याम सिंह जी, श्री राकेश कुमार जी और अन्य 52-53 माननीय विधायकों ने अपने विचार और सुझाव रखे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सरकार का जो पक्ष था सरकार के माननीय सदस्य, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और मैं आज खड़ा हूं आपके बीच में। जो बजट मैंने पेश किया है 2014-1015, उसके पक्ष में और बड़ी संख्या में माननीय सदस्य जिन्होंने मुझे सुझाव भी दिये हैं, राय भी दी है और बहुत सारी अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है। जहां पर बात खत्म हुई थी पैसे को ले करके यह लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि पहला लोकसभा का चुनाव हुआ होगा जिसमें जितना मीडिया है चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे आपका इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, चाहे अखबार के माध्यम से मीडिया हो। इतने बड़े पैमाने पर प्रचार किसी दल ने नहीं किया होगा, जहां आखिरी बात खत्म हुई, उन्होंने किया और चुनाव के दौरान मैंने कहा आदरणीय अध्यक्ष जी कि अगर प्रचार पर इतना खर्चा होगा तो इससे भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वह अखबारों में भी आया है और वह जानकारी आ भी जायेगी कि आखिरकार कितना खर्च हो रहा है प्रचार में, तो प्रचार में अगर खर्चा होगा प्रचार के माध्यम से, सत्ता तो मिल गयी, मौका भी मिल गया क्योंकि केन्द्र सरकार में पहुंच गये, वह बिन्दु अलग है वह बहस अलग से छेड़ी जायेगी लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का बजट है यह तीसरा बजट मुझे जनता को, जनता के लिए रखने का मौका मिला है इस सदन में। इससे पूर्व भी मैंने दो बजट रखे हैं यह सौभाग्य मिला है मुझे कि मैंने तीसरा बजट रखा है। इससे पहले भी बहुत सारे बजट कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं उन्होंने भी रखे हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है उन्होंने भी अपने बजट रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उन्होंने भी अपने बजट रखे हैं। इसके साथ-साथ ऐसे बजट आये हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की मिल करके सरकार बनी थी उसके बजट आये हैं। जहां तक बजट का सवाल है मैंने अपने भाषण में पढ़ा था कि ''प्रथम चरण में नौजवानों के भविष्य को संवारने तथा उज्जवल बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने लैपटाप वितरण, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन आदि कुछ कार्यक्रम शुरू किये थे, जिसका अधिकाधिक लाभ नौजवान युवक-युवतियों को मिला है। अब दूसरे चरण में हमारी सरकार की योजना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्धन बस्तियों में जीवन की आधारभूत तथा मूलभूत सुविधायें मुहैया करायी जाय। इन कार्यक्रमों व अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने तथा पूंजी निवेश को प्रोत्साहित कर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं।'' और इसको मैंने इसलिए पढ़ा है कि बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने जब अपनी बात रखी है और खासकर नेता प्रतिपक्ष से जहां बात शुरू हुई उन्होंने नौजवानों का लैपटाप और तमाम जो योजनायें हैं उस पर बहुत बात रखी, कन्या विद्याधन पर कहा, बेरोजगारी भत्ता भी था हमारा और उसके अलावां दसवां पास बेटियों के लिए भी जो हमारी योजना थी वह हम लोगों ने 2 साल चलाई लगातार चली उत्तर प्रदेश में, बड़ी संख्या में नौजवानों को लाभ मिला बड़ी संख्या में नौजवान जो पढ़ना चाहते थे, लाभ मिला। लेकिन जिस लैपटाप को हम लोग कहते थे यह पढ़ने में आगे बढ़ने में मदद करेगा, शुरू का भाषण अध्यक्ष जी आप याद करिये लैपटाप का नाम आपने झुनझुना रखा था जब हम लोग लैपटाप देने जा रहे थे तब आपने झुनझुना कहा और जब

आपकी ही वजह से तमाम सुझाव तमाम राय और चुनाव के मैदान में जाने क्या क्या आपने लैपटाप के लिए कहा और उसके बारे में अब आपने फिर कहा झुनझुना क्यों वापस ले लिया। यह दुनिया ऐसी है इस समय कोई बात यहां से कही जायेगी दुनिया में जायेगी। अब आप यह सोचिये दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही होगी कि जहां लैपटाप को आपने झुनझुना कहा तो दुनिया में यह बात जायेगी तो आप समझ लीजिए झुनझुना जहां दे नहीं रहे थे अब झुनझुना आप भी मांग रहे हैं और जो नौजवानों को हमने दिया वह पढ़ने के लिए दिया, आगे बढ़ने के लिया दिया, रोजगार के लिए दिया और मैं इस सदन में कह सकता हूं कि देश की सबसे बड़ी सेकुलर और सोशलिस्ट स्कीम मैंने चलाई थी और समाजवादी सरकार ने सबसे बड़ी सेकुलर स्कीम, सोशलिस्ट स्कीम चलाई और इस स्कीम को मैं सोशलिस्ट, सेकुलर इसलिये कहता हूं कि यह बात इस बात से साबित है कि इस स्कीम में कहीं भेदभाव नहीं हुआ। अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन में यह बता दे कि इस स्कीम में कहीं भेदभाव हुआ हो। न जाति का न धर्म का, किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। जिस भी छात्र ने आगे पढ़ाई करने के लिये एडमीशन लिया, उसको समाजवादी सरकार की तरफ से लैपटाप देने का काम किया गया। इसलिये मैं कहता हूं कि यह सेकुलर स्कीम थी और सोशलिस्ट स्कीम मैं इसलिये बोलता हूं, जो माननीय सदस्य या जो लोग इस बात को जानते होंगे कि जिस समय इसके अंदर इंटरनेट लग जाये चाहे वह किसी तरह की इन्फारमेशन हो, जानकारी हो, पढ़ाई हो, उसकी पूरी की पूरी गैर बराबरी खत्म कर देता है। तो यह सोशलिस्ट और सेकुलर स्कीम हम समाजवादियों ने चलाई और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जो लैपटाप दिया गया है वह दिन के लिये नहीं दिया गया है। अब यह अलग बात है कि मैं नेता प्रतिपक्ष के पास बैठ नहीं पाता हूं, इनका मोबाइल नहीं देख पाता हूं हो सकता है कि इनको शौक हो कि हर तीन महीने बाद यह अपना मोबाइल बदल देते हों। हो सकता है यह शौक हो इनका। घर में बहुत सारी चीजें एक बार ली जाती हैं और वह कई वर्षों तक बनी रहती है। अगर आपने फ्रिज लिया होगा तो वह कई वर्षों घर में रही होगी, अब स्कूटर का जमाना नहीं है शायद आप कभी स्कूटर चलाये होंगे, अब मोटरसाइकिल का जमाना है। तो मोटरसाइकिल कई साल रहती है घर में। कार एक बार खरीदी जाती है तो कई वर्षों बनी रहती है। तो इसलिये माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि यह लैपटाप कोई एक दिन के लिये परिवार में नहीं पहुंचा, यह बरसों उस परिवार में रहेगा, मदद करेगा, पढ़ने का मौका देगा और सीखने का मौका देगा। बहुत सारे माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि अगर लैपटाप एक बार ले लिया तो चार-चार साल, पांच-पांच साल, आठ-आठ साल वह घरों में रहता है। उससे सब पढ़ते हैं और काम चलाते हैं। तो बताइये कि कितने परिवारों को हमने यह पहुंचा दिया। 15 लाख परिवारों में हमने इसे पहुंचाने का काम किया है और आपने कितनों का नुकसान किया है, इसमें आप दोनों लोग शामिल हैं और सच यह है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा कम है।

श्री सतीश महाना-

वास्तव में कांग्रेस पार्टी थोड़ा कम है।

श्री अखिलेश यादव-

लेकिन लैपटाप पर सबसे ज्यादा बुराई हुयी। इन्होंने छीन लिया और माननीय सदस्य खुद जानते होंगे कि किन-किन परिवारों में लैपटाप पहुंचा है। यह माननीय सदस्य शहर के हैं क्योंकि इनका भाषण जब भी सुनता हूं तो वह तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि यह उसमें हैण्डपम्प याद न

दिला दें। इसलिये मैंने माननीय मंत्री जी से राय ली और हमने तय किया कि मैं इनको हैण्डपम्प नहीं लेकिन एक पानी की टंकी जरूर दूंगा। आपकी पानी की टंकी को हमने स्वीकार कर लिया है हम विचार कर रहे हैं कि शहर में पानी की टंकी कैसे दें। यह ग्रामीण क्षेत्र का मामला है तो माननीय सदस्य आप जानते हैं कि यह किन-किन परिवारों में पहुंचा है। प्रतापगढ़ की चुनावी सभा में मैं गया था और मैंने वहां जानकारी की और जब मैं वहां गया तो एक पत्रकार मेरे साथ थे। मैंने उनसे कहा कि जाकर यह पूछो कि यह जो बच्चे खड़े हैं बाउण्ड्री पर, हेलीकाप्टर के बगल में खड़े हैं, क्या इनको इस सुविधा से लाभ मिला है कि नहीं मिला। तो वहां पर पत्रकार गये और उन्होंने पूछा और आकर मुझे बताया कि जिस बेटी को लैपटाप मिला है वह खुद सीख रही है और उसके परिवार में उसके पिताजी चलाते हैं, मां भी सीखने लगी है और भाई भी सीखता है अब बताओं आपकी इतनी सरकारें रही हैं, अगर परिवार के करीब कोई योजना पहुंची हो तो मुझे एक योजना बता दो जो लैपटाप के बराबर आपने पहुंचाई हो और फिर आपने तो सपना बड़ा दिखाया, माननीय सदस्य बहुत सीनियर हैं, आप जितना सम्मान उनका करते हैं उससे ज्यादा मैं उनका सम्मान करता हूं। वह आन्दोलन में बैठ गये कि बिजली मिलनी चाहिये। हमारी खिलाफत तो इसी बात को लेकर थी कि जितना हम बिजली दे रहे हैं इससे ज्यादा बिजली देने का वायदा आपने किया, जनता में यही तो आपने कहा कि हम बिजली 24 घण्टे दे देंगे। आपने तमाम वायदे किये, कानून व्यवस्था पर भी वायदा किया जो आपका सबजेक्ट नहीं था। देश की जनता नहीं समझ पाई कि कानून-व्यवस्था का सवाल इनका नहीं है, यह स्टेट सबजेक्ट है लेकिन देश के चुनाव में आपने वह भी मुद्दा बना लिया। बिजली का जहां तक सवाल है जितनी हम बिजली देते थे उससे ज्यादा ही बिजली की मांग थी, मैंने उनका पूरा सम्मान करते हुये उनकी बात मान ली लेकिन साथ ही साथ मैंने उनसे निवेदन भी किया कि कम से कम यदि उत्तर प्रदेश का कोटा नहीं बढ़वा सकते तो कम से कम बनारस का तो कोटा बढ़वा दो आप। मैं पूछना चाहता हूं जो सरकार में पहुंच गये हैं वह बताइयें कि कोटा कब बढ़ेगा उत्तर प्रदेश का क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुमत आपको मिला है। उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसके साथ-साथ तमाम जरूरतें हैं एक नई चीज आ गई है कि केन्द्रीय मंत्री ट्विटर पर बात करेंगे। मैंने चन्दौली की एक मीटिंग में पूछा कि ट्विटर क्या होता है, हम तो लैपटाप दे रहे थे आप तो ट्विटर पर पहुंच गये। मैं तो जानता नहीं हूं ट्विटर क्या है, अगर आप जानते हो तो हिन्दी में बता दो। वह सदस्य सिंगल है वह बता सकते हैं कि ट्विटर का मतलब क्या है। हिन्दी में ट्विटर को जानना चाहता हूं कि हिन्दी में ट्विटर को क्या कहते हैं।

श्री सतीश महाना-

किसी से संवाद करना, ट्वीट करने का मतलब है।

श्री अखिलेश यादव-

हिन्दी में बताइये।

श्री सतीश महाना-

अगर आप ट्वीट करना नहीं जानते तो कम्प्यूटर कैसे जानेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह नहीं कह पा रहे हैं। मैंने चुनावी जनसभा में पूछा कि यह ट्विटर क्या चीज है ? तो बहुत सारे लोग न बता पाये, मैंने सोचा कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 तो जानते होंगे लेकिन वहां से एक पत्रकार आया जो पीछे खड़ा था पत्रकार, उसने कहा कि ट्विटर का मतलब है कि चोंच लड़ाना। यह सभा की बात है, तो आपके मंत्री ट्विटर पर बात करना चाहते हैं।

(मेजें थपथपाई गई)

मा0 अध्यक्ष महोदय, जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं और चीजें कितनी बदल गई। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग बगल में हैं, बचकर रहिये चोंच उधर ही पहले आयेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 मुख्य मंत्री जी यह तो बता दें कि उसमें मर्दानी चोंच कौन सी होती है और जनानी चोंच कौन सी होती है।

श्री अखिलेश यादव-

यह तो पड़ोसी बतायेंगे कि क्या है, मा0 प्रदीप माथुर जी बतायेंगे। इसलिये जमाना बदला है और चीजें कैसे सुधरें दुनिया भर में जितने भी देश हैं वह चाहते हैं कि उनके देश में इन्वेस्टमेंट आये। उनके यहां चीजें आयें और आप जानते हैं कि आपकी पहली कैबिनेट का डिसीजन क्या था, देश की सरकार बनी तो उनकी कैबिनेट का डिसीजन क्या था, एफ0डी0आई0 एलाऊ कर देंगे आपके डिफेंस में। आप भी तो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिये लगातार काम करना पड़ेगा और मैं इस मौके पर मा0 अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगा कि अगर इस काम की बहुजन समाज पार्टी ने आगे बढ़ाया होता तो मैं उसको और आगे बढ़ा देता लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों की पांच साल सरकार रही अगर एक भी इन्वेस्टमेंट मीटिंग की हो तो बता दें, कोई समिट की हो तो बता दें आप, अगर दुनिया का कोई उद्योगपति, कोई एम्बेसडर आपसे मिलने आया हो तो आप बता दें। हम कहते हैं कि आपने झुनझुने से लैपटाप को बदनाम कर दिया, जब कानून-व्यवस्था का सवाल उठाते हैं तो केवल हम समाजवादी लोग ही बदनाम नहीं होते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता और पूरा का पूरा सदन बदनाम होता है। मुकदमें कैसे-कैसे उठाये आपने, ये तो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं ही, ये लोग तो आग लगा ही देंगे लेकिन प्रचार में जो सबसे आगे हैं, मैंने कहा, चुनाव में भी कहा और मैं आज भी कहता हूं कि अगर देश के राजनैतिक दलों में सबसे ज्यादा कोई राजनैतिक दल चालू हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। धन्यवाद दूंगा अपने डॉक्टर साहब का, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी का, ये कभी नहीं बदलते, इनके गले में जो दुपट्टे का रंग है वह हमेशा पड़ा रहता हैं गलती हो गई, इसको दुपट्टा न बोलें तो इसको क्या बोलेंगे। ये जो अंगौछा रखते हैं इसको यह हमेशा रखते हैं लेकिन चालू लोगों से पूछिये और जो मा0 सदस्य हैं, केवल आपको रोकने के लिये इन्होंने अपने गले में दुपट्टा डाला था, केवल आपको रोकने के लिये। तो जो विचारधारा है, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ यह सही है कि विकास पर आपने थोड़ा बहुत दिखाया लेकिन पूरा का पूरा इलेक्शन कम्युनल एज पर लड़ा था इन लोगों ने। इन चालू लोगों ने क्या किया कि इन्होंने पूरे देश में यह फैला दिया कि बदायूं का मामला जो हुआ है वह एक दलित परिवार है। राजनीतिक लाभ तो ले रहे थे ये

लोग, लेकिन उसका प्रचार झूठा किसने किया इन्होंने, और मिनस्ट्री आफ होम अफेयर्स भी कन्फ्यूज हो गयी। उन्होंने जवाब-तलब किया कि अगर दलित बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है तो अभी तक हरिजन एक्ट क्यों नहीं लगा? उसी का कारण है कि बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता भी बदायूं में आ गये। बताओ कोई राष्ट्रीय नेता वहां कब पहले आये थे? अध्यक्ष महोदय, यह मुझे जानकारी दे दें कि जितने राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग पहुंचे थे वह कब पहले आये थे। जो पूर्व में स्पीकर रहीं वह इससे पहले कब उत्तर प्रदेश आयी थीं, एक और मंत्री हैं वह कब पहले गये थे? बहुजन समाज पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं पीछे से फीडबैक दे रहे थे। अगर घटना हुई है तो हर आधे घण्टे में फोन किया जा रहा था हालांकि अब मैंने जांच सी0बी0आई0 को दे दी है। कोई सरकार हो, कोई मुख्य मंत्री हो इससे ज्यादा क्या कर सकता है, कानून के अंदर, इस काम के अन्दर जो मैंने किया है बदायूं में। मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछूंगा कि आप बताओ, इससे ज्यादा सरकार क्या करती, अगर एक भी डिसीजन में देरी की हो तो बता दो। कोई डिसीजन लेने में हमने देरी की हो तो बता दो और उसके बाद मैंने प्रशासन और अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अगर कोई घटना होती है, आपको प्रेस से जानकारी मिलती है तब पहुंचते हो, आपको प्रेस से पहले पहुंचना है, यह जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर किसी घटना पर पहुंचना है तो प्रशासन के लोग पहुंचेंगे और उसके बाद बदलाव आया है। इसलिए जो बदनाम करने का काम किया है वह दोनों लोगों ने मिलकर किया है। बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट आये। ये दूसरी चीज चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट आयेगा तो वह भी आपका मामला ठीक होगा लेकिन आप इन्वेस्टमेंट आने ही नहीं देना चाहते हैं। हमने आगरा समिट की और एक माहौल बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने तथा पहली बार उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने पालीसीज बनायी। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वह कैसे इन्वेस्ट करता। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का बाजार आज अंडों का, मैंने कई बार कहा इस सदन में कि 2 करोड़ अंडे प्रतिदिन खाये जाते हैं उत्तर प्रदेश में, यह बाजार है हमारा। अगर स्कीम किसी ने बनायी है ''पोल्ट्री स्कीम'' तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनायी है और उसकी वजह से बहुत सारी यूनिट्स उत्तर प्रदेश में लगने लगी हैं। आप में से किसी माननीय सदस्य ने कहा कि दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, मैं स्वीकार करता हूं। गुजरात की कम्पनी अमूल जो उत्तर प्रदेश में आ रही है वह किसी की मेहरबानी पर नहीं आ रही है, उन्होंने देखा की उत्तर प्रदेश का बाजार बहुत बड़ा है और सबसे पहले मैंने उसको लाने का काम किया है, कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। जब किसी का नाम भी नहीं था तब मैं अमूल को लेकर उत्तर प्रदेश में आया और मैंने उनको जगह दी है। माननीय सदस्य जानते होंगे कानपुर देहात में काम शुरु हो गया है और अमूल का प्लाण्ट लगने वाला है। वह सिफारिश मैंने खुद किया और अमूल के जितने भी डायरेक्टर्स हैं और सीनियर मेम्बर्स हैं, वह वहां पर आये थे और वहां पर लगना शुरु हो गया है। इसी तरह से लखनऊ के चक गंजरिया में मैंने उनको 25 एकड़ जमीन दी है वह भी लग जायेगा उसके बाद बनारस में अपने-आप लगेगा। हमने इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने का काम किया है। हमने दूसरी समिट की इन्वेस्टर्स मीट, चुनाव के बाद की मैंने। मुझे खुद लगता था कि पता नहीं इन्वेस्टर्स आयेंगे की नहीं आयेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आया था। लेकिन उसे बावजूद भी जितनी बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स आये हैं, मै बधाई देना चाहता हूं। मैंने वहां भी धन्यवाद दिया है और इस सदन के माध्यम से मैं आपकी तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि

इतनी बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स मीट में तमाम उद्योगपति आये। जो आगरा समिट हुई थी उसमें कोई एम0ओ0यू0 साइन करने की बात नहीं थी। उसमें तो हमने केवल अपनी पालिसी उनके बीच रखी थी। आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना शुरु हुआ है मैं आपको भरोसा दिलाता हूं क्योंकि कांग्रेस के हमारे सीनियर सदस्य मा0 प्रदीप माथुर जी सम्मेलन में थे वह जानते होंगे कि किस तरह से इन्वेस्टर्स ने बात कही उत्तर प्रदेश के बारे में और जो 60 हजार करोड़ से ऊपर के एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार लगातार फालो करेगी और हमारे अधिकारी लगातार फालो करेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए। इण्डियन आयल के लिए एक्सपेंशन चाहते हैं जमीन नहीं मिलेगी एक्सपेंशन कैसे कर लोगे। गेल अथारिटी के लोग भी जमीन चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। तब जाकर इन्वेस्टमेंट आ पाएगा। जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो जाब अपारच्यूनिटी मिलेगी नौकरियां मिलेंगी। यह काम तो कम से कम समाजवादी सरकार ने शुरु किया है। सोलर इनर्जी के लिए कोई आपकी पालिसी नहीं थी सोलर एनर्जी में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। केन्द्र सरकार की जो एन0एच0पी0सी0 है उसने भी उत्तर प्रदेश सरकार से समझौता किया वह भी जालौन में प्लांट लगाने जा रहे हैं। ललितपुर में सोलर प्लांट लगने जा रहा है। यह जो इन्वेस्टमेंट मीट हुआ है उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार काम करना पड़ेगा एच0सी0एल0 जो नोयडा दिल्ली से बाहर नहीं जा रही थी एच0सी0एल0 दुनियां की मानी हुई कम्पनी है। वह कम से कम लखनऊ में तो आ रही है। लखनऊ में एक आई0टी0 सिटी उन्होंने लिया है। पर्यावरण क्लियर करने की जितनी एन0ओ0सी0 चाहिए थी वह हम उनको दे रहे हैं। यहां लखनऊ में आई0टी0सिटी बनेगी। कम से कम हमने नोयडा से दिल्ली से इन्वेस्टमेंट यहां पर लाने का काम किया है। इसी तरह से इन्फोसिस कम्पनी कभी नार्थ इण्डिया में नहीं आई उन्होंने 25 एकड़ जमीन ली है हमारे माननीय सदस्य लोग जानते हैं इन्फोसिस आना चाहती है। मोबाइल जो बाजार में चल रहा है सैमसंग के लोग बड़े वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें। उनका भी एक्सपेंशन होने जा रहा है। यदि किसी ने माहौल बनाया है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी सरकार ने बनाया है जिस वजह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। याद कीजिए नेता जी की सरकार थी आप भी उस समय अध्यक्ष थे जो शुगर मिल प्लांट लगे, को जनरेशन पालिसी बनी, टाटा का प्लांट और तमाम प्लांट उत्तर प्रदेश में लगे। उत्तर प्रदेश में था गोरखपुर में जो प्लांट लगे आप जानते होंगे वह इसीलिए लगे क्योंकि पालिसी थी पालिसी से लाभ लेकर यहां माहौल बना था मैं पूछना चाहता हूं कि पांच साल में इन्होंने कौन सी इन्वेस्टमेंट मीट की कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आए जो पालिसी चल भी रही थी उसको अगर किसी ने भी खत्म किया है तो यही बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने खत्म किया है। मैं चुनाव में सुनता था मुझे बताया गया कि भाषण दिया गया अखबारों में निकला है इंडिया टुडे में बहुत पहले एक बार निकला था तब मैंने उसको नजरअन्दाज कर दिया इनकी बहुजन समाज पार्टी की नेता ने हम लोगों के लिए कहा कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न होते तो मुख्य मंत्री गाय भैंस चरा रहे होते। यही तो आपका स्टेटमेंट था इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब तो जान जाएं कि अमूल आ रहा है पराग आ रहा है। इनको जानकारी होनी चाहिए मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट डेयरी का बाजार यह जान जाएं देश के जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनका जितना टर्न ओवर होगा उससे ज्यादा मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट का उत्तर प्रदेश में टर्न ओवर है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से कहूंगा कि यह जानकारी कहीं देना मत अगर आपने जानकारी दे दी तो हो सकता है कि वह हाथी छोड़कर गाय भैंस

पाल लें क्योंकि मुनाफा दूध और उसके प्रोडक्ट में ज्यादा है। जहां तक सवाल है इन्वेस्टमेंट का समिट का यह लगातार काम करना पड़ेगा। हर मुख्य मंत्री हर सरकार इसी तरह से काम करती है। और माहौल बनाना पड़ता है कि आपके प्रदेश में आएं मुझे जानकारी मिली कि बड़ी-बड़ी कम्पनियां आपके प्रदेश में है। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है चाहे वह अमेरिका की हों, इंग्लैण्ड की हों चाहे जापान की हो चाहे ताईवान बहुत सारी कम्पनियां जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट चाहती है हमने उन्हें मौका दिया है और आश्वासन भी दिया है कि अगर हमें कोई सिटी बनानी पड़ेगी हमें अगर कोई आई0टी0 हार्डवेयर सिटी बनानी पड़ेगी या अलग से इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलप करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी सरकार पीछे नहीं हटेगी। उसको बढ़ावा देगी। माननीय सदस्य असीजा जी बैठे हुए हैं वह कभी गये होंगे वह इलाका जिसकी जमीन को कोई पूछता उस जमीन पर हम लोगों ने इण्डस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं शायद आपकी जानकारी में इण्डस्ट्रियल टाउन बने तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। यह सही है कि थोड़ी देरी जरुर हुई उसको इस स्तर पर लाने के लिये क्योंकि उसके पीछे जो एक्सरसाइज चली उसके कारण हम लोग थोड़ा पिछड़ गये और जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, जिसके लिये मैंने 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बजट रखा है। सप्लीमेन्ट्री में भी रखा था क्योंकि लैंड एक्वीजिशन एक्ट बदल गया है, जमीन के लिये पैसा देना पड़ेगा। हालांकि एक एक्सप्रेस वे आपने भी बनाया था। जब मैं साइकिल से निकला था तो आपने चढ़ने नहीं दिया था। जब चढ़ने नहीं दिया था तो मैंने कहा था, हमारे तमाम नौजवान साथियों ने कहा था कि आज चढ़ने नहीं दे रहे हैं कल ऐसा दिन भी आयेगा जब आपको उद्घाटन करना पड़ेगा। तो उद्घाटन हम ही ने किया (मेजें थपथपाई गई) और उसी के कारण देरी हो गई। इन्होंने इतना स्वीटनर दिया, इतना स्वीटनर दिया कि बिना स्वीटनर के कोई उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहता। बताओ कितना बड़ा लैंड पार्सल दे दिया आपने छोटी सी सड़क पर। लेकिन चलो अच्छा हुआ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कुछ तो बना यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे सरकार बना रही है और आपकी गलत नीति की वजह से पी0पी0पी0 पर हम वह सड़क नहीं दे पाये। मैं जानता हूं सड़क बनने से और भी बहुत से लोग जानते हैं, आपने इंगलिश में सही कहा था उस सड़क को ले करके। उन्होंने कहा ठीक कहा। इसलिये सड़क बना रहे हम लोग कि जिस समय वह सड़क बन जायेगी न केवल इन्डस्ट्री, न केवल शहर बल्कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ मिलेगा और इसलिये लाभ मिलेगा कि आज जरुरत है ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर की। आज दिल्ली में आपकी कांग्रेस सरकार थी जाने कितनी बार आन्दोलन करना पड़ा कि यह फल सब्जी महंगी है। यह फल सब्जी दिल्ली के लिये महंगी है, मुम्बई के लिये महंगी है, बड़े शहरों के लिये है। हमारे बहुत सारे सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे। जो महंगाई वहां पर है वह उनके क्षेत्र के आस पास महंगाई नहीं होगी। अगर वहां कोई सब्जी महंगी है, तोरई, लौकी अगर महंगी है वहां पर तो यह जरुरी नहीं है कि उनके गांव के पास महंगी हो। सवाल यह है कि बस माल नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर। अगर दिल्ली में दूध महंगा है तो यह जरुरी नहीं है कि वह लखनऊ के एक कोने में भी दूध उतना ही महंगा हो। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को भेजा था और यह कहा कि यूरोप की रुगींस सबसे बड़ी मंडी है, उसको देखकर आयें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो पी0पी0पी0 में नहीं बन पाया वो मैं स्टेट बजट से बना रहा हूं। और स्टेट बजट से बनाकर साथ-साथ किस तरीके से एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडेक्टस और फूड प्रोसेसिंग पालिसी के तहत लोग आयेंगे और इन्वेस्ट करेंगे और कम से कम बाजार में वह चीजें समय से पहुंचेंगी। इसलिये हमने यह लिया और देरी

इसलिये हुई क्योंकि इन्होंने स्वीटनर के बहाने बहुत सारा लैंड पार्सल दे लिया। हम नहीं ले सकते किसानों की जमीन, मुकदमा नहीं चला सकते किसानों पर। आपकी सरकार में जाने कैसे-कैसे गम्भीर धाराएं लगी कई वर्षों किसान नेता जेल पर रहे। उनके मुकदमें किसी ने वापिस लिये तो समाजवादी सरकार ने लिये। कोई किसानों पर लाठी नहीं चला रहे। किसानों से आम सहमति करके कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आम सहमति बना कर करके वह हाई वे बन जाय। वह बनेगा हम लोग बनाना चाहते हैं और उसके लिये 3 हजार करोड़ रुपये रखे हैं। उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा और जो बात आपने कही थी उसी बात मैं कह सकता हूं कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकानमी। अगर आप रफ्तार बढ़ा सकोगे तो आप अपनी इकानमी एक्टीविटीज को बढ़ा ले जाओगे क्योंकि दुनिया में जितने मुल्क तरक्की किये हैं वह जब तक उनके यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ और खासकर सड़क। जो अमेरिका के लिये कहते हैं कि कभी अमेरिका ने सड़क बनाई और उस सड़क ने अमेरिका को बनाया। इसलिये सड़क बहुत जरुरी है। जिस समय सड़क बनेगी और एनएचएआई जो आपने बनाया है। आप तो खुद जानते होंगे इस बात को एनएचएआई जो बना है नेशनल हाई वे एथारिटी आफ इंडिया जिससे हाई वे बने गोरखपुर का बन गया बहुत सारे चुनाव में हम यही बताना भूल गये कि यह नेशनल हाई वे किसका है। स्टेट का है कि सेन्टर का है। गोरखपुर से अगर बनारस की सड़क खराब है तो उसके लिये दोषी समाजवादी पार्टी ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सड़क नहीं है वो। लेकिन वो बता ही नहीं पाये। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया कि यह समाजवादियों की देन थी। और देन थी नेशनल हाई वे की, देन थी केन्द्र सरकार की। उन्होंने सड़क ले ली और बनाई ही नहीं। बताओं कहां बनाई सड़क। आपने पैसा ही नहीं दिया उसको। वो तो छोड़िये आपने अपनी सुल्तानपुर वाली रोड का पैसा नहीं दिया। आप कानपुर से अगर लखनऊ आते होंगे तो बताइये क्या हालत है। अरे कम से कम अब तो दिलवा दो पैसा। देखें कब तक बनेगी ? इनके बीच में सड़क बन रही जब मैं सांसद था, तब बनते हुए देख रहा था मैं वह सड़क और अभी भी वह सड़क बन रही है।

बताइये, रामादेवी चौराहे के पास वह सड़क अब भी बन रही है या नहीं बन रही है? कितने वर्षों से बन रही है, बताओ ? हम, लोगों को बता ही नहीं पाए कि यह सड़क एनएचएआई की है, हमारी सड़क नहीं है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया। कितना पैसा मेन्टीनेंस के लिए दिया? कुछ भी नहीं दिया। मैंने पत्र लिखा है क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि सड़क अच्छी बने, रायबरेली तक तो फोर लेन है, उसके बाद फोर लेन है ही नहीं। मैंने पत्र लिखा है, कोई जानकारी चाहे तो मैं दे सकता हूं, रायबरेली तक तो फोर लेन है लेकिन उसके बाद फोर लेन नहीं बनी है। इसी तरीके से कानपुर से लेकर हमीरपुर वाली रोड एनएचएआई में है, वह हमारी सड़क नहीं है लेकिन कितना बुरा-भला हुआ, हम वोट के मामले में पीछे रह गए। तो नेशनल हाईवे में पैसा ही नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, वह सब रिकार्ड पर है कि कितना पैसा मिला, कितना नहीं मिला, चाहेंगे तो मैं नेशनल हाई वे का दे सकता हूं कि मेंटीनेन्स के लिए कितना पैसा दिया। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जो पैसा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला और बुराई हुई, उत्तर प्रदेश सरकार की। बिजली के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमीरपुर के पास नेवली लेग्नाइट का लगा था, मैंने उस समय के केन्द्रीय मंत्री जो कोयला के थे, उनके साथ मिल करके करार किया था, कोयला नहीं मिला बिजली नहीं बनी। इसी तरह 9 एम0ओ0यू0 इन्होंने साइन किये कोयला ही नहीं मिला तो इन्होंने जो गलती की, उसकी सजा जनता ने दी है, उनका तो 10 परसेण्ट वोट कम हो गया, इनका 8 परसेण्ट कम हो गया,

हम फिर भी बच गये, 01 परसेण्ट ही हमारा कम हुआ। सवाल यह है कि इन्होंने 9 एमओयू साइन किए, कम से कम उत्तर प्रदेश की यह सरकार जब से बनी है, दोनों प्लान्टों को हम लोगों ने लगाना शुरु कर दिया, चाहे वह बारा का हो, चाहे ललितपुर का हो। एमओयू जरुर साइन किया, न कोयले का इन्तजाम किया, न पानी का, न सड़क का, इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो बिजली के क्षेत्र में हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं, जनरेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। परीछा में जो नेता जी ने शुरु किया था, यूनिटें, वह अब बन कर तैयार हो गयी है, 500 मेगावाट वहां से बढ़ करके बिजली आ रही है। पनकी पर हम लोग लगाने जा रहे हैं। इसी तरह से हरदुआगंज में जो नेता जी ने लगाया था वह अभी चालू हुआ है और आगे भी उसको बढ़ाने जा रहे हैं, पनकी को। हरदुआगंज भी चालू हो गया है, वहां भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रान्समिशन लाइनें बेहतर हों, तहसील स्तर पर फीडर कैसे अलग हों, तहसील स्तर पर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सब-स्टेशन बने हैं। तहसील स्तर पर सब-स्टेशन बन रहे हैं, यह माननीय सदस्य जानते होंगे, लगभग 800 करोड़ की लागत से वह स्कीम चल रही है। तो कम से कम तहसील स्तर पर फीडर सेपरेट कर रहे हैं और मुख्य रुप से 3 जिले मैंने लिए हैं-मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, जहां पर पूरा का पूरा फीडर सेपरेट कर दे रहे हैं, आपके किसानों को चलाने के लिए ट्यूबवेल भी। फीडर सेपरेट हो जायेगा तो निश्चित रुप से जितने घण्टे बिजली देनी है, हम दे सकेंगे, फीडर सेपरेशन का काम चल रहा है। केशियन बिडिंग पर हमने बिजली खरीदने का इन्तजाम किया है, 2 हजार मेगावाट से ऊपर और भी अगर मिलेगी तो सरकार विचार करेगी। हम जनरेशन बढ़ा रहे हैं, नेता जी ने श्रीनगर में जो प्लान्ट लगाया था, 330 मेगावाट का, वह ट्रान्समिशन लाइन इन्होंने पांच साल नहीं लगायी, कम से कम हमने लगा दी, केवल थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, जिस दिन लग जायेगी, केवल एक तार जोड़ना है बस, एक खम्भे पर, जिस दिन जुड़ जायेगा, उसी दिन उत्तर प्रदेश में 330 मेगावाट के लगभग बिजली आ जायेगी। यह एक हफ्ते में भी हो सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। तो बिजली व्यवस्था को कैसे बेहतर करें और समाजवादी सरकार ने तय किया है कि वह 2016 से गांवों में 18 घण्टे और शहरों को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करायेगी। यह बड़ा फैसला है और यह तब करने जा रहे हैं, जब केन्द्र सरकार से कोई भरोसा नहीं है कोयला मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है, तब करने जा रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में हमने काम किया है, इसीलिए जो हमारा बजट है, उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है। हेल्थ के सेक्टर में बेहतर किया है, मेडिकल कालेजेज चालू किए हैं, 500 एमबीबीएस की सीटें किसी सरकार ने नहीं बढ़ायी होंगी, लेकिन हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 500 सीटें बढ़ा दी हैं, जो नए मेडिकल कालेज बन रहे हैं। यूनीवर्सिटी एक आपके क्षेत्र में बन रही है, एक इलाहाबाद में बनने जा रही है और नेता प्रतिपक्ष ने अपने ही दोस्त और सहयोगी की यूनीवर्सिटी नहीं बनने दी, उस फाइल को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया।

अध्यक्ष महोदय, उस फाइल को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया कम से कम प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी बनाने के लिए मौका दे रहे हैं। हमारे मा0 मंत्री जी भी अपने रामपुर में बना रहे हैं। वह एक शानदार यूनिवर्सिटी है। मुझे भी जाने का मौका मिला है। वह यूनिवर्सिटी बन रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और सरकार की यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज भी बना रहे हैं। पालिटेक्निक भी, आई0टी0आई0 भी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बंद पड़ा था शुरु ही नहीं किया था। कम से कम जब हमारी सरकार आयी तो हमने शुरु किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 40 लाख से ज्यादा आनलाइन रजिस्ट्रेशन बच्चों ने किया है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

वैसे यह भी गिनीज बुक आफ रिकार्डस में होना चाहिए कि हिन्दुस्तान में आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था पर बुल्डोजर चलाया है तो वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने चलाया है।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार काम कर रही है। रोजगार का सवाल उठाया। मान्यवर, रोजगार दिया है। इन्वेस्टमेंट भी आया है। वह हमारे एक मा0 सदस्य बोल चुके हैं कि किस तरीके से स्माल स्केल इंडस्ट्री आयी है, कितनी नौकरी उसमें मिली है। आप चाहेंगे तो मैं पढ़ सकता हूं। इसलिए उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। जहां तक पढ़ाई टी0ई0टी0 का प्रश्न है। तो टी0ई0टी0 को अगर किसी ने उलझाया है छात्र, नौजवान अगर उसमें नौकरी नहीं पा पाये हैं तो उसको उलझाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो यह बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। इन्होंने उलझा दिया। हमारे मा0 मंत्री जी जानते होंगे कि कितना लड़ना पड़ा। टी0ई0टी0 के छात्र जब जनता दरबार में आते थे तो किस तरीके से वह नौजवान आते थे। और जो परीक्षा करायी थी और आज के जमाने में इन्होंने मैनुअल परीक्षा करायी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का पूरा का पूरा निर्देश मान रहे हैं। मैनुअली हमें दोबारा उसका डेटा फीड करना पड़ रहा है। आप जानते होंगे मा0 मंत्री जी। जितने बच्चों ने टी0ई0टी0 लिखी उनका पूरा का पूरा डेटा कम्प्यूटर पर फीड करना पड़ रहा है। और जो लोग टी0ई0टी0 करा रहे थे उनकी गाड़ियों में कानपुर देहात में क्या पकड़ा गया था आप जानते होंगे। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी जानते होंगे कि गाड़ी में क्या पकड़ा गया था। और जेल में भी जाना पड़ा था। तो अगर किसी ने इन नौकरियों को उलझाया है तो आपने उलझाया है। अब तक जो वह नौकरी पा जाते, हम आगे बढ़ जाते। हम लोगों ने उर्दू मोअल्लिम में नौकरी दे दी। शिक्षा विभाग में कम से कम 25 हजार नौकरियां दी है। और आगे जाकर यह एक लाख हो जाएगी और भर्ती भी होने जा रही है। यही लोग बेरोजगारी भत्ता का विरोध करते थे। आप न जाने बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या-क्या कहते थे। अब हम नौकरी दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बेरोजगारी भत्ता और वो बच्चियां वह परिवार जिन्होंने 30 हजार रुपये एक वक्त में नहीं देखे थे। खजाने से जाते थे इनकी वजह से।

श्री अखिलेश यादव-

आप लोगों ने वादा किया है। इससे भी बढ़कर देंगे। मैं देख रहा हूं कि लैपटाप से बढ़कर क्या मिलने जा रही है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

पहले उस महिला को न्याय तो दिला दीजिए जिसने एक केंद्रीय मंत्री जी पर बलात्कार का आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य शांत रहें। मा0 मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव-

आपने कहा कि रिक्शा नहीं मिल पाये हैं। क्योंकि सरकार ने जिस रिक्शे को देने की बात कही है वह रिक्शा मोटर से चलने वाला है, जिसमें पैडल नहीं होगा। तो इसके लिए कार्रवाई चल रही है। क्योंकि मोटर एक्ट में परिवर्तन होना है। केन्द्र सरकार से मैं समझता हूं कि अब रास्ता निकल गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उसके लिए धन्यवाद।

श्री अखिलेश यादव-

जब पूरा रास्ता निकाल लेंगे तो धन्यवाद दे देंगे। क्योंकि मोटर एक्ट हमारे अंडर नहीं आता। वह केन्द्र सरकार के अंडर आता है।

...तो गरीब रिक्शा चलाने वालों को फ्री रिक्शा मिल जायेगा, यह भी अच्छा हुआ आपने रिक्शा पहले नहीं बांटा, नहीं तो चुनाव में कोई न कोई नई बात यह कहते, तो गरीबों का कम से कम रिक्शा तो बच गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पूछ लीजिए अगर यह न चाहें तो अब भी रोक दें।

श्री अखिलेश यादव-

तो रिक्शा भी मिलने जा रहा है, चूंकि टेक्निकल मामला है, उसको ठीक करने में समय लग गया है, इसलिए हम लोगों को देरी हो गई है, लेकिन उस ऐक्ट में अगर एलाउ कर देंगे उन कम्पनीज को तो आपके उत्तर प्रदेश में आप रिक्शा देखेंगे, जो मुफ्त रिक्शा, रिक्शा चलाने वालों को मिलेगा। इसके साथ-साथ आपने कहा कि हमने, समाजवादी लोगों ने लोकतंत्र सेनानियों के पेंशन मद में कोई व्यवस्था नहीं की है, लगता है इस पर भी खतरे की घण्टी है, आप अगर पूरे बजट की जानकारी करते, तो आप जानते कि यह मिलने जा रहा है और मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि हम लोग इसे बढ़ाने जा रहे हैं और आपकी सरकार तो वह है जिसने इसे बन्द कर दिया था। इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 अगर कोई परेशान करता है फोन काल से मैसेज से, मैंने पहले भी भाषण में कहा आपकी सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, 1090 से कम से कम महिलाओं की यह शिकायत दूर की और बहुत सारी माताएं-बहनों की परेशानी दूर की और विशेषकर महिलाओं पर और क्राईम अगेन्स्ट वूमेन पर अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए अलग से सेल, अलग से महिला अधिकारी को हमने पोस्ट किया है और विभाग भी बना दिया है, कहीं भी यदि घटना होगी, कम से कम सरकार और सरकार के अधिकारी इतने सेंसिटिव है कि मौके पर जा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे झूठे प्रचार का मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उत्तर प्रदेश में घटना होती है तो मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर के प्रचार किया जाता है। हमने कई चैनलों को देखा है, अगर उत्तर प्रदेश में घटना हो जाय तो फोटो लगाई जाती है मुख्यमंत्री की, आपके नागालैण्ड में घटना हुई, मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हो टी0वी0 पर तो बता दो, आपके राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में घटना घटी है तो मुख्यमंत्री की कहीं तस्वीर/फोटो लगी हो तो बता दो आपके कर्नाटक में घटनायें हुई हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई गई हो तो बता दो आप, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ लेकिन उत्तर प्रदेश में

जब कभी घटना होगी तो सबसे आगे मुख्य मंत्री की तस्वीर होगी, उनका नाम होगा कि उनकी सरकार में यह हो रहा है। हमारे मा0 मंत्री जो सदस्य थे उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किये। हालांकि ऐसी घटनाओं पर अगर हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो हमें भी दुख होता है कि आखिरकार ये घटनायें क्यों हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बदायूं की जब घटना हुई तो बताया कि इटावा में भी एक घटना हुई इसी तरह की और आजमगढ़ की भी घटना दिखाई टी0वी0 पर। मैं पूछना चाहता हूं वह कौन सी घटना थी इटावा की और आजमगढ़ की भी झूठी निकली, हमीरपुर की भी झूठी निकली, बहराइच का मामला दूसरी तरीके का था, इसलिए कानून व्यवस्था के सवाल पर कोई समझौता नहीं, लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है और कोई भी सरकार हो, किसी प्रदेश की आप जानकारी कर लेना क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही है। मैंने खुद पत्र लिखा है कि क्राईम अगेन्स्ट वूमेन में अगर कोई कार्रवाई होनी है, अगर मुझे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की अनुमति मिल जायेगी, उसके लिए भी हमने चिट्ठी लिख दी है, जिससे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले का जल्द निस्तारण होकर उनको सजा मिले और सख्त से सख्त सजा मिले, इस पक्ष में समाजवादी सरकार है, इसलिए सेंसिटिव है सरकार और स्ट्रिक्ट ऐक्शन के लिए तुरन्त कार्रवाई कर रही है सरकार इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करुंगा कि जब इन्वेस्टमेण्ट की इतनी एक्सरसाइज चल रही है यहां हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेण्ट आयें, अगर कानून व्यवस्था के सवाल पर आप तमाम ऐसी बातें कहते हैं जिससे कि छवि उत्तर प्रदेश की भी बनती बिगड़ी है, सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए छवि आपके हाथ में भी है और कई बार राजनैतिक लाभ लेने के लिए लोग घटनायें बताते हैं, आप बताओ बदायूं की घटना में आपके नेतृत्व के लोग क्या कर रहे थे, आपकी पार्टी के लोग, क्या लगातार जानकारी नहीं दे रहे थे, अब तो लाई डिटेक्टर के अन्दर वह कार्यवाही चल रही है, सी0बी0आई0 अपना निर्णय लेगी, हमने सी0बी0आई0 के अण्डर में दे दिया, इसलिए जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है, सरकार काम कर रही है और सख्ती से काम कर रही है, इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं, न भेद-भाव होगा, यह मैं भरोसा दिला सकता हूं मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन को।

जहां तक, चूंकि सारे सवाल उठाये कि कृषि में कोई बजट नहीं है। तमाम सवाल आये कि कृषि पर नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है। आप पूरी जानकारी अगर करेंगे तो आप पायेंगे कि गांव, गरीब और किसान के लिये, कृषि के लिये अगर सबसे ज्यादा बजट किसी ने दिया है तो इस समाजवादी सरकार ने दिया है। इसके साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, सड़क, बिजली, पानी में इतना बजट अगर किसी सरकार ने दिया हो तो बता दो आप। कभी किसी सरकार के बजट में इतना पैसा दिया गया हो तो बता दें। हमारे मा0 सदस्य वह भी बैठे हैं जिनका बहुत दिन पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग रहा, ये पीछे वाले। आप तो सड़क बनाते हो, इंजीनियर रहे हैं। जो बात आपने उठायी थी मा0 सदस्य पीछे से उसकी क्वालिटी क्या हो। हम भी यही सोचते हैं कि क्वालिटी क्या हो सड़क की क्योंकि इंजीनियर साहब बैठे हैं वे जानते होंगे जो सड़क आपकी सरकार में आखिरी बनी होगी। जो सड़क आपकी सरकार में आखिरी समय में बनी होगी तो कितनी लाइफ होनी चाहिए उसकी। कम से कम 4 साल तो चलनी चाहिये। कितने साल की गारण्टी होनी चाहिये पी0डब्ल्यू0डी0 बतायेगा। इन्होंने कौन सी सड़क बनाई थी जो 5 साल से पहले चली जा रही है इसलिये हम लोग कम से कम क्वालिटी तो ठीक कर रहे हैं और आपकी सरकार ने कोई फोर लेन का प्रोग्राम बनाया हो तो बता दें। कम से कम समाजवादी सरकार ने फोर लेन बनाने का काम तो शुरु कर दिया। शक्ति नगर और वाराणसी जोड़ने वाली सड़क स्वीकृत की कि नहीं की। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके आप चले गये।

ओप्सा-ओबिडा बनाया समाजवादी सरकार ने, हमारी सरकार में यह बन रही है कि नहीं बन रही है। मुरादाबाद और संभल में फोर लेन सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है। मुरादाबाद, संभल वाले मंत्री जी जानते होंगे। इटावा-मैनपुरी सड़क बना रहे हैं, मदर डेरी का प्लाण्ट शुरु हो गया है, बाबतपुर-भदोही बनने लगी है, बाबतपुर-भदोही वाले जानते होंगे, सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

बलिया को भी कुछ दिया है।

श्री अखिलेश यादव-

अरे, बलिया को भी दे देंगे। बलिया को तो सबसे ज्यादा बजट दिया है यदि याद रखें आप, आपको जानकारी नहीं है। हमारे मा0 सदस्य अम्बिका जी, मंत्री बता देंगे। बलिया के मा0 सदस्य हमारे मंत्री हैं, ये जानते हैं, सबसे ज्यादा अगर देखोगे प्रदेश के जिलों का बजट, सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो बलिया में दिया है पिछली बार बलिया और गाजीपुर और जो बनारस में सड़कें बनी है, जो बनारस में अच्छी सड़कें बनी हैं, पेण्ट भी हो गयी। मा0 सदस्य अगर आप बनारस गये होंगे तो कहीं झटका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ आप। ये दोनों लोग हैं, इन्होंने सड़क बनायी है अच्छी कि नहीं बनायी। आपके फ्लाई ओवर की डिजाइन क्या थी, बता दो मा0 सदस्य, आप बैठे हैं, उस समय इंजीनियर रहे होंगे। क्या एक-आध फ्लाई ओवर की गलत डिजाइन है कि नहीं है। काम हो रहा है काम शुरु कर दिया है। कुशीनगर और बहराइच के लिये मैत्री बजट आया कि नहीं आया, सड़क भी आयेगी। मैत्री बजट आया कि नहीं आया बताइये। कितने वर्षों से, जाने कितने वर्षों से रुका पड़ा था। वह हमने क्लियर किया है और कहीं भी किसान को एक भी जगह आंदोलन नहीं करना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सहयोग कर देते तो वह मैत्री बजट और बड़ा हो जाता। देवरिया वाले हमारे जानते होंगे बताओ कहीं पूरे विकास में भेदभाव किया है क्या, उन्होंने मदद की कि नहीं की तो मदद कर हैं कहीं न कहीं और जहां तक पूर्वांचल निधि का सवाल है तो ये नेता जी ने शुरु की थी और नेता जी के माध्यम से इसलिये अगर कहीं कोई स्पेशल केस है, कहीं कोई और कुछ अलग से देना पड़े। किसी विशेष योजना में देना पड़े या विशेष डेवलपमेण्ट के लिये देना पड़े तो हम उसको दे देंगे उसके माध्यम से तो ये नेता की शुरु की गयी है लेकिन चूंकि बजट पी0डब्ल्यू0डी0 का या और शिक्षा विभाग का, बिजली विभाग का या सब विभागों का अगर मिला दोगे तो सबसे आगे अगर बजट में कोई होगा तो वो पूर्वांचल का इलाका ही होगा जिसको बजट में किया है। अगर जहां तक सवाल है डेवलपमेण्ट का तो बहराइच से श्रावस्ती सड़क फोर लेन बन रही है कि नहीं बताओ और जितने भी गंगा के पुल है पूरे होना शुरु हुये हैं इस सरकार में। प्रतापगढ़ के लोग बैठे होंगे, नेता जी प्रतापगढ़ को पुल दिया था गंगा का और वह 5 साल बना ही नहीं इनकी सरकार में। वह जाकर के अभी पूरा हुआ है। अब बना है जाकर के गंगा पर चलने लगा है।

...कितने वर्षों से बन रहा है पता नहीं कौन लोक निर्माण मंत्री थे, उस समय जब दिया गया था ये पुल, अब वे केन्द्र में मंत्री है, उन्होंने दिया था। जब कभी काम हुआ है उस पुल पर तो समाजवादी सरकार में हुआ है, वह भी पुल बनने जा रहा है। इसी तरह शास्त्रीपुल पर मिर्जापुर में दो हैं, एक चुनार पर है और एक दूसरे घाट पर है। दोनों बताइये किसने दिये, हम लोग काम शुरु कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं यहां पर। यह बहुत आरोप लगाते हैं, मैगजीन की बातें पढ़कर

हमारे पर आ जाते हैं कि साढ़े चार मुख्य मंत्री हैं, साढ़े पांच मुख्य मंत्री हैं। अब ये पुल तो मैंने उनसे पूछे नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं तो टाइम लाइन बना दिया है, तय कर दिया है कि इस साल या इस समय पर पुल बनकर तैयार हो जायेगा, बताओ आपने कभी टाइम लाइन बनाया। अगर इनको पांच साल पहले बना दिया गया हाता तो इतनी कीमत भी नहीं लगानी पड़ती और इतना खर्च भी नहीं करना पड़ता बजट का, आपको चिंता है कि बजट क्यों नहीं खर्च हुआ। कभी आपने अपने बजट देखें हैं कि वह कितना पैसा बजट का खर्च नहीं होता था और अगर खर्च भी करते थे तो किस लिए खर्च करते थे आप। बहुत-सी सड़कों का पता नहीं लगा कि पैसा किस पर खर्च हुआ। खर्च पता ही नहीं है, वह सड़क के लिए पैसा जरुर आया है लेकिन खर्च कहां हुआ ये पता ही नहीं है। वह पता नहीं नहीं लगा कि कहां खर्च हुआ। अब बताइये खर्च की आपको चिंता है और जो पुल कम पैसे में बन जाते बजट कम लगता, आज बताओ कितना पैसा देना पड़ रहा है उन चीजों के लिए। कई पुल ऐसे हैं, जिसमें दुगुना पैसा सरकार को खर्च करना पड़ेगा। बताइये सैदपुर का पुल जिस समय स्वीकृत था उस समय उसकी कीमत क्या थी, और आज हमें पुल की कीमत कितनी देनी पड़ रही है। इसी तरह आप जो बता रहे हैं संतकबीर नगर का, अम्बेडकर नगर का जोड़ दिया पुल, नेता जी ने दिया था उस समय, बहुत-सारे पुल हैं, मैं लिस्ट पढ़ सकता हूं पुलों की तो जो पुल बनाये नहीं इन्होंने या नेता जी ने रिकार्ड टाइम पर बनाये थे या रिकार्ड टाइम पर इस समय पुल बन रहे हैं जितनी स्पीड से पुल बन रहे हैं, उतने स्पीड से कभी नहीं बने। हालांकि इन्हें पुल याद नहीं होंगे नेता प्रतिपक्ष को लेकिन कुछ (आर0ओ0बी0) रेल ओवर ब्रिज एक तो हमेशा याद रखोगे आप कि हमने बनाया है, और जब मौका मिले आपको, हमारे घर के पास कोई रेल पटरी नहीं निकलती, कोई ट्रैक नहीं है, हमारे घर के पास हम कभी भी बसेंगे तो सैफई में बसेंगे। कभी आर0ओ0बी नहीं बनाना पड़ेगा आपको वहां और वह यादगाार आर0ओ0बी0 हमने बनाया है। (सदन में हंसी)

श्री मोहम्मद आजम खां-

फिर भी ये गाना गा रहे थे कि एक पुल बनाऊंगा तेरे पुल के सामने। (सदन में हंसी)

श्री अखिलेश यादव-

अगर पुल के सामने बनाये तो और अच्छा है, ये पार्टी से निकाल दिये जायेंगे और यह सच है ये पुल बनाकर जिस दिन तैयार होगा, हो सकता है अनुशासनिक कार्यवाही हो जाए आपके खिलाफ कुछ, क्योंकि सदन में तो आप बहुत बोलते हैं, सदन में हर पक्ष रखते हैं और सबसे विश्वासपात्र आप ही है इस समय, तो आप रोक क्यों नहीं पाये जो बन गया पुल बोलो। तो इस पर हो सकता है कि कार्यवाही हो लेकिन पुल बनने के बाद कार्यवाही होगी, उससे पहले नहीं होगी, तो वह यादगार पुल बना है। बताइये लखनऊ में जो लोग जानते होंगे, लखनऊ के अलावा आर0ओ0बी0, इतने हम लोगों ने भागदौड़ करके स्वीकृत कराये हैं, उसमें केन्द्र सरकार का भी सहयोग मिला था। अब हम समझते हैं केन्द्र सरकार का यहां भी सहयोग मिलेगा, कानपुर में भी बना दिये दोनों, मा0 सदस्य महाना जी जानते होंगे गोविन्द नगर, गोविन्दपुरी वह गलती हमसे हुई थी कि स्वीकृत कर दिया था, हालांकि स्वीकृत नहीं था लेकिन अब दोनों स्वीकृत है। एक बन कर पूरा हो गया और दूसरा बनने जा रहा है और बिना भेदभाव के बनाया है बताओं। कहीं भेदभाव किया हो पालिटिकल आप कह रहे हैं कि आपकी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो भेदभाव की है। जाति का, धर्म का भेदभाव है, बताएं हमारी कौन-सी योजना में जाति का, धर्म का भेदभाव है। किसी योजना में अगर आप बता दें, इसीलिये मैंने आपको

याद दिलाया कि जो लैपटाप स्कीम है वह वॉन ऑफ द सेकुलर सोशल स्कीम है, वह बना कर हमने दिखायी और उससे सेकुलर स्कीम, सोशल स्कीम कोई हो तो बता दें और इस पर आपने कहा था कि आई0टी0 का इस्तेमाल होना चाहिये। मा0 सदस्य गये होंगे कानपुर तो वहां वन ऑफ द बेस्ट कन्ट्रोलरूम बनाया है कि नहीं बनाया कानपुर में। जहां पुलिस की गाड़ियों की जी0पी0एस0 है और अभी पूरा-का-पूरा शहर जितना आ सका लाये हैं। कम से कम ये शुरूआत हुई है और दुनिया में जो सेफेस्ट सिटी हैं, उनमें इस तरह के कन्ट्रोल रूम बनाये गये हैं इस तरह के सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये गये हैं। कानपुर में सबसे पहले दिया और इस सदन में सबसे ज्यादा आई0टी0 को लेकर के किसी ने कहा था तो आपने ही कहा था। अगर पिछले बजट में आपको याद होगा तो आपने कहा था कि आई0टी0 का इस्तेमाल होना चाहिये था इसीलिये मैंने सबसे पहले कानपुर शहर को वह कन्ट्रोलरूम दिया...लखनऊ का तैयार है, गाड़ियां वहां दी जा रही है। तो पुलिस बेहतर काम करे कम समय में रिस्पांस टाइम पर वहां पर पहुंच जाये यह हमें काम करना है। 1090 हमने स्टार्ट किया है। आपके कंट्रोल रूम्स है, भर्ती चल रही है, ट्रेनिंग बेहतर हो रही है, मशीनें आ रही है। बड़ा बजट हम लोगों ने दिया है। पुलिस प्रशासन बेहतर कैसे हो इसके लिये बड़ा बजट इसमें दिया है। आपका मेट्रो बनाने जा रहे हैं। देश में कोई प्रदेश ऐसा बता दें जहां तीन शहरों में मेट्रों बन रही हो। औरों का हमने डी0पी0आर0 बनवा दिया है, कानपुर का हम डी0पी0आर0 बनवाने जा रहे हैं, बनारस का डी0पी0आर0 और मेरठ का और यह आपका आगरा का क्योंकि यह शहर उस कैटिगरी में आते हैं जहां पर डी0पी0आर0 के आधार पर मेट्रों आ सकती है। तो मेट्रों आ रही है आपके लखनऊ में और देश के सबसे ज्यादा जाने-माने जिनको मेट्रों मैन कहा गया है उनको हमने इसका सलाहकार बनाकर रखा है। वह हमारे साथ है और मदद कर रहे हैं सरकार को और उन्होंने भी टाइम बाउंड तय कर दी है तो इस टाइम बाउंड से चलेगा और जो-जो टाइम बाउंड है उसको फालो कर रहे है हम लोग कि किस दिन क्या कार्य होगा किस दिन टेंडर होगा और किस दिन शुरुआत हो जायेगी। आप देखेंगे कि नोएडा में ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद में शुरू होने जा रही है। वहीं लखनऊ में भी मेट्रों शुरू होगी। और वह टाइम बाउण्ड शुरू करेंगे। मेजों की थपथपाहट तो यह सरकार इस प्रदेश में तीन शहरों में मेट्रों चलाने जा रही है। आप ऐसा कोई प्रदेश बता दें जहां तीन शहरों में चल रही है। कोई प्रदेश नहीं। जहां का मॉडल चला था चौदह-पन्द्रह साल, वहां मेट्रों चली ही नहीं मेट्रों है ही नहीं वहां पर। तो इसलिये मेट्रों भी हम लोग ला रहे हैं। हास्पिटल कैसे अच्छे बने आपके हास्पिटलों में ओ0पी0डी0 ही नहीं है, जितने भी हास्पिटल बने हैं, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर वहां ओ0पी0डी0 ही नहीं है। अगर वहां कोई आना बैठना चाहे वहां पर तो कहां पर मरीज बैठे। जो सुधार कर सकते थे वह किया है हमने। जो बुराइयां एन0आर0एच0एम0 में थी वह बुराइयां आपकी सरकार लाई है। कितनी बुराइयां हैं उसमें, कितना काम किया है उनमें इन्होंने, कितने प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खुलने थे वह खोले ही नहीं इन्होंने, वह पैसा कहां चला गया पता ही नहीं और एन0आर0एच0एम0 का पूरा पैसा कहां बरबाद हो गया, उसकी सजा कुछ लोग भुगत रहे हैं उसमें जिसमें अधिकारी भी है और आपके लोग भी हैं, तो एन0आर0एच0एम0 के नाम पर क्या-क्या किया इन्होंने। हमारी सरकार ने अस्पताल बनाने शुरू कर दिये हैं। इलाज शुरू कर दिया है दवाई का इन्तजाम कर दिया है, दवाई हर जगह मिल रही है, किसी को कोई शिकायत नहीं है कि दवाई नहीं मिल रही है। अगर आप में से कोई स्पेसिफिक बता देंगे कि इस अस्पताल में दवाई नहीं है तो हम कार्यवाही करेंगे। आप लिखकर हमें दे दीजियेगा मैं बांदा गया था हमारे सदस्य वहां के हैं उनके पिता जी बीमार हुये थे उस समय और मैंने वहां एक-एक से पूंछा

जा करके किसी को कोई तकलीफ नहीं थी कोई परेशानी नहीं थी, उन्हें दवाई मिल रही थी और तमाम सुविधायें मिल रही थीं। तो अगर कहीं कमी है तो उसे दूर करने का काम हमारा है और इसीलिये सदन चलता है और जानकारी कम से कम सरकार के सामने आ जाये। तो पूरे मशीनरी में जो लोग बैठे हैं वह जरूरी नहीं हैं कि सभी विश्वासपात्र हों उनमें कुछ ऐसे लोग भी है जो काम चोरी करते हैं। अगर वह ठीक हो जायें, आपके माध्यम से ठीक होंगे, सदन के माध्यम से ठीक होंगे। (मेजों की थप-थपाइट) आप जानकारी दें, कार्यवाही सरकार करेगी। एक माननीय सदस्य ने जानकारी दी है हम उसे अलग से दिखवा लेंगे। इसमें सरकार कार्यवाही कर रही है तो हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। इतने मेडिकल कालेज कभी नहीं बने। अस्पताल कभी नहीं बने, वह बनाने जा रहे हैं हम लोग। महिलाओं के लिये भी बने हैं। आप कह रहे थे कि आपके बजट के साथ यह आना चाहिये था कि दो साल में आपने क्या काम किया। जो काम हम लोगों ने किये वह सब याद हैं और जनता को भी याद है। आप बतायें कि 108 समाजवादी एम्बुलेन्स कौन भूल जायेगा। कोई नहीं कह सकता कि 108 एम्बुलेन्स वोट के लिये किया है कोई हमें बता दे कि हमने यह चलाई है। यह सही है कि यह सरकार बनने से पहले यह हमारा घोषणा-पत्र था। 1650 करोड़ रुपये कर्ज माफी के लिये, किसानों के लिये था जिन पर पचास हजार का कर्ज था। हम तो प्रदेश सरकार के लिये आये थे हम सेन्ट्रल ग्राण्ट्स के लिये नहीं आये थे यहां पर। उसमें भी हमारे खिलाफ प्रचार हुआ कितनी स्कीम बतायें हम आपको जो दो साल में चलाई है हम लोगों ने। कितनी स्कीम हमने चलाई हैं दो साल में, उसको हमने बताया है। यह सही है कि जो काम हो जाते हैं वह भूल जाते हैं लोग। हम कैसे कह दें कि जो 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा हमने चलाई उससे कितने लोगों को फायदा हुआ कितने परिवारों को फायदा हुआ तो उसमें जरूरी नहीं है कि उन्होंने हमें वोट किया हो। यह कभी नहीं होता है लोकतंत्र में। कोई लैपटाप हमने दिया आपने झुनझुना कहा तो अब हम उसके लिये क्या कर सकते हैं और यह तो कमी निकालेंगे। जब लैपटाप बटने की बात आई तो तब मैंने एक बात कहीं थी और मैंने एक बात रखी उस समय मैंने कहा कि जब कोयले इंजन का अविष्कार हो रहा था तो तमाम लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि कोयला इंजन बनेगा ही नहीं और कोयले से स्टीम से इंजन कैसे चलेगा, कैसे बनेगा और जब वह बन गया इंजन स्टार्ट हो गया तो बोले कि अब यह चलेगा नहीं और जब चलने लगा वह कोयला इंजन तो ऐसे लोग थे कहे कि अब रूकेगा नहीं और जब रूकने लगा तो बोले कि यह तेज नहीं चलेगा तो ऐसे लोग तो है ही सदन में। अध्यक्ष महोदय, है ऐसे लोग सदन में। जब लैपटाप बाट रहे थे तो कह रहे थे कि झुनझुना है बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रहे हो नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो या आप विद्याधन क्यों दे रहे हो दवा पास बेटी को क्यों मदद कर रहे हो आप क्यों सुविधायें दे रहे हो अभी तो देंगे अभी तो सरकार हमारी कहां जा रही है इसलिये अभी भविष्य में क्या होगा, यह क्या है इस बार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया है तो इसलिये काम कर रही है सरकार। क्या काम नहीं किया तो को-आपरेटिव बैंक बन्द थे उनको चालू कर दिया और भी पैसा दे रहे हैं उनको भी चालू करने जा रहे है मोदीनगर की दो चीनी मिले आप लोगों की सरकार होती तो बहुत पहले चली गयी होती खत्म हो गयी होती और को-आपरेटिव का इन्होंने कितना बकाया छोड़ा था यह सही है। यह बाजार की वजह से हमें बहुत संकट झेलना पड़ा सरकार को, बाजार में जो चीनी ही हालत थी उसकी वजह से किसान को भी परेशानी उठानी पड़ी और हम यह स्वीकार करते हैं कि किसान को अगर गन्ने की कीमत नहीं मिलेगी उसका घर चल सकता और उसकी तमाम सामाजिक जिम्मेदारियां, उनको पूरी नहीं कर पायेगी इसलिये हमारी सरकार ने जो बकाया था वह तो दिया ही दिया था आपकी

सरकार का 6000 करोड़ और को-आपरेटिव की जो सहकारी चीनी मिले हैं उनका तो हम देंगे ही देंगे भुगतान और इस सदन के माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं कि पहले भी प्राइवेट चीनी मिलों का जो था भुगतान कराया है आने वाले समय में देर जरूर लगेगी लेकिन एक-एक पैसा किसानों का पूरा का पूरा भुगतान सरकार करायेगी। अब चीनी के मामले बड़ी बहस हो सकती है कि उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी इन्होंने खोल दी उस पर हम नहीं जायेंगे बहस में, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि जिस तरीके से चीनी मिलों का भुगतान हुआ है गन्ने का आगे भी होगा। यह सरकार काम कर रही है अपनी और बहुत अच्छे फैसले लिये हैं सरकार ने तो पुराने जो दो साल में काम किये हैं मेडिकल कालेज बनाये हैं, स्टेडियम बनाये हैं और भी करने जा रहे हैं लायन सफारी भी बना दी, खैर वह आपके इन्टरेस्ट का मामला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय लायन सफारी भी बना दी, लायन सफारी। वह आपके मतलब का नहीं है और वह जिस जगह बन रही है वहां इनका फेवरेट जानवर जा भी नहीं सकता। क्योंकि वह पहाड़ पर चल नहीं सकता चढ़ाई नहीं चढ़ सकता वह (हंसी) तो लायन सफारी भी बन रही है कौन-कौन हो सकता है कोई विभाग बता दीजिये जिस विभाग ने अच्छा काम न किया हो। अब लायन सफारी बना दी, लायन गुजरात से आ गये भी पिंजड़े में रहेंगे। इसी तरह मण्डी में काम हो रहा है। बुन्देलखण्ड के हमारे जितने माननीय सदस्य होंगे वह जानते होंगे कि हर जिले में हमने मण्डी रूकी पड़ी थी बुन्देलखण्ड पैकेज के माध्यम से जो पैसा आया था रोके पड़े थे यह बहुजन समाज पार्टी के लोग, वह पूरी मंडिया बन रही है कोई जिला हमें बता दो आप बताइये बांदा में बन रही है, हमीरपुर में बन रही है, झांसी में बना रहे जमीन चिन्हित कर दी है, जालौन में जमीन दे दी हमने। अगर मान लीजिये यहां पर पशुपालन विभाग की जमीन ली है तो अच्छे काम के लिये ली है इसलिये पशुपालन विभाग की जमीन ली है तो मण्डी बन रही है। पशुपालन विभाग पर पहले भी जमीन दी गयी थी वहां पर ग्राउण्ड इंस्टीट्यूट बनी है उसके बाद सेन्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिये जगह दे दी है।

इस सरकार ने विकास को कभी नहीं रोका जिस जिले के माननीय सदस्य आते हैं उसके बगल के जिले में एम्स बनना था मैं पूछना चाहता हूं 5 साल आपने क्यों फाइल रोके रखी आपने एम्स के लिये कोई जगह नहीं दी। समाजवादी सरकार आई और जमीन, 148 एकड़ जमीन दी और फ्री जमीन दी एक भी पैसा सरकार ने नहीं लिया और पूरा का पूरा पैसा सरकार ने दिया और एम्स के लिये जमीन दे दी इसी तरह जिस कार्य के लिये मांगी उस हर कार्य के लिये जमीन दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। एफ0एम0 रेडियों के लिये स्टेशन के लिये जगह चाहिये थी वह भी दे दी, प्रशिक्षण केन्द्र बनना था उसके लिये जमीन दी इस सरकार ने....रेल कोच फैक्ट्री के लिये समाजवादी सरकार ने जमीन दी है। केन्द्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है, उसके लिये जमीन दी है। इंस्टीट्यूट आफ ड्राइलिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो रुका पड़ा था, टाटा कम्पनी जो मिलकर बना रही थी, इसके लिये समाजवादी सरकार ने जमीन दी है। आई0टी0बी0पी0 के लिये जगह दी है। सैन्य स्कूल के लिये जगह दी है और सैन्य स्कूल के लिये हमने शर्त रख दी थी, उस समय की केन्द्र सरकार अगर चाहती कि सैन्य स्कूल लोकसभा के उनके क्षेत्र में खुले तो हमने भी कहा कि हमें भी दो सैन्य स्कूल चाहिये, तब हम जमीन देंगे और फ्री जमीन दी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अगर सैन्य स्कूल अमेठी में खुल रहा है तो एक मैनपुरी में खोला है और तीसरा सैन्य स्कूल झांसी को दिया है और बजट में भी इसके लिये पैसे का प्रावधान किया है। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिये जगह दे दी और जगदीशपुर पेपर मिल के लिये 187 एकड़ जगह दे दी। 200 बेड का जो महिला अस्पताल है, उसके लिये भी जगह दे दी। इसी तरह बुन्देलखण्ड में जमीन दी है, वहां एक नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उसके लिये भी

जमीन दी है। जहां तक मंडी की बात है तो मंडी बनी और उसके साथ-साथ जनेश्वर मिश्र गांव बनाये और बड़ी संख्या में जनेश्वर मिश्र गांव बने। माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, बताओं कि मंडी के अन्तर्गत कितने गांव में सी0सी0 रोड बनाई थी। दो हजार से ज्यादा गांव है जिसमें हम सी0सी0 रोड बना चुके हैं जनेश्वर मिश्र योजना के माध्यम से और पहले 25 लाख रुपये देते थे अब उसको बढ़ाकर चालीस लाख रुपये कर दिया है। लोहिया आवास योजना जो पहले थी उसमें पहले कम पैसा था, उसको अब और बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने किसान बाजार बनाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में किसान बाजार बना रहे हैं, हमने नई योजना शुरू की है कि किसान बाजार बनें। क्योंकि अगर किसान खेत में पैदा करें और अपनी उपज अपने आप बाजार में बेच दें तो उसको ज्यादा फायदा होगा। जो सिकन्दराबाद के लोग होंगे, माननीय सदस्य वह जानते होंगे कि कई ऐसे किसान है जो अपनी मेहनत से पैदा करते हैं और अपने आप वह बाजार में अपना सामान लेकर जाते हैं। जो पिंक गाजर बुलन्दशहर में पैदा हो रही है, बड़े पैमाने पर किसान उससे जुड़े है। तो कहीं न कहीं यह सरकार किसान बाजार भी बनाने जा रही है। किसान बाजार बनाने का काम शुरू हो गया है, लखनऊ में बना रहे हैं ? झांसी में बनकर तैयार हो गया है, सैफई में बना रहे हैं और बहराइच के लिये जमीन दे रहे हैं और धीमे-धीमे बड़े किसान बाजार बना रहे है। इसके साथ-साथ बिजली के क्षेत्र में भी काम हो रहा है जिसे मैं बता चुका हूं। ग्रीन बेल्ट तैयार हो रही है, कभी इनकी सरकार ने पेड़ नहीं लगाये, पेड़ काटे, नोचे और फेंक दिये। इनकी सरकार में कभी पेड़ लगा हो तो बता दें, 5 साल में इन्होंने कहां पेड़ लगाये। इनका पार्क है पत्थरों का और हमारा लोहिया पार्क है पेड़-पौधों का और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी जिन्हें आक्सीजन चाहिये होती है, वह भी हमारे ही पार्क में आते हैं। इसके बाद 5 अगस्त के आस-पास हम एक बड़ा पार्क बनाने जा रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है, ग्रीन बेल्ट कभी इतनी तैयार नहीं हुयी। जो ग्रीन बेल्ट हम लोगों ने तैयार करना शुरू किया है। इन्होंने जो खजूर लगाये थे वह सूख गये। पुलों के बारे में मैं बता चुका हूं। नेशनल हाई-वे एथारिटी के बारे में मैं बता चुका हूं। जमीन इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है और बढ़ रहा है और डी0एम0आई0सी0 से भी समझौता किया है। जो आपने अस्पताल के लिये कहा था, माननीय सदस्य ने कहा था श्रमिकों के लिये, लेबर के लिये अस्पताल और सुविधायें होनी चाहिये तो हमने उसके लिये ढाई एकड़ जगह फिरोजाबाद में दे दी है। लेकिन केन्द्र सरकार नहीं मान रही है, वह कह रहे हैं कि 5 एकड़ जगह चाहिये। अगर 5 एकड़ चाहिये तो वह 8 किमी0 दूर है, अब माननीय सदस्य तय कर लें कि अगर फिरोजाबाद शहर में बीमा अस्पताल ई0एस0आई0 बनाना चाहते हैं माननीय सदस्य यह जानते होंगे क्योंकि यह विधायक जी बहुत उद्योगपतियों से घिरे रहते हैं। बताओं आपकी सबकी मदद की कि नहीं, जब अस्पताल खुलना था। मापदंड पर खरा नहीं था, तब भी जो सहयोग करना था सरकार को, अपने कानून के अंदर, वह सहयोग हमने किया कि नहीं किया और पानी का भी काम शुरू कर दिया है, इनको कभी मीठा पानी नहीं मिल सकता था। यह मीठा पानी के लिये चिल्लाते थे कि मीठा पानी मिल जाये, मीठा पानी मिल जाये। ...तो मीठा पानी भी दे दिया और रिकार्ड टाइम पर वह नहर बन रही है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, उद्योगपति घेरे तो ठीक है लेकिन घिरे तो नहीं हैं।

श्री अखिलेश यादव-

नहीं, नहीं, हम इन्हें जानते हैं बहुत करीब से, जब ये चेयरमैन थे तब से हम जानते हैं। हमने तो कहा कि आप चालू पार्टी के सदस्य हैं। आप बताओं कि हम आपको करीब से थोड़ा-बहुत

जानते हैं या नहीं। मान्यवर, इसी तरह से बैक्स, उत्तर प्रदेश में इतनी बैक्स कभी नहीं खुली, बैंक की जो ब्रान्चेज थी वह इतनी कभी नहीं खुली। उस समय के जो केन्द्रीय मंत्री थे मा0 पी0 चिदम्बरम साहब आये थे। उन्होंने और हमने मिल करके 300 ब्रान्चें एक दिन में खोलने का निर्णय किया जो कि कभी देश में नहीं खुली उसको हमने खोलने का काम किया था और 3000 ब्रान्चों को खोलने का लक्ष्य था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का सी0डी0आर0 रेशियों 10 परसेंट बढ़ा, जो कि कभी नहीं बढ़ा था। अभी तक 2170 ब्रान्चें खुल चुकी हैं अगर मा0 सदस्य चाहेंगे तो एड्रेस सहित एक-एक ब्रान्च का पता इन्हें भेज देंगे लेकिन हम प्रचार ही नहीं कर पाये क्योंकि प्रचार में वह दल आगे है। बिजली के बारे में मैंने कह दिया, बड़ा बजट इसीलिये है क्योंकि ज्यादा काम करना है और बड़ा काम करना है। यह मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं तीसरा बजट पेश कर रहा हूं और यह बहुत बड़े प्रदेश का बजट है। प्रदेश बड़ा है जनसंख्या में, आबादी में सबसे ज्यादा है, जो हमारे एक मा0 सदस्य ने सवाल उठाया कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं, संसाधन आप कितने करेंगे। मान्यवर, यह बड़ा सवाल है, इस बड़े सवाल पर मैं समझता हूं कि हम सबको मिल करके रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर हमारा हिसाब-किताब ठीक है तो जहां आजकल फीफा वर्ल्ड कम हो रहा है ब्राजील में, जनसंख्या में हम उनसे भी आगे निकल गये हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली अच्छी हो, पानी का इन्तजाम अच्छा हो, बहुत सारी और सुविधाएं हों। मैं मा0 डाक्टर साहब के सवाल के जवाब देना भूल गया, मा0 डाक्टर साहब ने बहुत अच्छे सवाल पूछे थे कि बजट को कैसे-कैसे बड़ा किया है और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अपने विभाग की बात रखी थी एम0एम0आर0 और आई0एम0आर0 के लिये, उनमें उत्तर प्रदेश बेहतर हुआ है और पहले से अच्छा हुआ है। मैं आपको जानकारी दे दूंगा उसके बारे में भी कि जो सवाल किया है इन्फेन्ट मार्टेलिटी और मदर मार्टेलिटी के बारे में। उत्तर प्रदेश के आंकड़े पहले से अच्छे हुये हैं और वह इसलिये भी हुये हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। बिल एण्ड बिलिण्डा गेट फाउन्डेशन शुरू में सरकार के साथ आई थी, हम लोगों ने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिये, हम केवल आपका सहयोग चाहते हैं जो आपकी ट्रेनिंग और जो तमाम एक्सपर्टीज है। मेमोरेन्डम ऑफ को-आपरेशन हम लोगों ने साइन किया था उस पर लगातार काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें भी आगे आ रहा है। मैं समझता हूं कि जहां सरकार ने दो साल से ज्यादा में काम किया है यह तीसरे साल का बजट है और हमने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर है। कोई मा0 सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर न चाहता हो इसलिये इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग काम करेंगे और उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। जो एम0एम0आर0 है वह बेहतर हुआ है पहले से हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुये है। 108 समाजवादी एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, उसकी वजह से भी एम0एम0आर जो 359 पहले था वह 359 से 258 पहुंच गया है और इसे लगातार सुधारना पड़ेगा और इसके लिये हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह से आई0एम0आर0 67 से 57 पहुंच गया है। आर0आई0 नियमित टीकाकरण उसमें भी हम 61 परसेंट पहुंचे हैं और इन्स्टीशनल डिलीवरी के लिये क्योंकि 102 एम्बुलेंस हैं, उसकी मदद से हम लोग 65 परसेंट पहुंचे हैं। तो मान्यवर, लगातार सरकार काम कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजूकेशन के क्षेत्र में। जहां तक इलाज की बात है तो हम लोग इलाज में भी मदद कर रहे हैं और मुख्य मंत्री कोष से भी मदद दी जा रही है क्योंकि इंसेफेलाइटिस बहुत गम्भीर बीमारी है।...बहुत से बच्चों की जान जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बहुत जानें जाती हैं। गोरखपुर और आसपास के जितने भी जिले हैं, बड़ी संख्या में जानें जाती हैं उसके लिये मदद कर

रह हैं और अस्पताल को भी बड़ा कर रहे हैं। जो वार्ड बने थे, पहले नेता जी ने 200 बेड का बनाया था, उसके बाद अभी हम और मंत्री जी गये थे उसको और बढ़ा दिया है हम लोगों ने और भी सुविधायें अस्पताल को दे रहे है जिससे बेहतर सुविधायें मिल जायं। (कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता श्री प्रदीप माथुर जी ने अपने आसन पर बैठे हुये मा0 विधायकों को सड़क दिये जाने का आग्रह किया।) वह बाद में। आपको पानी की टंकी दे दी। इसलिये यह बजट जो बहुत बड़ा बजट है। मैंने आपसे कहा कि मैंने यह जो 2014-2015 का बजट पेश किया है इसमें ठोस विकास के रास्ते पर ले जाने का काम उत्तर प्रदेश के लिये किया है। खास करके इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आयेगा और नौकरियां भी मिलेगी। यह जो हमारा फोकस पहले था उसको भी साथ ले करके और बेहतर काम कैसे हो ठोस विकास का, उस रास्ते पर प्रदेश को ले जा रहे हैं इसलिये इतना बड़ा बजट है। मैं तमाम माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सुझाव दिया, राय दी और जिन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में भी बहुत सारी जानकारी सरकार तक लाने का काम किया। (ब0स0पा0 के मा0 सदस्य श्री गुटियारी लाल दुवेश ने आगरा में ओवरब्रिज दिये जाने का आग्रह किया।) ओवर ब्रिज, आगरा का इनर रिंग रोड पर दिया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर दिया और ताज के अलावा, ताज के आसपास टूरिज्म को बढ़ाने के लिये काम किया है। मैं सदस्यों का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उन सुझावों को ले करके सरकार को और काम करने का मौका मिलेगा। मैं सभी मा0 सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं।

(नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, जब बजट भाषण का मा0 मुख्य मंत्री जी जवाब देते हैं तो आपको स्पष्टीकरण पूछने का हक है। आप स्पष्टीकरण पूछेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं बहुत ही थोड़ा समय लूंगा, मुझे खुद ही इसका ध्यान है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट भाषण पर हमारे मा0 नेता भा0ज0पा0 मा0 नेता कांग्रेस, मा0 नेता लोकदल, मा0 नेता पीस पार्टी सत्तापक्ष और विपक्ष के कुल 73 मा0 सदस्यों ने बजट चर्चा में भाग लिया है और सभी मा0 सदस्यों के बहुत से सुझाव भी आये हैं, क्षेत्र की समस्यायें भी आयी हैं साथ ही साथ इस पर अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत कुछ समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिये हैं लेकिन मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि लैपटाप तथा अन्य इनकी योजनायें सेकुलर और सोशलिज्म की स्कीम के अन्तर्गत लोकप्रिय रही है। मान्यवर, यही तो मैं भी कह रहा था जब वह सेकुलर और सोशलिज्म स्कीम थी तो उसको अलविदा करने की आवश्यकता क्यों रही आज कि अगर 15 लाख छात्रों को लैपटाप मिला तो माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह बात रहनी चाहिए कि प्रतिवर्ष 28-30 लाख इण्टर के छात्र पास होते हैं तो अब जो इण्टर के छात्र पास हो रहे हैं उनको इस योजना से वंचित क्यों किया गया। और 15 लाख की ही इसकी सीमा क्यों। यही चीज मैंने स्पष्ट किया था यदि माननीय मुख्य मंत्री जी यह सेकुलर और सोशलिस्ट स्कीम होती तो अनवरत चलती रहती और लोक सभा चुनाव में मनचाहा परिणाम न आने के नाते इस प्रदेश के नौजवानों को हाई स्कूल और इण्टर पास छात्र-छात्राओं को सजा दी गई है इसके पीछे मकसद यह है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप पहले भी कह चुके हैं। आप स्पष्टीकरण पूछें। यह राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है जिस पर आपको पूरा अधिकार रहता है इसमें आप कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं मात्र 10-15 मिनट में संक्षेप में अपनी बात रखूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप केवल स्पष्टीकरण पूछिए। आप नेता विरोधी दल हैं आप जानते होंगे कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आप कटमोशन रखते हैं तो आप अपनी बात कहते हैं माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं फिर मुख्य मंत्री जवाब देते है। यह बजट पर चर्चा है इस पर आपने अपनी बातें रखीं मुख्य मंत्री जी ने अपनी बातें रखीं अब कोई बात स्पष्ट न हुई हो वह पूछ लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी हमसे ज्यादा तो आप जल्दी में है। मैं जब आपके निर्देश का अक्षरश पालन करता हूं। फिर बार-बार...

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी परम्परा गलत पड़ रही है इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हो सकता है कि कुछ जिलों में 4 लेन की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी किए हों लेकिन प्राय मैं देखता हूं कि रायबरेली-प्रतापगढ़, प्रतापगढ़-सुल्तानपुर या सुल्तानपुर-प्रतापगढ़ या कुशीनगर-देवरिया या कुशीनगर-महाराजगंज, आजमगढ़-मऊ तमाम ऐसे जिले हैं अगर हम उन सबको लाएंगे तो मान्यवर, यह साबित हो जाएगा कि चुनिन्दे जिले में योजना चल रही हो लेकिन पूरा प्रदेश अभी उससे अछूता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ें। जहां तक सी0सी0 रोड की बात है यह हमारी नकल है आपने हमारी नकल किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। अम्बेडकर ग्राम योजना के माध्यम से मैंने पूरे प्रदेश में सी0सी0 रोड बनवाने की परम्परा डाली थी और मान्यवर, बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद आपने लोहिया ग्रामों में आपने उसका अनुकरण करना शुरु किया तो हम समझते हैं यह हमारी योजना का नकल है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोबिन्द चौधरी)-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको जो दिक्कत हो उसका स्पष्टीकरण पूछ लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि पूर्वांचल की जनसंख्या को देखते हुए पूर्वांचल विकास निधि 291 करोड़ बहुत कम है और सत्ता पक्ष की माननीय शादाब फातिमा जी ने भी जब इस 291 करोड़ बढ़ाए जाने की मांग की तो सत्ता पक्ष के

सारे सदस्यों ने इसका जोरदार स्वागत किया इसका मतलब है कि जो मैंने कहा वह सही है। या इसको बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी चीज मान्यवर, सत्ता पक्ष के ही एक माननीय सदस्य श्री जियाउद्दीन साहब ने स्वयं इस बात को कहा था कि हम विपक्ष में रहकर के हमें लड़ने में मजा आता था। सपा सरकार ने मुसलमानों को बहुत कुछ देने का वायदा किया लेकिन मिला कुछ नहीं। हल्ला बहुत मचा। हमारे क्षेत्र में तमाम सड़कें अपूर्ण है अगर हम विपक्ष में होते तो हमारी सड़कें बन जातीं। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष का काम करिये न करिये लेकिन कम से कम अपने सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का काम जरुर करिये जिससे कि उनको इस प्रकार की बात यहां करने का मौका न मिले। (माननीय सदस्य श्रीमती शादाब फातिमा के बोलने पर) अरे आपकी मांग पर बात मान ली जायेगी।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मेरे नाम लिया है इसलिये मैं कह रहीं हूं कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिये, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिये मैंने कहा है कि इसको 252 करोड़ से बढ़ाया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वही तो हम भी कह रहे हैं। आपकी मांग पर अपनी बात मान ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

शादाब फातिमा जी आप बैठिये। उनको अपना स्पष्टीकरण करने दीजिये।

(सदस्य श्री जियाउद्दीन रिजवी के बोलने पर कि माननीय नेता विरोधी दल आप गलत आरोप लगा रहे हैं।)

श्री अध्यक्ष-

अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं उनको अपनी बात कहने दीजिये।

स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं। यह कानून व्यवस्था पर चर्चा का विषय नहीं है। अलीगढ़ में एक अवर सिविल जज है। दुराचार के मामले में एफ0आई0आर0 भी उन्होंने दर्ज कराया है। किसी भी अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर न्याय देने वाला खुद इन्साफ की गुहार मचायेगा। तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं उस जज के साथ नाइन्साफी होगी। हम चाहते हैं उसको न्याय अवश्य मिल जाय। रही बात एन0आर0एच0एम0 के घोटाले की। उसको तो अपनी गोदी में बैठा लिया, तो इसलिये हमको उस पर कुछ नहीं कहना। एम्बुलेंस देने की जहां तक रही बात। जिसको अपनी गोदी में बैठाया, यह अपने ही कार्य-काल ही में सारे एम्बुलेंस मंगा लिये थे, वितरण नहीं करा पाये थे। वाह-वाही आप ले गये। इसलिये यह बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी नहीं है। इसके साथ ही साथ आज इनवेस्टमेंट हो, हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। निवेशक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में आयें। उत्तर प्रदेश की आबादी, जनसंख्या के मुताबिक विकास के मामले में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़े इसलिये हम चाहते हैं कि निवेशक बड़े पैमाने पर यहां आयें इसलिये आप उनको वातावरण बनाने के लिये, कानून व्यवस्था को बहुत चुस्त-दुरुस्त करने का काम करें। इसके लिये आपको कठोर कदम उठाने के लिये अपने को तैयार रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आगरा एक्सप्रेस वे हमारे

मथुरा एक्सप्रेस वे की तर्ज पर आपने पिछले दो साल से उस पर एक्सरसाइज करने का काम किया लेकिन कोई भी अभी तक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत बनाने वाला नहीं मिला तो सरकार उसको अपने तौर-तरीके से बनाने की कोशिश में तो हैं लेकिन कब तक बना लेगी इसकी अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे नेता का हवाला देते हुए कहा कि बाबा साहब डा0 अम्बेडकर नहीं होते तो हम यह करते (व्यवधान) मैंने वही कहा। वह पीड़ा केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वह पीड़ा इस देश के सभी दबे-कुचले, शोषित-पीड़ित, मजलूम समाज के लोगों की है क्योंकि भारतीय संविधान के पहले जो हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत न आप यहां बैठने लायक थे, न हम यहां बैठने लायक थे क्योंकि जो उस समय व्यवस्था थी, उस समय की व्यवस्था के मुताबिक ''शुद्रम् तु कार्येत दास्यम्, क्रीतम् अक्रीतम् व, दार्स्येव तु जन्मनः, ब्राह्मणम् तु स्वयंभुवः'', यह व्यवस्था थी। मान्यवर, परम् पूज्य बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर को हम सभी लोगों को मिल करके बधाई देनी चाहिए कि आजादी के बाद हम लगातार 65 साल जिस समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अग्रसर हैं, बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से उस रास्ते को प्रशस्त किया, जिससे कि आज दबे-कुचले, शोषित-पीड़ित, मजलूम समाज को मुख्य मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इससे भी बड़े ओहदे पर जाने का मौका मिल रहा है। इसलिए मान्यवर, किसी ऐसी दुर्भावना से बात नहीं कही गयी थी, यह केवल बात समझाने की है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने तमाम विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की, यद्यपि जब मैं कभी यहां खड़ा होता हूं तो पूरे प्रदेश की बात और पूरे प्रदेश की समस्या को ही इंगित करता हूं, लेकिन विशेष रूप से पूर्वांचल का गोरखपुर, मैं चाहूंगा कि जब बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे हास्पिटल बन रहे हैं तो वहां पर जो गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल तथा पूर्वांचल के अन्य तमाम जिले जो इन्सेफ्लाइटिस से विशेष रूप से प्रभावित हैं, उसका उच्चीकरण करके पी0जी0आई0 या एम्स के स्तर का अस्पताल बना करके, अगर एक अच्छा काम करेंगे तो हम समझते हैं, उसकी हम भी सराहना करेंगे और मान्यवर, आप तो विश्वविद्यालय ले गए, अपने यहां।

श्री अध्यक्ष-

वह भगवान बुद्ध की धरती पर गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसका तो मैं स्वागत कर रहा हूं और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने मा0 मुख्य मंत्री जी को विश्वविद्यालय देने के लिए राजी कर लिया लेकिन हम कुछ भी कहेंगे, चूंकि हम नेता विरोधी दल हैं, इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी हमारी बात तो मानेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष-

जो परम्परा आपने डाली है, वही परम्परा तो रहेगी। अब आप समाप्त करिए, अभी बहुत से लोग स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। अभी आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे बिजली देने का काम किया जायेगा। लेकिन सही मायने में 18 घण्टे या 24 घण्टे जब बिजली देंगे, वह अच्छी बात होगी लेकिन वर्तमान में या तो आप अपनी समय-सारणी कम करके उसको सुनिश्चित कर लें या जो आप निश्चित किए हैं, उसके मुताबिक बिजली देने का काम करें।

मान्यवर, चूंकि व्यवहारिक रूप में कुछ है, लिखत-पढ़त में समय-सारणी के मुताबिक आपूर्ति कुछ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि 18 घण्टे और 24 घण्टे की बात तो बाद में आयेगी और शायद हो सकता है 2016 तक उसकी नौबत न आये। इसलिए मान्यवर, यह जो बजट है, बजट पर हमने चोट, टिप्पणी इसलिए की कि जब आपके पिछले तमाम बजट भाषणों में प्राविधानित बजट के धन बिना काम किए वापस हुए या यथावत् पड़े रहे, उनको पुनः खजाने में भेजना पड़ा। इसलिए चूंकि आपकी सरकार है, आप मुख्य मंत्री हैं, आप का बजट है।

स्वाभाविक रूप से योजनायें आपकी प्राथमिकताओं की हैं तो इस पर ग्रहण नहीं लगना चाहिए। इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम होना चाहिए। मान्यवर, चूंकि इस बजट में बड़े पैमाने पर कमियां हैं, कथनी और करनी में अंतर है और हालत इस बजट की वही है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, एक ढपोरशंख था। एक गरीब ब्राहमण था।

(सत्तापक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष-

जब कभी ब्राह्मण का नाम आता है तो गरीब ही कहा जाता है। अब हो गया। ढपोरशंख के किस्से सब जानते हैं। अब हो गया। खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, उसका काम था घोषणा करना। एक लाख लो, दो लाख लो, दस लाख लो। लेकिन अंत में कहता था बदामि च ददामि न। बोलता हूं लेकिन देता नहीं करता नहीं। वही हाल हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी का है। घोषणायें बहुत, योजनायें बहुत, बजट बहुत लेकिन काम नहीं होता है। इसलिए मान्यवर, मैं इस ढपोरशंखी बजट का विरोध करता हूं।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष माननीय मौर्य जी ने कई स्पष्टीकरण मांगे हैं। जो हमारे यहां सदन में जितने मा0 सदस्य हैं जानते होंगे इनका कोई भी भाषण तब तक पूरा नहीं होता जब तक एक बार ढपोरशंख की कहानी न सुना दें। यह रिकार्ड से आप निकलवा लें। क्योंकि तीन बार बजट का सदन चला है और हर बजट में इन्होंने ढपोरशंख कहा है। तो आखिरकार हमें और इधर के लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि आखिरकार यह ढपोरशंख है कौन। जहां तक लैपटाप की बात है मा0 मौर्य जी ने हमेशा लैपटाप को इन्होंने लैपटाप नहीं माना। लैपटाप को कम्प्यूटर नहीं माना। जब सबसे पहले दिन बंटा तो मैंने खुद इनको एक उपहार के रूप में भेजा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री जी मेरे यहां रखा है। इन्होंने लिया ही नहीं। यह अभी लें तो इन्हें अभी दे दूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, जब लैपटाप की व्यवस्था खत्म हो गयी तो वह मा0 मुख्य मंत्री जी को वापस कर दें।

श्री अखिलेश यादव-

योजना खत्म हो गयी लेकिन लैपटाप तो नहीं गया। जिनके घरों में लैपटाप है वह तो है ही। इसलिए मैंने कहा कि लैपटाप जो मशीन है वह उसी तरीके से है जैसे घर में और जरूरत के सामान रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं हर महीने चेक करूंगा कि यह कहीं हर महीने अपना मोबाइल तो नहीं बदलते हैं। तो लैपटाप जहां पहुंच गया है वह कई वर्षों तक घर-परिवार में रहेगा। इस बार सरकार ने ध्यान देना शुरू किया है। सरकार ने इस बार जहां लैपटाप इतने बड़े पैमाने पर बॉट दिये हैं तो सरकार अब ई-लाइब्रेरी को बढ़ावा देगी, इ-लर्निंग को बढ़ावा देगी, ई-बुक्स को बढ़ावा देगी और जहां पर स्कूल में इंटरनेट की सुविधा देनी पड़ेगी उसके लिए भी सरकार काम करेगी। ब्राडबैण्ड तो हम दे ही रहे हैं इसके लिए तो स्वीकृति किया ही है, उसके साथ-साथ लखनऊ में तो फोर-जी आ ही रहा है। और बहुत सारे विद्यालयों महाविद्यालयों में यह सुविधा पहले से ही है। इसलिए लैपटाप और कम्प्यूटर की पढ़ाई के पक्ष में हम लोग थे ही, जो हम चाहते थे कि गांव में गरीब जनता के बेटे भी कम से कम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सपोज हों। इस टेक्नोलॉजी से न डरें, लैपटाप से न डरें। आपने अपनी प्राइमरी एजूकेशन की बात बतायी थी। न जाने आप किस जमाने में पढ़े हैं, नौ टीचर थे आपके यहां। अगर वह गुरू लोग जिंदा हैं तो मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जो हमारे मा0 नेता प्रतिपक्ष हैं वह उस समय कितने नटखट थे। इसलिए ई-लर्निंग क्या है इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्वीट ज्यादा करते हैं वह ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। जहां तक पूर्वांचल निधि का सवाल है। मैं पूर्वांचल निधि बजट में ज्यादा ही दे रहा हूं। और इसीलिए मैंने कहा जब एक मा0 सदस्य खड़े हुए थे, आप जिले-जिले की जानकारी कर लें, विभिन्न-विभिन्न विभागों में अगर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है सरकार ने तो पूर्वांचल पर दिया है, मैं मा0 सदस्य को भरोसा दिला सकता हूं मा0 अध्यक्ष जी कि समाजवादी सरकार बिना भेदभाव के पूरे उत्तर प्रदेश का विकास चाहती है, चाहे वह बुन्देलखण्ड हो या कोई पिछड़ा इलाका हो हमें अलग से भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा विकास के कार्यों में तो सरकार पीछे नहीं रहेगी, सरकार कामों को तेजी से बढ़ायेगी। जहां तक रिजवी साहब के बारे में कहा है तो मैं जानकारी कर लूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, समाजवादी पार्टी के लोग तो लड़ने वाले लोग हैं और क्या कहा ये मेरी जानकारी में नहीं है और क्यों कहा होगा, तो आपके साथी मा0 सदस्य बैठे होंगे उनकी वजह से कहा होगा। अब वह रिजवी साहब समझ गये, हम जान गये। इसी तरह अलीगढ़ की जो घटना आपने बताई, उसमें पूरी जानकारी है, पहले घटना हुई थी उसमें पारिवारिक झगड़ा है, एक परिवार केस लिखना चाहता है, दूसरा परिवार भी केस लिखाना चाहता हैं, जो आपने यह सवाल उठाया है उस पर सरकार निष्पक्ष कार्रवाई करेगी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे ई0पी0सी0 पर इसलिए लेकर के आये स्टेट बजट से क्योंकि देश में जो इन्वेस्टमेण्ट का माहौल था उसमें कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा था, कोई बैंक किसी को फाईनेन्स करने के लिए तैयार नहीं था और आपने जितने बड़े पैमाने पर स्वीटनेस दिया था, जमीनें दी थीं उस हाईवे के लिए, तो आप हिसाब किताब लगायें तो वह हाईवे जितने का बना नहीं है उससे कई गुना ज्यादा पैसे की कीमती जमीन आपने दी है, अगर लैण्ड पैकेज और पार्सल्स दिये हैं तो बड़े-बड़े दिये हैं और बड़े पैमाने पर दिये हैं,

अब तो क्योंकि बाजार कैसा है, चीजें बिकने लगीं आपने अपने मित्र को जो इतना बड़ा स्वीटनर दिया है, उनका तो सब बिकने लगा है अब आप जानकारी कर लें बाजार के बारे में क्या-क्या जा रहा है, क्या-क्या खोया जा रहा है उसमें यह ई0पी0सी0 हम इसलिए लेकर के आये क्योंकि कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि हमारा समय जरूर गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को क्योंकि इससे एग्रीकल्चर और हमारी एग्रो इण्डस्ट्री प्लस हमारी रूरल बेल्ट जो है, वह बेहतर होगी, इसलिए ई0पी0सी0 सरकार के बजट से हम लोग देने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश का बजट इतना बड़ा है, अगर कोई बड़ा से बड़ा बजट का काम करना चाहेंगे तो इस बजट के माध्यम से हम कर सकेंगे। इसलिए यह कहीं न कहीं हिम्मत सरकार ने जुटाई है कि इतनी बड़ी धनराशि दे रहे हैं इस बजट में। अगर कोई छोटा स्टेट होता तो मैं समझता हूं कि यह कभी सोच भी नहीं सकता था और देश में, मैं यह कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार यह पहली सरकार है जिसने सड़क का इतना बड़ा ई0पी0सी0 प्रोग्राम बनाया है और समयबद्ध खत्म हो, समय से पहले पूरी हो, इन्सेन्टिव दे रहे हैं हम लोग जिससे कि समय पर यह हाईवे बन जाय। बिजली बेहतर हो, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, कुछ मा0 सदस्यों ने यह भी बात उठाई कि ट्रान्सफार्मरों में पैसा लग जाता है। यह सुविधा हमने शुरू कर दी है कि विभाग की तरफ से गाड़ी आयेगी, कुछ जगह उसकी मदद मिल रही होगी और कई बार ट्रान्सफार्मरों में दिक्कत होती थी, ट्रान्सफार्मर समय से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जिले में हो सकता है अभी न हो, लेकिन यह व्यवस्था हमने कुछ जिलों में शुरू कर दी है, जिससे कि ट्रान्सफार्मर की सूचना मिलते ही विभाग की गाड़ी आयेगी और ट्रान्सफार्मर बदल देगी। जहां तक हमारे मा0 सदस्य ने बताया कि ट्रान्सफार्मर में पैसा देना पड़ गया निधि का, वह शायद तब आपको देना पड़ा होगा जब कैपेसिटी आपने बढ़ाने के लिए कहा होगा, लेकिन उसको एक बार फिर भी सरकार दिखवा लेगी। जहां तक एन0एच0आर0एम0 का सवाल है, बात आपने कही कि हमारे साथ आ गये, तो कुछ राज भी आये होंगे, आज आप जरूर करीब दिख रहे हों, लेकिन उस समय आप कितनी दूर थे, क्या थे, लेकिन जहां तक एन0एच0आर0एम0 का सवाल है पूरा का पूरा पैसा केन्द्र सरकार का, इनकी सरकार ने बर्बाद कर दिया और अगर पैसा सही तरीके से लगा होता, तो यह स्वास्थ्य विभाग बहुत बेहतर दिखाई देता। स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़े काम हो जाते। जहां तक फोरलेन से जोड़ने का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक एजेण्डा तय किया है कि जो फोरलेन से शहर जुड़ रहे हैं क्योंकि एन0एच0ए0आई0 भी सड़क बना रहा है और एन0एच0ए0आई0 के बनने से कुछ जिले कुछ कम दूरी से छूट जा रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय उन जिलों को हम लोग जोड़ रहे हैं और प्रोग्राम बनाया है, अभी तो 16 मुख्यालयों को जोड़ पर रहे हैं, इसके बाद और जोड़ेंगे और एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से भी बड़ी संख्या में 30 से ज्यादा जिले जुड़ गये हैं। तो यह प्रोग्राम उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली बार बनाया है। जहां फोरलेन से मुख्यालयों को जोड़ने का काम हुआ है। जहां अभी लगातार तीन साल और काम करना है तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जिला मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ने में यह सरकार सफल होगी जिससे आपके प्रदेश में एक मजबूत, एक ठोस, एक अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जायेगा जिससे कि गांव के लोग भी पलायन नहीं करेंगे। अभी मा0 सदस्य ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है और जिसकी वजह से जो सुन्दर, अच्छे शहर आपके होने चाहिये थे इसीलिये हमारी सरकार ने इसे बजट के भाषण में रखा है कि जहां हम रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वही शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो वो बजट भाषण में मैंने कहा है और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिये अगर

हमको बजट से देना पड़ेगा तो हम देंगे ही देंगे क्योंकि इस बजट में जितनी भी अथारिटीज है इनका पैसा नहीं आता है तो एक अलग से फण्ड बनाया है जो अथारिटी का इस बजट में पैसा नहीं आता है कभी भी। नोएडा अथारिटी, ग्रेटर नोएडा है और भी अथारिटी हैं जो मुनाफे में हैं, उनका पैसा ला करके इन्फ्रास्ट्रक्चर वाला जो फण्ड है उसमें रख करके हम शहर का भी इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे इसलिये मैंने कहा कि तीन मेट्रो किसी प्रदेश में नहीं आ रही होंगी, शहरों में जो उत्तर प्रदेश में आ रही है। कई जगह हम अपने बजट से भी शुरूआत कर रहे हैं। जब तक हमें बाहर से पैसा मिलेगा या इन्वेस्टर ढूंढेंगे तब तक हम अपना काम आगे बढ़ा लेंगे इसलिये ये काम हम लोग करने जा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, एक बात आपके संज्ञान में डाल रहा हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी,आप रायबरेली गये थे वहां पर आपने एक घोषणा की थी, आपने स्वयं घोषणा की थी। कंजेश्वर मंदिर से लोहरामऊ सई नदी पड़ती है बीच में उस पर आपने पुल बनवाने की घोषणा की थी और साथ ही साथ बछरावां-राजामऊ सड़क का चौड़ीकरण तथा उच्चीकरण। ये दोनों घोषणायें आपने एक साथ की थीं। मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपकी घोषणा के बाद कई महीने हो गये, अभी शुरूआत भी नहीं हुई है, इसका संज्ञान ले लें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, तीन स्पष्टीकरण हैं, तीन लाइन में। मैं लाइन तीन लाइन स्पष्टीकरण मागूंगा, लम्बा नहीं। मान्यवर, अभी इस सदन में एक बात आई कि एन0आर0एच0एम0 घोटाले में इन्होंने घोटाला किया उन्होंने गोद में ले लिया। उसके बाद मा0 मुख्य मंत्री जी ने सदन के अन्दर एक बात कही कि उनको गोद में लेने के बाद कुछ राज भी आये थे। मान्यवर, वे राज कौन से हैं, ये सदन को पता चलना चाहिये, जनता को पता चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मा0 महाना जी, कानपुर के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लो।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण तो हो गया और राज अगर कोई है तो उन राजों को उपयोग करके उनको सजा देनी चाहिये। मान्यवर, दूसरी बात, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय अगर कानपुर वाली रोड नहीं बनी थी तो उसके लिये ये क्यों जिम्मेवार हैं, केन्द्र सरकार जिम्मेवार है इन्होंने यहां का वहां का नाम लिया। कुछ पावर प्रोजेक्ट्स में कोयला नहीं मिल रहा था उसके कारण वे शुरू नहीं हुये तो उसके कारण नुकसान हुआ चुनाव में। मान्यवर, आप 10 साल उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तो उस सरकार में, उस प्रभाव का इस्तेमाल करके आपने उन कामों को पूरा कराने का कार्य क्यों नहीं किया, दूसरा स्पष्टीकरण चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, आरोप-प्रत्यारोप इसमें नहीं होता है, विकास की बात तो कर सकते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हाउस में बात आयी है। मान्यवर, चलिये वो भी खत्म हो गया। आप जवाब नहीं दिलाना चाहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, तीसरा जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने किया है। एक निवेदन के साथ स्पष्टीकरण है, सुझाव है। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की है उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरे प्रदेश में समेकित विकास के साथ रास्ते से क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिये सबकी भागीदारी लेने का भी आप काम करेंगे। यह तीसरा स्पष्टीकरण है।

‡श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जो अच्छा फैसला होता है उसका चाहे पक्ष के लोग हों, चाहें विपक्ष के लोग हों, सभी स्वागत करते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि 60 हजार करोड़ रुपये एम0ओ0यू0 साइन हुये हैं। हम स्वागत करेंगे और मैं समझता हूं कि सभी लोग स्वागत करेंगे। मान्यवर, जब पड़ोस में कहीं पानी बरसे तो कम से कम बौछार तो आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

शाहजहांपुर के लिये कुछ कहना चाहते हैं। श्री सुरेश कुमार खन्ना, मान्यवर, अरे सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं है। ये उदारता का लाभ न उठायें, अपने क्षेत्र की कोई बात हो तो कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने जब अनुमति दे दी।

श्री अध्यक्ष-

अनुमति इसलिये थोड़े दी है कि चाहे जो पूछो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सुन तो लें मान्यवर, पूरी बात सुन लें। जब पड़ोस में कहीं पानी बरसे और हमारे घर बौछार भी न आये मान्यवर, सदन के 425 लोग हैं। 403 यहां के और 100 लोग कम से कम विधान परिषद् में हैं। आज शाहजहांपुर एजेण्डा नहीं है मान्यवर, और न शाहजहांपुर के लिये कुछ मांग रहे हैं। ऐसा है मा0 अध्यक्ष जी एक मिनट के लिये अनइण्टरप्टेड, कृपा करें मा0 मुख्य मंत्री जी बहुत गौर से सुन रहे हैं। मैंने बधाई भी दी 60 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट का जब एम0ओ0यू0 हो गया निश्चित रूप से हम यह मानते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट निकट भविष्य में हो जायेगा। मान्यवर, जब पड़ोस में पानी बरसे और इस विधान सभा में फुहार भी न आये, यहां कम से कम बाछौर आनी चाहिए ताकि यह मालूम चले कि मुख्य मंत्री जी इतना बड़ा फैसला लेकर आये हैं और पूरा सदन उसके लिये धन्यवाद भी दे रहा है और बधाई भी दे रहा है मा0 अध्यक्ष जी। मान्यवर, हमने उस दिन एक बात कही थी कि रेलवे का किराया बढ़ गया है मान्यवर, साढ़े चौदह परसेन्ट ...

‡ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप माथुर-

अच्छे दिन आने वाले हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

दूसरी बात मान्यवर, हमने एक बात कही थी कि यह मैसेज अच्छा नहीं जाता है कि हम अपना वेतन भत्ता खुद बढ़ाये। इसको मान्यवर, प्राइस इंडेक्स से जोड़ दें। मुझे क्षमा करेंगे मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसके ऊपर रोशनी नहीं डाली शायद स्लिप कर गया होगा, किसी वजह से स्लिप कर गया होगा मान्यवर, तो हम यह जरूर चाहेंगे कि एक बार उसके ऊपर रोशनी जरूर डाल दें या इसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ने पर विचार करें। मा0 आजम खां साहब, इस पर अपना विचार दे चुके हैं। अपनी सहमति दे चुके हैं वह मान्यवर, कार्यवाही में रिकार्ड है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पूरी सरकार के लिये बहुत बढ़िया स्वर्णिम दिन है कि 60 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट बाहर से आ रहा है मान्यवर, इस विधान सभा को भी उसके बारे में कुछ देखने को मौका मिलना चाहिए मान्यवर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने जब अनुमति दे दी।

श्री अध्यक्ष-

अनुमति इसलिये थोड़े दी है कि चाहे जो पूछो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सुन तो लें मान्यवर, पूरी बात सुन लें। जब पड़ोस में कहीं पानी बरसे और हमारे घर बौछार भी न आये। मान्यवर, सदन के 425 लोग हैं। 403 यहां के और 100 लोग कम से कम विधान परिषद् में हैं। आज शाहजहांपुर एजेण्डा नहीं है मान्यवर, और न शाहजहांपुर के लिये कुछ मांग रहे हैं। ऐसा है मा0 अध्यक्ष जी एक मिनट के लिये अनइण्टरप्टेड, कृपा करें मा0 मुख्य मंत्री जी बहुत गौर से सुन रहे हैं। मैंने बधाई भी दी 60 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जब एम0ओ0यू0 हो गया निश्चित रूप से हम यह मानते हैं कि यह इनवेस्टमेंट निकट भविष्य में हो जायेगा। मान्यवर, जब पड़ोस में पानी बरसे और इस विधान सभा में फुहार भी न आये, यहां कम से कम बौछार आनी चाहिये ताकि यह मालूम चले कि मुख्य मंत्री जी इतना बड़ा फैसला लेकर आये हैं और पूरा सदन उसके लिये धन्यवाद भी दे रहा है और बधाई भी दे रहा है मा0 अध्यक्ष जी। मान्यवर, हमने उस दिन एक बात कही थी कि रेलवे का किराया बढ़ गया है मान्यवर, साढ़े चौदह परसेंट.....।

श्री प्रदीप माथुर-

अच्छे दिन आने वाले हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

दूसरी बात मान्यवर, हमने एक बात कही थी कि यह मैसेज अच्छा नहीं जाता है कि हम अपना वेतन-भत्ता खुद बढ़ायें। उसको मान्यवर, प्राइस इंडेक्स से जोड़ दें। मुझे झमा करेंगे मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसके ऊपर रोशनी नहीं डाली, शायद स्लिम कर गया होगा, किसी वजह से स्लिप कर गया होगा मान्यवर, तो हम यह जरूर चाहेंगे कि एक बार उसके ऊपर रोशनी जरूर डाल दें या इसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ने से जोड़ने पर विचार करें। मा0 आजम खां साहब, इस पर अपना विचार दे

चुके हैं। अपनी सहमति दे चुके हैं वह मान्यवर, कार्यवाही से रिकार्ड है। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पूरी सरकार के लिये बहुत बढ़िया स्वर्णिम दिन है कि 60 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है मान्यवर, इस विधान सभा को भी उसके बारे में कुछ देखने का मौका मिलना चाहिये मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

ये नेताओं की बैठक में बात हो जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अरे सुन तो लें मान्यवर, अभी पूरी बात नहीं हो पायी। उत्तरांचल में पौने दो लाख है। बिहार में 1 लाख 45 हजार अभी चार दिन पहले बढ़ा है। मेरा अनुरोध है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

क्या ? वेतन।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ये समझ रहे हैं सब। ये सब समझ रहे हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

उनकी सदस्य संख्या कितनी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है हम बिहार की बात कर रहे हैं मान्यवर, बिहार आज भी हमसे बीमारू राज्य है। मान्यवर, हमने एक सैद्धान्तिक बात कही है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें नेताओं की बैठक में बात हो जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

खन्ना जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर बहुत से लोगों की सहमति हो सकती है, लेकिन आप का खर्च ही कितना है ?

श्री अध्यक्ष-

वह अपने लिये कहां कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो किसके लिये कर रहे हैं, उसका नाम ही बता दें। जिसकी वजह से ये बढ़वाना चाहते हैं, उसका नाम बता दें। पूरा सदन मिलकर खर्च उठा लेगा। (सदन में हंसी)

*श्री प्रदीप माथुर-

धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं इनको बधाई देता हूं इन्वेस्टमेन्ट कान्क्लेव के लिये आगरा सम्मिट के लिये और उन्होंने सही कहा कि माहौल बना रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कानून-व्यवस्था की जब बात आयेगी ऊपर तो सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, नीचे जायेंगे तो नीचे वाकई में अच्छा नहीं है। वहां पर आपको आवश्यकता है दरोगा और सिपाही स्तर पर बदलाव करने की। बड़े जबरदस्त तरीके से उन लोगों ने ही सब कुछ बिगाड़ रखा है। दूसरी बात यह है कि अधिकारियों में सामंजस्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आप लोग घोषणा करते हैं, जो आप पैसा देते हैं, वह पैसा बजट में खर्च भी नहीं हो पाता। मान्यवर, आपसी तालमेल का अभाव है इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। आप इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत सारी रूग्ण और सिक इण्डस्ट्री हैं उनके रिहेब्लिटेशन का प्लान बनवाये जो कि बहुत इम्पारटेंट है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में यू0पी0एस0आई0डी0, यू0पी0एफ0सी, पिकअप जैसे वित्तीय संस्थान हैं, इनको पुर्नगठित किये जाने की आवश्यकता है। यह कोई काम नहीं करते हैं केवल वसूली का काम करते हैं और निगोशियेसन का काम करते हैं। मान्यवर, नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की बात उठी है। मान्यवर, चाहे गंगा नदी हो यमुना नदी हो घाघरा हो आमी नदी हो या जितनी नदियां हैं सबके प्रति लोगों की गहरी आस्था है। लेकिन उनमें प्रदूषित पानी बहता है। आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनकंट्रोल्ड है इस पर गौर करने की जरूरत है आपको। मान्यवर, आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शहरों में सब अरब ज्यादा बढ़ रहे हैं जो गांवों से पलायन हो रहा है या दूसरी जगहों से आ रहे हैं वह शहरों में अनअथराइज्ड कालोनी बनाकर रहे हैं। इसमें आपको कोई नीति बनानी पड़ेगी। जैसे पंजाब में है गरीबों को बसाने के लिये बाकायदा बजट में एलोकेशन होता है उसी तर्ज पर आपको भी बजट में एलोकेशन करना पड़ेगा। मान्यवर, आपने पर्यटन विभाग के लिये इसमें 64 करोड़ रु0 का प्राविधान किया है आप इस क्षेत्र के विकास के लिये कोई नीति बनायें और इस बजट धनराशि को बढ़ाये। मान्यवर, पूरे प्रदेश में संस्कृति की पहचान के रूप में हैरिटेज बने हुए हैं, जो हमारी विरासत है। उसको विकसित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, आपके संस्कृति विभाग का पुरसाहाल है उस पर गौर करने की जरूरत है। मान्यवर, पर्यटन और संस्कृति विभाग का आपसी तालमेल अच्छा होना चाहिए यह जरूरी है। इससे प्रदेश की इमेज भी अच्छी होगी। मान्यवर, आपने पूर्वांचल के विकास की बात कही, आपको पश्चिमांचल निधि की भी स्थापना करनी चाहिए। मेजों की थपथपाहट। चूंकि आपको पश्चिम के क्षेत्रों से ही सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है और वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट भी है और उसकी गुंजाइश भी है, लेकिन सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हम चाहेंगे कि वहां के विकास के लिये आप कोई प्लान बनायें और सब चीजों का वहां पर विकास हो। मान्यवर, जो हमारे जिलों के हेड क्वार्टर हैं, वहां सड़कों की हालत बड़ी खराब है। उन सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया जाय। बिना किसी भेदभाव के यदि आप जिला मुख्यालयों के हेड-क्वार्टनों के विकास पर ध्यान देंगे तो उससे आपकी इमेज का फार्मेशन होगा। मान्यवर, आपने लोहिया ग्राम और जनेश्वर मिश्र योजना में सड़कों के निर्माण के लिये 18 लाख रुपये का प्राविधान किया है इतनी धनराशि में तो गांव की तीन सौ मीटर की सड़क भी नहीं बन पाती है। तो मेरा अनुरोध है कि इस धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाय। मान्यवर, जिला योजना के लिये जिलों में पैसा नहीं पहुंचता है, मान्यवर, आपके मंत्री जिलों में बैठक करते हैं, लेकिन जब बैठक में विचार होता है तो किसी योजना के लिये उसमें पैसा नहीं होता है। तो मेरा अनुरोध है कि उसका प्राविधान बजट में होना चाहिए। मान्यवर, यह बहुत बड़ा बजट है लेकिन इसमें विधायकों के लिये उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिये विधायक निधि को बढ़ाने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। बकौल माननीय विपक्ष के नेता के इसमें विधायकों के लिये झुनझुना

है। मान्यवर, मेरा कहना है कि जो विधायक की सेलरी है उनका डी0ए0, टी0ए0 है वह चीफ सेक्रेटरी से एक रुपया ज्यादा होना चाहिए। मान्यवर, रेलवे का किराया चौबीस प्रतिशत तक बढ़ गया है तो उस सीमा तक हमारे रेल कूपन भी बढ़ाये जाने चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी आपके पिताजी बहुत सहृदय हैं और आप भी सहृदय हैं आप हम सब की बात मानते हैं माननीय श्री शिवपाल सिंह जी भी बैठे हुए हैं, हम हर विधायक को अपने क्षेत्र में सात-सात किलोमीटर बनवाने के लिये अनुदान देने की घोषणा करें। इसी तरीके से हमें अपने क्षेत्र में पांच-पांच गांव विद्युतीकरण के लिये देने की घोषणा करें। मान्यवर, भूतपूर्व विधायकों की पेंशन बहुत कम है वह बढ़ाई जानी चाहिए। मान्यवर, आप समग्र विकास की बात करते हैं यह अच्छी बात है इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमने जो मांगें रखी हैं उसको अमलीजामा पहनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

एक दो बात अपने क्षेत्र के बारे में कहा जाता है, मुख्य मंत्री जी को याद दिलाया जाता है यह तो पूरा दस्तावेज ही ले आते हैं आप लोग।

*श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को देख रहा हूं कि पूरे आत्मविश्वास के साथ और बड़े हंसमुख चेहरे से प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने जो अपना भाषण दिया एक दफा तो ऐसा मालूम पड़ा कि पूरे सदन को मंत्रमुग्ध कर दिया और ऐसा प्रतीत होता था कि पूरे प्रदेश में कोई समस्या नाम की चीज रही ही नहीं, फिर मैं कान फड़फड़ाकर उठा, अरे यह क्या हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो कहीं नाम ही नहीं। न अलीगढ़, न कासगंज, न मथुरा। मैंने कई बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गन्ना के भुगतान, किसानों के सम्बन्ध में समस्या, बिजली की अव्यवस्था, कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में कई बार अवगत कराया उसकी भी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथ ही साथ बजट के सम्बन्ध में हमारे कई विद्वान साथियों ने अपने-अपने हिसाब से तर्क दिये यह बहुत विद्वान लोग हैं यह एक-एक सप्ताह लाइब्रेरी में पढ़कर तैयारी करके आते हैं मैं तो कोई तैयारी करके नहीं आता। आपने जो भी योजना बन्द की है उसे बन्द करने का कारण तो आप जानते होंगे अच्छाई भलाई क्योंकि आप पूरे प्रदेश को देख रहे हैं लेकिन जो बजट में आपने उन योजनाओं को खत्म करके व्यवस्था की है सड़क, पानी, बिजली आदि चीजों के लिये वह सराहनीय है। उसके लिये हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने और भी कई काम किये हैं जैसे एफीडेविट में बच्चे मारे-मारे फिरते थे वह आपने मुक्त करा दिया। लेकिन इनसे काम बन नहीं रहा इनसे कोई काम नहीं बन रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये आपने तमाम योजनायें दे दी लेकिन पश्चिम के बारे में आपने एक नहीं कहा। आपने घोषणा की कि 660 बिजली घर अलीगढ़ में बनेगा, आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की। मैंने एक बात कही थी इस बजट भाषण में कि पूरे प्रदेश में इन्टर पास इतने बच्चे हो गये कि उनकी बी0ए0 और बी0एस0सी0 में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है जब तक आप सायंकालीन क्लास नहीं चलायेंगे या डिग्री कालेज के लिये नई स्वीकृति नहीं देंगे इसकी भी घोषणा आज आप करेंगे। अभी खन्ना जी ने बहुत अच्छी बात कही पूरे प्रदेशों में आप देखिए क्या हाल है बिहार में उत्तराखण्ड में जब हमारे साथी विधायक मिलते हैं तो हम लोगों का उपहास बनाते हैं वह लोग कहते हैं वैसे तो तुम बहुत बड़े प्रदेश के एम0एल0ए0 बनकर आये हो 4-4 लाख वोटों पे हम 80-80 हजार, 90-90 हजार, 1-1 लाख

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वोटों पे आये हैं और हमारे वेतन भत्ते इतने और हमको विधायक निधि इतनी मिलती है। मेरा आपसे सुझाव है यहां पर विधायक निधि से यह सब बैठे हैं इंजीनियर वह कौन है पहले वाले हैं बैठे हैं, यह जो डेढ़ करोड़ रुपया है सी0सी0 रोड इससे केवल और केवल डेढ़ कि0मी0 ही बनती है या तो आप इस विधायक निधि के कलंक से हम लोगों को मुक्त करा दें या फिर इसको बढ़ा दें। यही तो हम चाहते हैं सब विधायकों की राय यह है कि इससे खामखाह बदनामी होती है इसको खत्म करा दें। आपने नल दिये आपके जनेश्वर मिश्र में आपका पत्थर लगता है, लोहिया में आपका पत्थर लगता है लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है आपने जितनी योजना गिनाई उससे तो मालूम पड़ता है कि बस विकास हो ही गया प्रदेश का लेकिन जब हम उधर देखते हैं अलीगढ़ से कानपुर जब आप आते ही माननीय मंत्री जी बैठे हैं, 2-3 साल से सड़क की देन तो इनकी ही रही कि 4-5 महीने में खत्म हो गयी वह लेकिन उसके भुक्तभोगी हम आज तक बैठे पड़े हैं एक सड़क पर भी उधर काम नहीं हो रहा है। कानपुर से लेकर अलीगढ़ तक हमने रास्ता बन्द कर दिया तो आप चाहते हैं हम इटावा होकर जा रहे हैं आजकल आपकी कुछ सोची समझी रणनीति होगी। अलीगढ़-मथुरा सब सड़कें बुरी तरह ध्वस्त हुयी पड़ी हैं।

(बीच में डा0 मो0 अय्यूब सहित कई माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये अनुरोध किये जाने पर-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब डा0 साहब क्या पूछोगे, आप बैठ जाइये, अब किसी को कोई अुनमति नहीं है, अब बहुत हो गया। आप लोगों ने सब अपने भाषण में कह दिया, अब क्या पूछोगे। इस तरह भाषण की कोई परम्परा नहीं है।

श्री दलवीर सिंह-

हाटा और छाता शुगर मिल की आपने दो बार सड़क बनवाई, उसके अलावा आपने इस शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने को कहा लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। आगरा से लेकर गाजियाबाद तक आलू का इतना बड़ा काम होता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता लोकदल, यह परम्परा नहीं है, अब एक बात के लिये आप कितना भाषण देंगे। अब हम आपका लिखने ही नहीं देंगे। आप कितना भाषण देंगें। अब हम आपका लिखने ही नहीं देंगे। अब आप अपनी बात बंद करिये। यह तरीका नहीं है, यह परम्परा नहीं है। परम्परा यह है कि एक-दो बात मेम्बर पूछ लेता है। अब तो आप पूरा भाषण कर रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह-

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिये आपने घोषणा की, लेकिन कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नाम की चीज नहीं बनी। मैं खनन के सम्बन्ध में कई बार कह चुका हूं। रिकार्ड तोड़ खनन हो रहा है। एन0एच0-91 बन रहा है, सब मिट्टी झाड़ के वहीं पर पड़ रही है। एक रेलवे ट्रैक बन रहा है, मेरे यहां तो आस-पास की सब सड़कें ध्वस्त हो गयीं, एक भी सड़क शेष नहीं बची हैं। बड़े-बड़े हैवी डम्पर और पूरे प्रदेश भर के खनन माफिया हमारे यहां पहुंच गये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक पूछे जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठिये, अब कोई चीज लिखी नहीं जायेगी।

(नियम-51 की सूचनायें पुकारे जाने पर)

[5.06 बजे] अनुदानवार बजट साहित्य के उपलब्ध न होने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, कल विभागीय बजट है। लेकिन बजट का कोई साहित्य हम लोगों को नहीं मिला है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, कल से मदवार बजट प्रस्तुत किये जायेंगे लेकिन मान्यवर, कोई भी बजट सामग्री हम लोगों को अभी तक नहीं मिली है। यही चीज महाना जी भी कह रहे हैं और यही सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता है। इस पर मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

कल ही इसके बारे में हमारे विभाग ने इनको बताया था कि विभागीय सामग्री दे दी जाय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, परम्परा यह है कि जिस विभाग का बजट जिस दिन होगा, उसकी सामग्री 24 घण्टे पहले माननीय सदस्यों के पिजन होल में रख दी जायेगी। कल हमारे विभाग ने आपके विभाग को सूचित किया कि अभी तक सामग्री हमें नहीं मिली है जिसे हम पिजन होल में रखवाये। आपसे आग्रह है कि इस परम्परा को आप तुड़वाइये और जरा कहिये कि 24 घन्टे पहले पिजन होल में सामग्री रखवा दी जाय। विभाग के लोगों को आप निर्देशित करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस विषय के लिये इंगित किया लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय मंत्रियों का सहयोग और सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं इसलिये वह निरूत्तर हैं और बैठे हुये हैं और सिर हिलाकर अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। मान्यवर, इस व्यवस्था को आप ही सुनिश्चित करायें।

श्री अध्यक्ष-

कल हमारे विभाग ने उन विभागों को कहा था, अभी भी भिजवा दें। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, पंचायती राज, प्राविधिक शिक्षा, उद्योग विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट 27-06-2014 को पास होना है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, आप पहले भी इस पीठ पर रहे हैं और आज भी हैं और बराबर इस तरह की बातें आती रही हैं और बार-बार आपके निर्देश आते हैं इसलिए मान्यवर, एक-आध अधिकारी को आप यहां से दण्डित कर दीजिए, सब ठीक हो जायेगा। अभी ससपेंशन का आदेश आप दीजिए, सब ठीक हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

कल हमारे विभाग ने इन लोगों को सूचित कर दिया लेकिन बजट साहित्य अभी तक नहीं दिया। कल इन अधिकारियों को तलब किया जायं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, मान्यवर, तब तो वह आपको मना लेंगे, अधिकारियों में बड़ी खूबी होती है। कल के बजट की सामग्री अभी तक नहीं आई है, जिस-जिस विभाग की बजट सामग्री नहीं आई है उस विभाग के अधिकारियों के निलम्बन के लिए आप कह दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, संसदीय कार्यमंत्री जी ने जिस मजबूती के साथ प्रस्ताव रखा, उस पर अमल किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा निरंकुशता और अराजकताशाही बरती जा रही है, जिससे मा0 सदस्यों को समय-समय पर हमेशा आपसे निवेदन करना पड़ता है क्योंकि जिन तमाम मा0 सदस्यों को कटौती प्रस्ताव रखना है या अपनी बात रखनी है वह किस आधार पर कटौती प्रस्ताव रखेंगे और किस आधार पर अपनी बात रखेंगे। इसलिये मान्यवर, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी के प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाकर उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर दण्ड दिलाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके कार्रवाई करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जिस विभाग की बजट सामग्री आ गई है केवल उसी विभाग का बजट पास करायें शेष विभाग को स्थगित करा दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

एक चीज और मान्यवर, इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि जो विभाग अपनी बजट सामग्री नहीं दे रहा है उसके विभाग के बजट को स्थगित कराने का भी निर्देश दें। जब तक आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस मनमानेपन पर अंकुश नहीं लग पायेगा। इसलिए मान्यवर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको गम्भीरतापूर्वक आप लें और इसको अमलीजामा पहनायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम कल उनको तलब करते हैं और आवश्यकता हुई तो सदन में खड़ा करेंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था की बात है, जब मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने इतनी गम्भीर बात कह दी, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने कह दी और अन्य मा0 सदस्यों ने कह दी तो एक व्यवस्था आपकी पीठ से हो जाएं कि जो लिट्रेचर अब तक पिजनहोल में आ गया है या उपलब्ध करा दिया गया है, उसका बजट प्रस्तुत हो और जिस विभाग का बजट नहीं आया है उस विभाग का बजट कल स्थगित हो और इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उसे कठोरतम दण्ड दिया जायेगा यह व्यवस्था आपकी ओर से आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

अभी हम दिखवाते हैं क्या पिजनहोल में कुछ सामग्री रखी है ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पिजनहोल में केवल कृषि विभाग की बजट सामग्री है।

श्री अध्यक्ष-

यदि कृषि विभाग का आ गया है तो कृषि विभाग का ही बजट रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, शेष विभागों के बजट जिसकी सामग्री नहीं आई है उसको स्थगित करा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्यमंत्री जी तय कर लेंगे कि किस विभाग का बजट रखा जाय।

श्री अध्यक्ष-

कौन सा विषय आयेगा और कौन सा नहीं आयेगा यह मा0 संसदीय कार्यमंत्री और मा0 नेता विरोधी दल का विषय है आप तय कर लेंगे कि कौन सा विषय आयेगा और कौन सा नहीं आयेगा, अगर आप चाहें तो उसे स्थगित कर दें। जिन लोगों ने बजट सामग्री नहीं दी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सबकी सहमति है कि आप व्यवस्था दे दें कि जिन विभागों का लिट्रेचर नहीं है उनका स्थगित रहेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सभी मा0 सदस्यों की ओर से मैंने निवेदन कर लिया और संसदीय कार्यमंत्री जी ने उस पर कठोर कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया। मा0 मंत्री श्री अम्बिका चौधरी जी अपनी सहमति सत्तापक्ष की ओर से दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि आपको भी कुछ कठोर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप कठोर निर्णय नहीं लेंगे, इस रवैये पर अंकुश नहीं लग पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। अब मैं नियम-51 की सूचनाएं ले रहा हूं।

[5.15 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-06-2014 को नियम-51 के कुल 76 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में अवैध पार्किंग स्थलों द्वारा अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री उमाशंकर की जनपद बलिया के रसड़ा अन्तर्गत राजकीय बालिका विद्यालय के भवन को बनाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर अन्तर्गत ग्राम राहाटीकर एवं पूरे नौती

इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के सूरजपुर से मौल्नापुर मिसरौली तक जर्जर रिंग बांध की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर से तहसील स्वार मार्ग पर सैजनी नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य की जनपद बदायूं के उवसा, उसैहत, दातागंज आदि क्षेत्रों में ई0ओ0 की मिलीभगत से दबंगों द्वारा की जा रही वसूली के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री अलगू प्रसाद चौहान की जनपद संतकबीर नगर के अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड प्रथम द्वारा काश्तकारों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद-मथुरा के कस्बा-बाजना स्थित पायल थिएटर की अपील पर मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन न कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद-कासगंज के अमापुर क्षेत्रान्तर्गत सहावर में तहसील परिसर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचना पर शासन का ध्यानाकर्षण किया गया :-

ग्यारहवीं सूचना श्री मदन चौहान की गढ़मुक्तेश्वर बृजघाट में स्नान घाट पर सुरक्षा बैरिकेटिंग की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद खीरी के अन्तर्गत बाढ़ एवं कटान क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद खीरी के अनेक विकास खण्डों में क्षेत्र पंचायत निधि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में खराब विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में है तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद आगरा के डा0 जेड0एच0 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एवं मैनेजमेंट स्कूल, सतौली (एत्मादपुर) के अनुसूचित जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं:-

क्र0सं0	नाम
1	श्री सुल्तान बेग
2	श्री राधे लाल रावत
3	श्री धर्मपाल सिंह
4	श्री सतीश महाना
5	डा0 अरूण कुमार
6	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
7	श्री रवीन्द्र जायसवाल
8	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)
9	श्री लोकेन्द्र सिंह
10	श्री विक्रम सिंह

क्र0सं0	नाम
11	श्री संत प्रसाद
12	श्री गोरख पासवान
13	श्री मो0 गाजी
14	श्री भीम प्रसाद सोनकर
15	श्री राधेश्याम जायसवाल
16	श्री रामवीर उपाध्याय
17	श्री संजय प्रताप जायसवाल
18	श्री सन्त राम कुशवाहा
19	श्री गुटियारी लाल दुबेश
20	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
21	श्री मनीष असीजा
22	श्री सुरेश बंसल
23	श्री पंकज कुमार मलिक
24	श्री रोशन लाल वर्मा
25	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज
26	श्री बंशी सिंह पहाड़िया
27	श्री सुधाकर सिंह
28	श्री जाकिर अली
29	श्री अजय कुमार लल्लू
30	श्री अनीसुर्रहमान
31	श्री दलजीत सिंह
32	श्री प्रभूदयाल बाल्मिकी
33	श्री अमर पाल शर्मा
34	श्री मो0 अलीम खां
35	श्री बृजेश कुमार
36	श्री अनिल कुमार
37	श्री दिलनवाज खान
38	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
39	श्री प्रदीप माथुर

क्र0सं0	नाम
40	श्री रामहेत भारती
41	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
42	श्री दीपक पटेल
43	श्री भगवती प्रसाद
44	श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट'
45	श्री वीरपाल राठी
46	श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन
47	श्री अली युसुफ अली
48	श्री मो0 रिज़वान
49	श्री हरिविन्दर कुमार उर्फ रोमी साहनी
50	श्री जगपाल सिंह
51	डा0 धर्म सिंह सैनी
52	श्री इन्द्रपाल सिंह
53	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप
54	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल
55	श्री रविदास मेहरोत्रा
56	श्री सुशील सिंह
57	श्री जगन प्रसाद गर्ग
58	श्री गेंदालाल चौधरी
59	श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू
60	श्री सुदेश शर्मा
61	श्री भगवान सिंह कुशवाहा

जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर की अपेक्षा एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-24 को स्थगित किया जाता है।

जनपद-बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारियों द्वारा आदेश के बावजूद श्री राम प्रसाद त्यागी का भुगतान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री गया चरन दिनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसको भी स्थगित किया जाता है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मद संख्या-25 पर आज वक्तव्य लगा था लेकिन उसका वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, इसका वक्तव्य नहीं आ पाया है इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया है।

जनपद-बुलन्दशहर के ग्राम दौलतपुर कला में अवैध दुकानें बनाकर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री दिलनवाज खां हैं ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आगे बढ़िये।

जनपद-सहारनपुर के ग्राम शुक्रताल में सड़क के किनारे नाली व सड़क के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, जनपद-सहारनपुर में नकुड़ विधान सभा क्षेत्र....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है।)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना।

[के ग्राम-शुक्रताल, ब्लाक-नकुड़, जनपद-सहारनपुर में सड़क के किनारे नाली न होने के कारण सड़क जल्दी-जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे पी0डब्लू0डी0 विभाग को काफी हानि हो रही है

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा ग्राम वासियों एवं राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों ने, विभागीय अधिकारी एवं उच्चाधिकारियों को, इस विषय पर अवगत करा चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण उनमें सरकार के प्रति काफी अक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर ग्राम-शुक्रताल में सड़क के किनारे नाली निर्माण कराने की अपेक्षित कार्रवाई की मांग करता हूं।

वक्तव्य-

जनपद सहारनपुर में नकुड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नकुड़ नसरूल्लागढ़ मार्ग के कि0मी0 3 से शुक्रताल तक 0.900 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग के पुनः निर्माण एवं नाली निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-259/26-ब0प्र0-2014-9 एस0सी0पी0 (पु0न0)/2014, दिनांक 04-03-2014 द्वारा रु0 14.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 4.76 लाख का आवंटन किया गया है, जिसके सापेक्ष मार्ग की लम्बाई का 34 प्रतिशत वर्टिकली कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं रु0 4.76 लाख व्यय किया जा चुका है। नाली निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। कार्य प्रगति में है।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व मानचित्र की स्वीकृति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[''लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यूनिट मानचित्रों की स्वीकृति न होने से शहर में आवास की गंभीर समस्या हो रही है। लखनऊ जोकि प्रदेश की राजधानी है यहां पर आवास की अत्यधिक कमी है, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा छोटे भू-खण्डों पर यूनिट के मानचित्र स्वीकृत न किये जाने के कारण आवास की समस्या और भी अधिक गंभीर हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा छोटे भू-खण्डों पर यूनिट अनुमन्य नहीं की जा रही है, जबकि प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में यूनिट मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य प्राधिकरणों की भांति यूनिट निर्माण की अनुमन्यतायें के

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव दिनांक 06-01-2012 के अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया गया था। परन्तु शासन द्वारा कोई भी अनुमोदन न किये जाने के कारण यूनिट निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण स्तर से प्रदान नहीं कि जा रही है। यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा छोटे भू-खण्डों पर यूनिट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो प्राधिकरण को अधिक राजस्व का लाभ मिलेगा तथा जनता को आवास आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। तथा लखनऊ में हो रहे निर्माण नियमों के अन्तर्गत होंगे।

यह अविलम्बनीय और अत्यधिक लोक महत्व का विषय है, जिस पर वक्तव्य देने के साथ-साथ मांग करता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यूनिट मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की जाये''।

2-मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-3830/8-3-11-181 विविध/08 दिनांक 11-08-2011 एवं सपठित शासनादेश संख्या-4384/8-3-11-181 विविधि/08 दिनांक 27-09-2011 के माध्यम से शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 में प्रस्तावित संशोधनों पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 में प्रस्तावित संशोधनों पर प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से इन्हें अंगीकार किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत अपेक्षित परिष्कारों को बोर्ड की संस्तुति सहित प्राधिकरण द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 में आवश्यक परिष्कार/संशोधन के उक्त प्रस्ताव में

भू-खण्डीय विकास के अन्तर्गत 2000 वर्ग मी0 तक भू-खण्ड की अनुमन्यता/यूनिट्स (फ्लैटेड डेवलपमेन्ट) की अनुमन्यता हेतु परिष्कार का प्रस्ताव भी अन्य परिष्कारों सहित प्रस्तावित किया गया है, जिस पर विचार कर समुचित निर्णय लिया जाना है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में परिष्कार से सम्बन्धित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तत्क्रम में निर्णयोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद-बिजनौर के नहटौर और हल्दौर के सरकारी अस्पताल में पर्याप्त डाक्टर दवा तथा पैथोलोजी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में श्री ओम कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-29 को स्थगित किया जाता है।

जनपद-सहारनपुर के ग्राम सलेमपुर के ग्राम पीकी तथा राजवाहे की पटरी पर सड़क व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जनपद-सहारनपुर में ग्राम-सलेमपुर भूखड़ी से ग्राम-पीकी तक राजवाहे की पटरी पर सड़क एवं राजवाहे पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23-06-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना निम्नवत् हैः-

''विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक-पवारका, जिला-सहारनपुर में ग्राम-सलेमपुर भूखड़ी से ग्राम-पीकी तक राजवाहे की पटरी पर सड़क एवं राजवाहे पर पुलिया न होने के कारण ग्राम-वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों द्वारा कई बार वहां के अधिकारियों से सड़क तथा पुलिया बनाये जाने का अनुरोध भी किया गया, परन्तु ग्राम-सलेमपुर भूखड़ी से ग्राम-पीकी तक राजवाहे की पटरी पर सड़क एवं राजवाहे पर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। सड़क एवं पुलिया का निर्माण न होने के कारण सरकार के प्रति काफी आक्रेश है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से ग्राम-सलेमपुर भूखड़ी से ग्राम-पीकी तक राजवाहे की पटरी पर सड़क एवं राजवाहे पर पुलिया का निर्माण कराने की अपेक्षित कार्रवाई की मांग करता हूं।'']

केवल वक्तव्यः

सलेमपुर भूखड़ी ग्राम से पीकी तक जाने हेतु एक रजवाहा पड़ता है, जिस पर बनी पुलिया संतोषजनक स्थिति में है। रजवाहा पार करने के बाद पीकी तक रजवाहे की कच्ची पटरी हैं पीकी तक जाने हेतु ढमोला नदी से गुजरना पड़ता है, जिस पर कोई सेतु नहीं है।

लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत रु0 325.00 लाख का आगणन गठन की प्रक्रिया में है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद-चित्रकूट के ग्राम बरेठी में एक भी ट्यूबवेल न होने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री योगेन्द्र पाल सिंह हैं ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह भी नहीं हैं।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

जो सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं उनकी सूचना पर आया हुआ वक्तव्य कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा।

जनपद-शामली में गिरते जल स्तर एवं नदियों के प्रदूषित पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य.... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री पंकज मलिक जी हैं ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पंकज मलिक जी भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न में मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,

दिनांक 26 जून, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 157 विधान सभा (280)-29-10-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।